R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.oksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 20
16 से 31 जुलाई 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

लोकतंत्र के मंदिर में न कायदा, न कानून

सत्तापक्ष और विपक्ष के हंगामे में जनता के करोड़ों रुपए स्वाहा

15वीं विधानसभा में 128 दिन के सत्र में 128 घंटे ही चला सदन

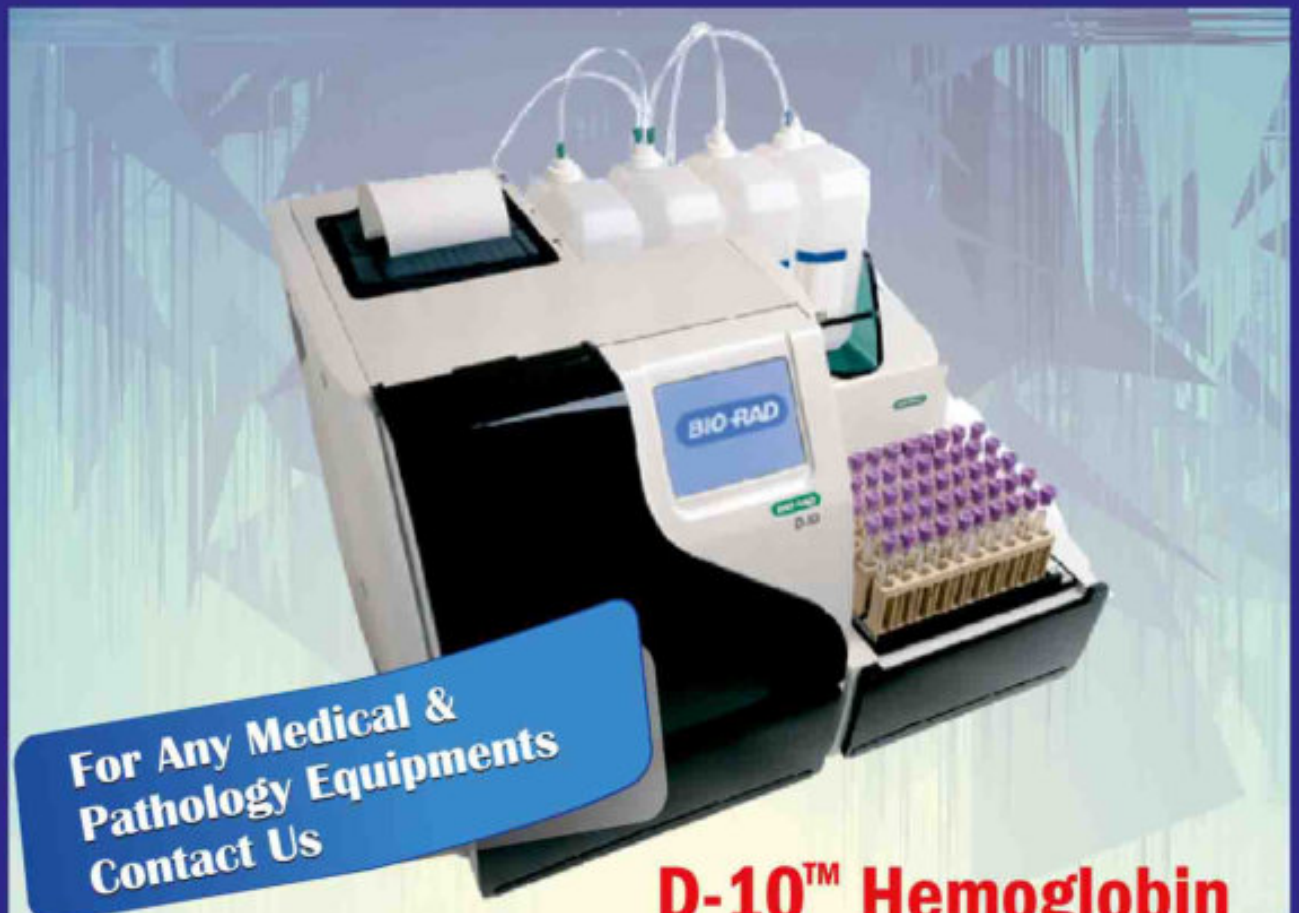

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

मास्टर प्लान
9 | आपत्तियों का निराकरण...

आखिरकार करीब 17 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान को लागू करने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस मास्टर प्लान के लिए लोगों ने जो आपत्तियां लगाई हैं, सरकार उन्हें फेस-टू-फेस सुनने की बजाय ऑनलाइन...

राजपथ
10-11 | युवाओं पर सत्ता का दांव

भाजपा और कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए दोनों पार्टियों के युवा नेताओं के चेहरे पर चमक आ गई है। चुनावी साल में भाजयुमो और युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मैदानी मोर्चों पर अपना दम दिखा रहे हैं।

घपला
15 | आदिवासियों के नाम पर...

मप्र में आदिवासियों के नाम पर जमीनों को हड़पने का बड़ा खेल खेला जा रहा है। आदिवासियों की जमीन बेचने में जबलपुर जिले में हुए खेल में चार अफसरों पर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इससे कहीं बड़ा खेल कटनी जिले में हुआ है।

तैयारी
18 | सरकार का चुनावी निर्माण पर फोकस

मप्र में चुनावी साल होने के कारण सरकार का फोकस सबसे अधिक उन योजनाओं और कार्यों पर है, जिसका जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने सड़कों जैसे चुनावी निर्माण के कार्यों पर सबसे अधिक फोकस किया है। इन योजनाओं के लिए फंड की कमी न हो इसके...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

जिस राज्य में मुख्यमंत्री हर मंच से यह कहने से चूकते नहीं हैं कि मप्र मेरा मंदिर है और जनता इसकी भगवान और मैं जनता का सेवक। उस प्रदेश में लोकतंत्र के मंदिर में भगवान की किस कदर उपेक्षा की जाती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में हुए कुल 15 सत्र में 128 बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन उनमें से सदन केवल 128 घंटे ही चल पाया। उस दौरान भी जनहित के मुद्दों की बजाय हंगामे ही होते रहे।

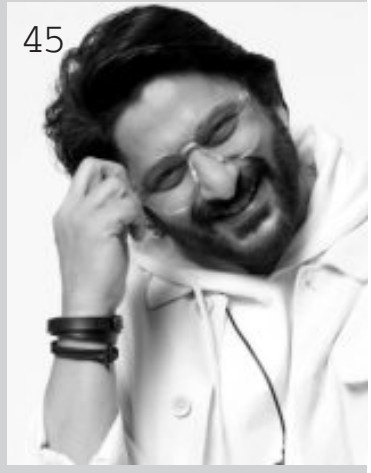

राजनीति
30-31 | आसान नहीं विपक्षी...

विपक्षी दल अपने साथी दल के पर कतर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक जीतने के बाद वह अपने को 2024 का विजेता मानकर चल रही है। वह चाहती है कि बाकी दल उसकी पालकी के कहार बनें। इस चक्कर में कम से कम चार ऐसे दल...

महाराष्ट्र
34 | गुरु दक्षिणा में दिया धोखा!

अजित पवार ने अपने चाचा से सियासत की एबीसीडी सीखी है, अपने गुरु और चाचा शरद पवार को धोखा देकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि अब वो सियासत का महत्वपूर्ण सेमेस्टर पास कर चुके हैं। अजित पवार ने साबित कर दिया कि राजनीति में गुरु दक्षिणा में धोखा भी दिया जाता है।

बिहार
37 | अगड़ी जातियों की अहमियत

बिहार की राजनीति यही कोई तीन दशक से गैर सवर्ण जातियों के इर्द-गिर्द घूमती आई है। खास तौर पर पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व इतना बढ़ा कि इस तबके से आने वाले लालू यादव-राबड़ी देवी-नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते आए हैं। हालांकि एक दौर वह भी रहा...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

खुले पड़े बोरवेल...दम तोड़ते मासूम

किसी शायर ने लिखा है....

किसे खबर थी कि ये वाकिया भी होना था
कि खेल-खेल में इक हादसा भी होना था

उपरोक्त पंक्तियों की तरह मप्र सहित देशभर में खेल-खेल में ऐसे हादसे हो रहे हैं, जिससे मासूमों का जीवन उजड़ रहा है। ये हादसे खुले पड़े बोरवेल के कारण हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, जिला प्रशासन की बार-बार की हिदायत के बाद भी बोरवेल खुले रखे जा रहे हैं। इस कारण कोई न कोई मासूम बच्चा इन बोरवेल में गिर रहा है और उसे निकालने के लिए जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रोबोटिक टीम रात-दिन लगी रहती है। इनमें से कोई भाग्यवान बच्चा ही बच पाता है। अगर देखा जाए तो मप्र में तकरीबन हर चौथे-पांचवे महीने कोई न कोई बच्चा बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा रहा है। खुले बोरवेल रखने वालों पर कई कार्रवाईयां हो चुकी हैं और उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी है। उसके बावजूद हर साल देशभर से बोरवेल में बच्चों के गिरने के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकांश की बोरवेल के भीतर ही दम घुटकर मौत हो जाती है। सृष्टि हो या तन्मय, इन बच्चों की मौत प्रशासन से लेकर परिजनों तक पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि आखिर बार-बार होते ऐसे हादसों के बावजूद देश में कब तक बोरवेल या ट्यूबवेल के गड्ढे खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तब मासूम जानें इनमें गिरकर दम तोड़ती रहेंगी। आखिर कब तक मासूमों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? खेत में खुले पड़े बोरवेल में मौत के मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद बोरवेल में गिरने से मौत के मामले कम नहीं हो सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार साल में देशभर में 281 लोगों की मौत बोरवेल में गिरकर हुई है। जहां कही भी बोरवेल में कोई बच्चा फंसता है, सेना से लेकर एनडीआरएफ की टीमें तेजी दिखाते हुए रेस्क्यू में जुट जाती हैं। कई घंटों तक रेस्क्यू चलता है, कुछ एक बार तो सफलता मिल जाती है, लेकिन अधिकांश बार बच्चों की मौत के बाद रेस्क्यू विफल हो जाता है। जिस राज्य में बोरवेल में बच्चा गिरने का हादसा होता है, वहां हादसे के बाद प्रशासन जाग जाता है और बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आता। महीने-दो महीने में फिर किसी न किसी राज्य से बोरवेल में बच्चे गिरने की खबर सामने आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2010 को बोरवेल को लेकर तमाम दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि देशभर में स्थिति जस के तस है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई केजी बालकृष्णन की अगुवाई वाली बेंच ने एक याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने सरकारों से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा था। तब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि बोरवेल या नलकूप में बच्चे गिरकर फंस जाते हैं। ये खबरें अलग-अलग राज्यों से आ रही हैं। ऐसे में हमने स्वतः पहल की और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। इन सबके बावजूद बोरवेल बंद नहीं किए जा रहे हैं।

इस कारण खेल-खेल में कोई न कोई बच्चा इन बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा रहा है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 20, पृष्ठ-48, 16 से 31 जुलाई, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

तैयारी में जुटीं पार्टियां

मप्र में विधानसभा चुनाव को अब कम समय ही रह गया है, इसलिए पार्टियां तेजी से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपना बेस मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जन-जन की समस्याओं का समाधान करने की बात कह रही है।

● **महेंद्र तिवारी,** धार (म.प्र.)

सीएम राइज अच्छी पहल

प्रदेश की शिवराज सरकार ने आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार सीएम राइज स्कूल खोले हैं, उससे बच्चों में स्कूल जाने की ललक बढ़ेगी, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए और ऐसे कदम उठाने चाहिए।

● **नीतू सिंह,** जबलपुर (म.प्र.)

हर घर नल से जल

मप्र सरकार जल जीवन मिशन के कामों को लेकर चुनावी मोड पर है। सरकार ने इस योजना के लिए खजाना खोल दिया है। मप्र में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की गति के चलते बुरहानपुर के बाद अब निवाड़ी प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला है, जहां हर घर में नल के पानी का कनेक्शन है।

● **सुनील यादव,** इंदौर (म.प्र.)

कड़े नियम लागू करने चाहिए

मप्र की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा अग्निकांड ने जिस प्रकार सरकारी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत भी दे दी है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस प्रकार के हादसे पहले भी होते रहे हैं, जिससे सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले से सतर्क रहना चाहिए था। कोई कोचिंग संस्थान हो, कोई अस्पताल हो या फिर कोई रहवासी बिल्डिंग, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सरकार को इस विषय में सतर्क रहने की जरूरत है इसके साथ ही कड़े से कड़े नियम लाकर उन्हें लागू करवाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसे न हों।

● **हेमंत श्रीवास्तव,** भोपाल (म.प्र.)

राजनीति में उथल-पुथल

देश में मोदी सरकार के खिलाफ बड़े-बड़े विपक्षी दल एक हो गए हैं। विपक्षी गठबंधन से मीडिया में नेरेटिव जरूर बनता है, जमीन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मनभेद और मतभेद को भुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मंच से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है, लेकिन मन ही मन में सभी को प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। बाहर से सभी दल एक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को श्रेष्ठ बनने का लालच भी दिखाई पड़ता है। इस समय कई राज्यों की राजनीति में उथल-पुथल भी दिख रही है।

● **प्रियांशु त्रिपाठी,** सीहोर (म.प्र.)

मप्र बना विकसित राज्य

देश के हृदय स्थल मप्र ने पिछले डेढ़ दशक में विकास के नए आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मप्र की सुशासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मप्र बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। इस महती उपलब्धि में प्रदेश में जन-भागीदारी से विकास के मॉडल ने अहम भूमिका निभाई है। इससे प्रदेश की विकसित तस्वीर देशभर में छा गई है।

● **शंकर मिश्रा,** सागर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

नया मंच तैयार करेंगे चौधरी

अगले साल पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव। ऐसे में हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां हरियाणा में जजपा-भाजपा का गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का आने-जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। कुछ ऐसा ही इशारा किया है भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। दरअसल, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीरेंद्र सिंह बीते दिनों अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया है कि वह जींद में 2 अक्टूबर को होने वाली रैली में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंह ने भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को खूब खरी-खोटी भी सुनाई। कई मुद्दों को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार युवा अपनी जमीनों को बेचकर विदेश भाग रहे हैं। चाहे उन्हें गलत ढंग से विदेश जाने का मौका मिले वह चूक नहीं रहे हैं। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य की है जिसको लेकर बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है।

पायलट-गहलोत में सुलह की संभावना

कांग्रेस हाईकमान राजस्थान विधानसभा चुनावों का कैंपेन शुरू होने से पहले गहलोत-पायलट का झगड़ा सुलझाना चाहता है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान को यह फीडबैक मिलता रहा है कि पायलट खेमे को साथ लिए बिना सरकार के खिलाफ नाराजगी कम नहीं होगी। ऐसे में अब दोनों खेमों को साधकर चुनावी मैदान में जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पहला विकल्प पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाने के साथ विधानसभा चुनाव की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का है। इस फॉर्मूले पर पहले भी चर्चा हुई थी। इससे विरोधी खेमे को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा विकल्प पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष और उनके खेमे के विधायक को उपमुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन गहलोत खेमा इसका विरोध कर रहा है। इसके लिए कैबिनेट में फेरबदल करना होगा। प्रदेशाध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत खुद के खेमे के नेता की जगह पायलट का विरोध करते रहे हैं। 2020 में पायलट को प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पदों से बर्खास्त किया गया था। चुनावी साल में जाट वर्ग के नेता को अध्यक्ष पद से हटाने से एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी का खतरा भी है।

झारखंड कांग्रेस में होगा नेतृत्व परिवर्तन

झारखंड कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के नेता 2019 में लोकसभा चुनाव वाले नतीजे को उलटने की रणनीति बनाने में लगे हैं। तब 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें एनडीए ने जीत ली थीं और यूपीए को दो सीटें मिली थीं। इस बार कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक का प्रोग्राम झारखंड में करवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की भी खबरें आती रहती हैं। जिसके चलते नेतृत्व परिवर्तन के भी कयास लगने लगे हैं। पार्टी के कई नेता इसके लिए आए दिन दिल्ली में कैंप भी करते नजर आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बदलने की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। दरअसल कांग्रेस का एक गुट झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व को लेकर शुरुआती दिनों से ही लगातार पार्टी में आवाज मुखर करती रही है। पहले उन्हें पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह की पसंद बताया गया उसके बाद उनकी एनसीपी से आए नेता के रूप में निंदा की गई, मंत्री रामेश्वर उरांव ने तो इशारों-इशारों में कई बार नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं।

कौन बनेगा अगुआ ?

देश का सबसे बड़ा सूबा नियमित पुलिस महानिदेशक की बाट जोह रहा है। उप्र में पिछले नियमित पुलिस महानिदेशक जून 2021 में मुकुल गोयल बनाए गए थे। नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सहमति और केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग की स्वीकृति से करने का नियम है। शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी एक तो वरिष्ठता क्रम में ऊपर होने चाहिए, दूसरे उसकी नौकरी छह माह से अधिक शेष होनी चाहिए। मुकुल गोयल इन दोनों ही कसौटियों पर खरे थे। वे उप्र के पुलिस महानिदेशक बनाए जाने से पहले केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। केंद्र सरकार की भी उनकी नियुक्ति के पीछे अहम भूमिका थी। साफ सुथरी छवि के अलावा वे वैश्य वर्ग से थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पद से हटा दिया। दरअसल, उस समय के प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के खास माने जाते थे। पर, मुकुल गोयल उनकी जी हजूरी करने को तैयार नहीं थे।

हरियाणा कांग्रेस में कलह

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस के लिए हरियाणा के हालात भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। खबर है कि राज्य के नए प्रभारी दीपक बावरिया की पहली ही बैठक में नेताओं के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। एक ओर जहां प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रमुख कुमारी शैलजा बीच बैठक से ही बाहर चली गईं, वहीं रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं के गुट अपने-अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल कुछ समय पहले ही गुजरात कांग्रेस के नेता बावरिया को दिल्ली और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर में बैठक ली थी। उनके सामने ही मंच साझा कर रहे नेता एक-दूसरे की बातचीत में रोक-टोक करते नजर आए। उस दौरान बावरिया ने खुद नेताओं से एकजुटता पेश करने की अपील की। बैठक के दौरान हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान गुट, किरण चौधरी गुट, शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट ने अपने-अपने नेताओं के लिए जमकर नारेबाजी की।

विधायक और दलाल की पार्टनरशिप

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक विधायक और एक दलालनुमा व्यावसायी की पार्टनरशिप की चर्चा जोरों पर चल रही है। यह पार्टनरशिप है या कुछ और ये तो यही लोग जानें, लेकिन तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि महाकौशल क्षेत्र के एक जिले से आने वाले एक माननीय ने राजधानी के पास देश के एक बड़े व्यावसायिक घराने की 100 एकड़ जमीन खरीदी है। यह घराना इन दिनों संकटों के दौर से गुजर रहा है। इसलिए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जमीन औने-पौने दामों में खरीदी गई होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए राजधानी के इस दलाल ने विधायक जी को परमिशन तो दिलवाई ही है, साथ ही साथ भोपाल विकास प्राधिकरण के एक बड़े प्रोजेक्ट को भी वहां अनुमति दे दी गई है। वहां जानबूझकर बीडीए का प्रोजेक्ट लाया गया है, ताकि उक्त जमीन तक एक सरकारी सड़क बन सके। इससे उक्त जमीन सोने के भाव हो जाएगी। बताया जाता है कि उक्त दलाल विधायक जी के साथ इस जमीन में पार्टनर भी है। यहां बता दें कि उक्त दलाल पत्थर का व्यावसाय करते हैं। लेकिन वर्तमान में वे प्रशासनिक वीथिका के बड़े दलालों में गिने जाते हैं। इनकी प्रशासनिक मुखिया के साथ ही प्रदेश के अन्य अफसरों के साथ घनिष्ठता है, जिसका फायदा ये भरपूर उठाते हैं।

एक बंगला हो न्यारा

राजधानी में इस समय एक मंत्री का बंगला चर्चा का विषय बना हुआ है। कहने को तो साहब चटनी-चूरन वाले विभाग के मंत्री हैं, लेकिन मंत्रीजी के निर्मित हो रहे बंगले ने लोगों को सोच में डाल दिया है। लोग हिसाब-किताब में जुट गए हैं कि मंत्रीजी को कुबेर का ऐसा कैसा खजाना मिल गया है, जिससे वे राजधानी में करोड़ों का बंगला बनवा रहे हैं। एक तो मंत्रीजी राज्यमंत्री हैं, उस पर भी तथाकथित तौर पर छोटे विभाग के। लेकिन जानकारों का कहना है कि चटनी-चूरन वाला यह विभाग कमाई का बड़ा समुंदर है। दरअसल, विभाग में जो ठेकेदार काम करते हैं, वे नजराना, हर्जाना और खर्जाना भरपूर लुटाते हैं। इससे ही इनकी कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि अभी डेप्युटेशन पर आए एक साहब ने ठेकेदारों से जमकर नजराना लिया था। वहीं मंत्रीजी ने भी उनसे खूब हर्जाना वसूला। नजराना और हर्जाना देकर ठेकेदार काम में जुटे ही थे कि विभाग में नए पीएस आ गए हैं और उन्हें ये पता है कि पुराने अधिकारियों को नजराना, हर्जाना और खर्जाना देकर ये आगे बढ़े हैं। अब देखना यह है कि उनके द्वारा दिया हुआ नजराना, हर्जाना और खर्जाना काम आएगा या नहीं।

पत्नी वियोग से डिप्रेशन में साहब

मप्र में अक्सर अजब-गजब घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, मामला पुलिस विभाग का है। कुछ साल पहले तक विभाग में एक एडिशनल एसपी दंपत्ति खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे थे। यारबाज यह दंपत्ति खाने-पीने का काफी शौकीन था। अक्सर पीने-पिलाने की पार्टियां आयोजित होती थीं, जिसमें ये अपने दोस्तों के साथ जमकर आनंद उठाते थे। इसी आनंद-आनंद में इस दंपत्ति को न जाने किसकी नजर लग गई कि इनका कुनबा बिखरने लगा। दरअसल, मैडम की नजर किसी और से लग गई। पहले तो सबकुछ चोरी-छिपे चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे मामला इश्क-मुश्क छिपाए न छिपते हैं की तर्ज पर उजागर होने लगा। सूत्रों का कहना है कि एडिशनल एसपी साहब ने बिखरते परिवार को जोड़ने के लिए काफी कोशिश की। लेकिन अपने नए प्रेमी के प्यार में मैडम इस कदर पागल हो गई कि उन्हें अपने पति की तनिक भी फिक्र नहीं रही। वे अपने प्यार पर इस कदर न्यौछावर होने लगी थीं कि उनके पति रात-दिन अपनी इज्जत और मैडम की फिक्र में खोने लगे। सूत्रों का कहना है कि आज स्थिति यह है कि जहां एक ओर मैडम प्यार में खोई हुई है, वहीं साहब डिप्रेशन में चले गए हैं। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या डिप्रेशन में चले गए अपने एक अफसर को इससे निकालने के लिए सरकार उनका इलाज कराएगी?

चोरी-चोरी पिया करो

आपने पंकज उधास की यह गजल तो सुनी ही होगी कि महंगी बहुत शराब है, थोड़ी-थोड़ी पिया करो...। कुछ इसी तर्ज पर प्रदेश के एक दारूखोर मंत्रीजी अब चोरी-चोरी शराब पी रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कभी ग्वालियर चंबल अंचल के तीन-चार मंत्रियों के साथ महफिल सजाकर दारू पीने वाले मंत्रीजी अब तथाकथित तौर पर शराबखोरी छोड़ चुकी हैं। बताया जाता है कि हमेशा विवादों को जन्म देने वाले मंत्रीजी के राजधानी स्थित बंगले पर शाम को शराब की महफिल जम जाती थी। उनके साथी मंत्री पानी की तरह शराब बहाते थे। इस दौरान मंत्रीजी और एक सरकार के कददावर युवा मंत्री उटपटांग हरकतें भी करते थे। लेकिन यह बात श्रीमती जी को पता चली तो वह भी अब बंगले पर आकर रहने लगीं। फिर क्या था। अपने आप को जंगल का शेर समझने वाले मंत्रीजी ऐसी भीगी बिल्ली बन गए हैं कि अब बंगले पर न शराब की महफिल सजती है और न ही साथी मंत्री आते हैं। उनके संगे-साथी का कहना है कि अब महफिल तो नहीं सजती है, पर मंत्रीजी चोरी-चोरी जाम छलकाते रहते हैं।

वाकई मप्र अजब है...

पर्यटन विभाग ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए जो स्लोगन तैयार कराया था कि मप्र अजब है-गजब है, वह प्रदेश में कई मामलों पर खरा उतरने लगा है। इस बार इस स्लोगन की जिस मामले में बात हो रही है, वह वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि सरकार के मुखिया ने प्रशासन के मुखिया को एक पटवारी का तबादला करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश पर प्रशासन के मुखिया ने तत्काल उक्त पटवारी का तबादला करने का आदेश दे दिया था। लेकिन विडंबना यह देखिए कि आज तक उक्त पटवारी अपनी जगह पर कायम है। दरअसल, पटवारियों के रिकार्ड का संधारण सीएलआर ऑफिस ग्वालियर करता है। लेकिन लेकिन हैरानी की बात यह है कि शासन और प्रशासन के मुखिया के निर्देश के बाद भी आज तक उस पटवारी का तबादला नहीं हो पाया है। इस बात को जो भी सुनता है, वह यही कहता है कि जब शासन और प्रशासन के मुखिया का यह हाल है तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। अब देखना यह है कि बड़े लोगों का यह निर्देश कब तामील होता है।

सीता माता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उनके आकर्षण के कारण ही श्रीराम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए। ऐसे ही आजकल गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे हैं। मुझमें कोई क्वालिटी तो होगी।

● **राजेंद्र गुढ़ा**

साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब जीतने के बाद भारत में आत्मविश्वास बढ़ा है। ये जीत मोटिवेशनल है, पर फीफा वर्ल्डकप अभी दूर की बात है। हमारे देश में फुटबॉल का माहौल यूरोप जैसा नहीं है। अभी भारत में खिलाड़ी फुटबॉल को कैरियर नहीं समझते। उम्मीद है जल्द ही भारत फुटबॉल में मजबूत होगा।

● **संदेश झिंगन**

मेरी सरकार और इजराइल के लोग बहादुर जवानों की मौत से दुखी हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और ये वादा भी करते हैं कि चाहे जो भी हो इजराइल किसी आतंकी को छोड़ेगा नहीं। हम जहां इजराइली लोगों को बसाना चाहते हैं, वहां जरूर बसाएंगे। आतंकी चाहे जहां हों, उनकी पनाहगाहें तबाह की जाएंगी। उनका सफाया किया जाएगा।

● **बेंजामिन नेतन्याहू**

भाजपा विकास को नजरअंदाज करके राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश रच रही है। यूसीसी आदिवासियों में भ्रम बढ़ाएगा। इससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा और परंपरा, रीति-रिवाजों को मानने वाले वर्ग की पहचान को झटका लगेगा।

● **चंद्रशेखर राव**

आखिरकार अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूं जो मैं पिछले 4 सालों से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन, मुझे अपना ये सपना सच करने के लिए सही टीम के साथ की जरूरत थी। मैंने जैसी पढ़ाई की और मेरे बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से मैं हमेशा से एक्टिंग से बढ़कर कुछ और भी करना चाहती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरी टीम और मेरा विजन एक ही है और ये विजन मेरे सपनों को सच करने में मेरे काम आएगा। मैं क्लेंस्टा के साथ इंवेस्टर और पार्टनर के तौर पर अपनी नई शुरुआत को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। मैंने इस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहा इसकी सिर्फ एक ही वजह है-ये ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे फिलहाल कोई भी नहीं बना रहा।

● **परिणीति चोपड़ा**

वाक्युद्ध

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की जो कवायद चल रही है, उसमें न कोई नेता है, न नीयत है और न ही नीति है। यह कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये सभी अपने-अपने भ्रष्टाचार को बचाने में जुटे हुए हैं। विपक्ष का यह जमावड़ा भले ही एकजुट दिख रहा है, लेकिन चुनाव से पहले यह बिखर जाएगा।

● **जेपी नड्डा**

विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। फिर विपक्ष की एकजुटता से वे और उनकी पार्टी क्यों घबराई हुई है। विपक्षी एकता पूरी तरह मजबूत है और सबका एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। हम इसमें सफल भी होंगे।

● **मल्लिकार्जुन खड़गे**

आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन

मास्टर प्लान के लिए लोगों ने जो आपत्तियां लगाई हैं, सरकार उन्हें फेस-टू-फेस सुनने की बजाय ऑनलाइन समाधान करने की तैयारी में है...

आखिरकार करीब 17 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान को लागू करने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस मास्टर प्लान के लिए लोगों ने जो आपत्तियां लगाई हैं, सरकार उन्हें फेस-टू-फेस सुनने की बजाय ऑनलाइन समाधान करने की तैयारी में है। यानी लोगों ने जो आपत्तियां उठाई हैं, उसे सरकार अपने तरीके से निपटा देगी। न लोगों की बातों को सुना जाएगा, न ही उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा। ढाक के तीन पात वाली स्थिति बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सरकार ने लोगों से मास्टर प्लान पर आपत्तियां क्यों मांगीं।

मास्टर प्लान पर कुल 2961 आपत्तियां आई हैं। सरकार के पास जो आपत्तियां पहुंची हैं, उनमें से लैंड यूज की 25.67 प्रतिशत, कैचमेंट की 20.3 प्रतिशत, फार की 13.13 प्रतिशत, सड़क की 11.04 प्रतिशत, रेगुलेशन्स की 8.36 प्रतिशत, सिटी फॉरेस्ट की 5.67 प्रतिशत, आरजी4 की 4.78 प्रतिशत, एलडीआर की 4.48 प्रतिशत, लेक फ्रंट की 3.28 प्रतिशत, नर्सिंग होम की 1.79 प्रतिशत, 10 नंबर की 0.6 प्रतिशत, अरेरा कॉलोनी की 0.3 प्रतिशत, काउंट की 0.3 प्रतिशत और लहारपुर की 0.3 प्रतिशत आपत्तियां आई हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ लग रहा है कि सबसे अधिक आपत्तियां लैंड यूज पर आई हैं। गौरतलब है कि जमीनों के उपयोग के कारण ही पूर्व के वर्षों में मास्टर प्लान खारिज होते रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार सरकार ने ऑनलाइन आपत्तियां निपटाने की तैयारी की है।

गौरतलब है कि पूर्व में जब भी मास्टर प्लान का खाका आता था तो जितनी भी आपत्तियां आती थीं, उसकी सुनवाई आमने-सामने बैठकर होती थी। इससे शासन-प्रशासन के सामने वास्तविक स्थिति आ जाती थी। लेकिन इस बार ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सारी आपत्तियों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। विभागीय टिप्पणी के लिए इन्हें वर्गीकृत भी किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार आपत्तिकर्ताओं का सामना करने से क्यों कतरा रही है। ज्ञातव्य है कि एक महीने पहले भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया था। इसमें वर्ष 2021 में आई आपत्तियों और सुझावों को भी शामिल किया गया। वहीं, दावे-आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। इसकी 30 जून आखिरी तारीख थी। मास्टर प्लान पर आम जनता के साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी आपत्ति लगाई है। भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे उच्च वर्ग का मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। इसमें कई विसंगतियां हैं। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। उन्होंने मास्टर प्लान का ड्राफ्ट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि ड्राफ्ट में कैचमेंट को ग्रीन बेल्ट में दर्शाया गया है। साथ ही, तालाब का क्षेत्रफल 200 हैक्टेयर ज्यादा दर्शाया गया है। यह किस नियम के तहत किया गया? इसका आधार क्या है? इससे कैचमेंट क्षेत्र के रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। विधायक ने कहा कि भोपाल की भौगोलिक संरचना अन्य शहरों की अपेक्षा अलग है, इसलिए जोन वार मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके बाद भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार हो। विधायक ने कहा कि गांवों तक पहुंच मार्ग को 18 मीटर तक चौड़ा दर्शाया गया है, फिर इन गांवों में अन्य निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? भोपाल का भौगोलिक क्षेत्र अन्य शहरों की अपेक्षा अलग है, इसलिए पहले भोपाल का जोनल प्लान बनाया जाए। मास्टर प्लान में जहां सेंट्रल पार्क दर्शाया गया है, उस पर वन विहार सात महीने पहले ही आपत्ति जता चुका है। जब ऐसा है, तो मास्टर प्लान में सेंट्रल पार्क को किस आधार पर दर्शाया गया। भौतिक सत्यापन के बिना मास्टर प्लान जारी करना नागरिकों व भोपाल के साथ अन्याय होगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान में कालापानी, बोरदा, सतगड़ी, समसगढ़ आदि जिस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया गया। यहां बड़ी आबादी पहले से रहती है, जहां शासन द्वारा उन्हें पट्टे भी दिए गए, अन्य को भी जल्द दिए जाने हैं। निवेश क्षेत्र धामनिया खोरी गोल व शोभापुर में आद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाए। ग्राम मुंडला, आमला व सरवर के मध्य औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाए। कैचमेंट क्षेत्र में 1100 वर्ग फीट क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट के निर्माण की अनुमति दी जाए।

साथ ही, कैचमेंट क्षेत्र में फार्म हाउस की भी अनुमति दी जाए। फंदा ब्लॉक के दक्षिण क्षेत्र की ओर विकास योजना में ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका पुन: अवलोकन किया जाए। इंदौर से सीहोर मार्ग को व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा को मास्टर प्लान 2031 में सम्मिलित करें। फंदा के दक्षिण क्षेत्र में हवाई पट्टी प्रस्तावित की जाए।

● **प्रवीण सक्सेना**

ये आपत्तियां लगाई गईं

भोपाल के बड़ा तालाब के कैचमेंट प्रभावित गांवों को कैचमेंट के नाम से मुक्त किया जाए। कैचमेंट के नाम पर जो भी प्रावधान नकारात्मक किए गए हैं, उन्हें हटाया जाए। फंदा, भदभदा, रातीबड़, नीलबड़ मार्ग पर बसे गांवों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं हैं। इन गांवों को आवासीय योजना में शामिल किया जाए। भोपाल-सीहोर रोड पर पूरी भूमि ग्रीन बेल्ट में दर्शाई गई हैं, यह उचित नहीं है। कोलास नदी के आसपास के कैचमेंट एरिये की दूरी तय की जाए। कुछ जमीनों को डूब में दर्शाया जा रहा है, जो कभी डूब में थी ही नहीं। इसे आवासीय किए जाने की अनुमति दी जाए। भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 में 30 किलोमीटर दूर के क्षेत्र के आवासीय उपयोग के लिए उचित माना है, जबकि भोपाल से फंदा-सीहोर और भदभदा से रातीबड़-नीलबड़ रोड के बीच के गांवों को आवासीय नहीं किया गया है। संत हिरदाराम नगर पूरी तरह से कमर्शियल हो चुका है। यहां की आबादी भी काफी हो चुकी है। आसपास के इलाकों में भी बसाहट हो रही है। इसलिए आसपास की जमीनों को भी आवासीय किया जाए। कोलांस नदी के आसपास विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई हो। कॉलोनाइजरों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

युवाओं पर सत्ता का दांव

4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने मैदानी सक्रियता बढ़ा दी है। इनमें से केवल दो पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसके लिए दोनों पार्टियों का फोकस यूथ पर है। यानी दोनों पार्टियां जहां युवाओं को साधने में जुटी हुई हैं, वहीं युवा वोट बैंक को देखते हुए इस बार अधिक से अधिक टिकट युवाओं को देने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

भाजपा और कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए दोनों पार्टियों के युवा नेताओं के चेहरे पर चमक आ गई है। चुनावी साल में भाजयुमो और युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मैदानी मोर्चों पर अपना दम दिखा रहे हैं। साथ ही पार्टी आलाकमान के सामने अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2023 के चुनाव में प्रदेश में 52 फीसदी से अधिक युवा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में पार्टियों के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर युवाओं को टिकट दिया जाता है तो उनकी जीत की संभावना अधिक रहेगी। बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के रणनीतिकारों ने सभी 230 विधानसभा सीटों का आंकलन कर टिकट देने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत अगर विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो उसके सामने किसी युवा नेता को टिकट दिया जाए। हालांकि यह फॉर्मूला जीत की संभावना को देखते हुए ही लागू किया जाएगा।

चुनावी रण में उतरने के लिए युवा भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस चुनाव में यूथ कांग्रेस 35 सीटों पर तो भाजयुमो 46 सीटों पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजयुमो से टिकट के दावेदारों की अच्छी-खासी फौज है। कई इलाकों में तो सीटिंग विधायक की जगह टिकट का दावा किया जा रहा है। भाजयुमो ने संगठन से 20 प्रतिशत यानी करीब 46 सीटें मांगी हैं। हालांकि, उम्मीदवारी का मौका कितनी सीटों पर मिलेगा, यह कहीं से भी तय नहीं है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का कहना है कि टिकट का फैसला पूरी तरह भाजपा नेतृत्व का होगा। कई साथी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले चुनावों में भी भाजयुमो से टिकट मिला है और लोग जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन सर्वे के मुताबिक जिताऊ दावेदार को ही टिकट देगा। बाकी सबको पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए काम करना है। चुनावों को लेकर दोनों ही प्रमुख भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों द्वारा चुनावों की तैयारियां की जा रही है। अब तक दोनों ही प्रमुख दल द्वारा महिलाएं, युवतियां, बुजुर्ग, मजदूर और किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब दोनों ही दलों का फोकस युवाओं पर आ टिका है। इस फोकस का कारण चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा रहे नए मतदाताओं के आंकड़े हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा ही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। युवाओं को साधने की प्लानिंग के तहत जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है तो वहीं सत्ताधारी

मैदानी तैयारियां एक साल पहले से शुरू

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि युवाओं को जोड़ने की योजना पर एक साल पहले से काम चल रहा है। संगठन ने प्रदेश के 178 विधानसभा क्षेत्रों में खिलते कमल नाम से कार्यक्रम किया था। इसमें संबंधित क्षेत्र के प्रतिभाशाली और गांव-समाज में प्रभाव रखने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। ऐसे 400-500 प्रभावशाली लोगों का सम्मेलन किया। पिछले साल ही खेलेगा मप्र कार्यक्रम किया गया। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे खेल आयोजित किए गए। गांव-शहर के खेल प्रेमी युवाओं को संगठन की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश हुई। इसके बेहतर परिणाम बाद के कार्यक्रमों में दिखे हैं। 670 बाइक रैलियों के जरिए युवाओं को सरकार की विकास योजनाओं की झलक दिखाई गई। चुनाव नजदीक आते ही भाजयुमो ने संभाग स्तर पर बड़ी रैलियों की योजना बनाई है। इनमें संबंधित संभाग से हजारों युवाओं को बुलाने की तैयारी है। रैलियों में संबोधित करने के लिए भाजयुमो के राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को भी बुलाने का कार्यक्रम है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का कहना है कि संभागीय रैलियों के बाद प्रदेश स्तर की एक बड़ी सभा भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें भाजयुमो के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी बीच भाजयुमो युवा संकल्प यात्रा भी निकालेगा। भाजपा और भाजयुमो के रणनीतिकारों ने युवा वोटरों से बातचीत के लिए कुछ खास विषयों को ही चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सबसे बड़ा विषय है। बातचीत का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज गिनाने का है।

दल भाजपा ने भी अपना रुख युवाओं की तरफ कर दिया है।

दोनों पार्टियों के युवा नेता टिकट की दावेदारी को लेकर तर्क दे रहे हैं कि प्रदेश में कुल 5.40 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। इनमें से 2 करोड़ 85 लाख यानी 52 प्रतिशत मतदाता 18 से 40 साल के बीच के हैं। 30 लाख वोटर्स ऐसे हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। यही हार-जीत की दिशा तय करेंगे। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 7 लाख से कुछ अधिक थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 2023 में यह संख्या 5 करोड़ 40 लाख 94 हजार 746 हो चुकी है। इसका मतलब है कि इन पांच सालों में करीब 33 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच के तीन महीनों में प्रदेश में 1 लाख 6 हजार 870 मतदाता बढ़ गए हैं। मतदाता सूची में 38 हजार 235 वे नए मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से 1 अप्रैल की अर्हता तिथि में 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। इन लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन दिया था। बताया जा रहा है कि नए मतदाताओं में से करीब 30 लाख वोटर 18 से 21 साल के बीच के हैं। ये लोग इस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं।

5 जनवरी 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 मतदाता थे। तीन माह में मतदाताओं की संख्या में 1 लाख 6 हजार 870 की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 80 लाख 10 हजार 110 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख 83 हजार 368 है। निशक्त मतदाताओं की संख्या 4 लाख 82 हजार 148 है। प्रदेश में 1 हजार 268 मतदाताओं ने अपनी पहचान थर्ड जेंडर के तौर पर दर्ज कराई है। प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता युवा हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 40 साल तक मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 85 लाख से अधिक है। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख जबकि 30 से 39 साल तक के 1 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं। 40 से 49 साल के बीच 1 करोड़ 6 लाख से अधिक वोटर हैं। वहीं, 50 से 59 साल के बीच के मतदाताओं की संख्या 75 लाख बताई गई है। 60 से 69 साल के बीच के 43 लाख मतदाता हैं। 70 से 79 के बीच के 20 लाख और 80 साल से अधिक उम्र वाले 8 लाख मतदाताओं का नाम सूची में शामिल है।

भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के युवा संगठनों के पदाधिकारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजयुमो की तरफ से 20 प्रतिशत यानी 46 सीटों पर उम्मीदवारी का दावा किया गया है। वहीं, युवा कांग्रेस ने 35 टिकट मांगे हैं। दोनों ही संगठन उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कई स्तरों पर सर्वे करा रहे हैं। युवाओं को टिकट के सवाल पर दोनों संगठनों का एक सा जवाब है- जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका दिया जाएगा। उनका कहना है कि युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा गया तो पार्टी को फायदा होगा। नई लीडरशिप भी डेवलप होगी। युवा और नए चेहरों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। कांग्रेस ने फॉर्मूला तय कर लिया है कि उम्मीदवार के चयन का आधार बूथ जोड़ो-यूथ जोड़ो अभियान की सफलता होगा। इसी तरह भाजपा में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों की मेहनत पर टिका है। लिहाजा, दोनों ही दल टिकट फाइनल करने से पहले युवाओं को केंद्र में रखेंगे।

कांग्रेस ने इस अभियान में उन युवाओं को टारगेट किया है, जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं। युवा कांग्रेस की बूथ समितियों को जो जिम्मा दिया गया है, उनमें फर्स्ट टाइम वोटर की पहचान करना भी शामिल है। इन लोगों से लगातार संपर्क में बने रहने का टास्क भी अलग-अलग टीमों को मिलेगा। मतदाता सूची से जिन वोटरों का नाम कट गया है या जो उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं यानी फर्जी हैं, उनकी पहचान भी करनी होगी। पिछले चुनाव में फर्जी वोटरों की कई शिकायतें आई थीं। उस समय संगठन पर इसे लेकर सवाल भी उठे थे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बताते हैं कि इस महीने से मप्र समृद्धि कार्ड अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की पांच गारंटियों को लेकर घर-घर दस्तक देंगे। सभी को इससे जुड़ी पुस्तिका, ब्रोशर आदि दिया जाएगा। मप्र समृद्धि कार्ड अभियान की निगरानी युवा कांग्रेस की केंद्रीय टीम कर रही है। इसके लिए युवा कांग्रेस के 14 राष्ट्रीय सचिवों को मप्र भेजा गया है।

● **कुमार राजेन्द्र**

ये हैं प्रदेश के युवा विधायक

2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 40 साल से कम वाले 15 विधायक चुनाव जीते थे। इनमें राम डंगोरे (29) पंधाना, शरद कोल (28) ब्यौहारी, सुभाष रामचरित्र (31) देवसर, दिव्यराज सिंह (33) सिरमौर, आकाश विजयवर्गीय (34) इंदौर 3, सुमित्रा कास्डेकर (35) नेपानगर, (2018 में कांग्रेस से और 2020 में भाजपा से विधायक), विक्रम सिंह (36) रामपुर बघेलान, कमलेश जाटव (37) अम्बाह, राजेश कुमार प्रजापति (37) चंदला, मनीषा सिंह (37) जैतपुर, केपी त्रिपाठी (38) सेमरिया, शिवनारायण सिंह (38) बांधवगढ़, धर्मेंद्र सिंह लोधी (40) जबेरा, योगेश पंडाग्रे (40) आमला और आशीष गोविंद शर्मा (40) खातेगांव शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से 19 युवा विधायक चुनाव जीते थे। उनमें जयवर्द्धन सिंह (32) राघौगढ़, प्रियव्रत सिंह (40) खिलचीपुर, कुणाल चौधरी (36) कालापीपल, नीरज विनोद दीक्षित (29) महाराजपुर, कल्पना वर्मा (29) रैगांव, नीलेश पुशाराम उइके (30) पांढुर्ना, विपिन वानखेड़े (32) आगर, (2020 में विधायक बने), हिना लिखीराम कांवरे (33) लांजी, सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू (33) सतना, नीलांशु चतुर्वेदी (35) चित्रकूट, भूपेंद्र सिंह (35) शहपुरा, प्रवीण पाठक (36) ग्वालियर दक्षिण, सचिन यादव (36) कसरावद, हीरालाल अलावा (37) मनावर, मनोज चावला (38) आलोट, तरबर सिंह (38) बंडा, सचिन बिरला (39) बड़वाह, विशाल पटेल (39) देपालपुर और निलय डागा (40) बैतूल शामिल हैं। वहीं बसपा के दोनों विधायकों- संजीव सिंह और रामबाई की उम्र 2018 में 40 साल थी।

सतपुड़ा की आग में करोड़ों स्वाहा

कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार यह है रीडेवलपमेंट प्लान

कंसल्टेंट कंपनी ने सतपुड़ा भवन की आग के बाद रीडेवलपमेंट का जो प्लान बनाया है, उसके अनुसार बिल्डिंग पर 72.78 करोड़ खर्च किए जाएंगे। रीडेवलपमेंट प्लान के अनुसार साइट डेवलपमेंट के तहत सड़क पर 37 लाख, पार्किंग एरिया पर 5.59 करोड़, बाउंड्रीवाल, गेट पर 39 लाख खर्च होंगे। वहीं बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में टेक्स्चर सर्फेस (धौलपुर स्टोन फिनिश/एक्सपोस्ड कांक्रीट फिनिश) पर 1.99 करोड़, विंडो ग्लाइजिंग पर 1.6 करोड़, फ्रंट सेंट्रल लॉबी एरिया पर 28 लाख और कैनोपी पर 28 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इंटरनल कंपोनेंट्स में कॉमन एरिया, एंटरेंस लॉबी, स्टेयरकेस और लिफ्ट लॉबी, कॉरिडोर्स, फ्लोरिंग, रेलिंग, फॉल सीलिंग, लाइटिंग पर 1.86 करोड़, कैंटीन, सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिस रूम और स्टॉफ रूम पर 1.26 करोड़, बेसमेंट एरिया में वॉटर सप्लाई और फायर फाइटिंग पम्प रूम पर 14 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार ओपन स्पेस पर इंटरनल कोर्टयार्ड में 35 लाख, रूफ टॉप पर 23 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं बिल्डिंग सर्विसेस के तहत फायर अलार्म पर 1.52 करोड़, सीसीटीवी कैमरों पर 2.38 करोड़, ईवीएसी सिस्टम 74 लाख, इमरजेंसी लाइटिंग पर 1.65 करोड़ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर 5.60 करोड़, फायर हाइड्रेंट सिस्टम पर 1.88 करोड़, फायर स्प्रिंक्लर्स पर 1.83 करोड़, एचटी एंड एलटी इलेक्ट्रिकल्स पर 12.35 करोड़, राइजिंग मैन एंड इंटरनल इलेक्ट्रिकेशन कंप्लीट पर 13.27 करोड़ और अंडर ग्राउंड वॉटर टैंक पर 1.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एसटीपी 100 केएलडी पर 1.10 करोड़, रैनवॉटर हार्वेस्टिंग पर 40 लाख, सीवर लाइन, स्टोर्म वॉटर ड्रेनेज पर 42 लाख, इंटरनल वॉटर सप्लाई एंड प्लंबिंग सर्विसेस पर 60 लाख और हार्ड एंड सॉफ्ट लैंडस्कैपिंग पर 37 लाख रुपए खर्च होंगे।

मप्र की राजधानी भोपाल की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली अरेरा हिल्स पहाड़ी पर बनी तीन भव्य इमारत वल्लभ भवन-1, सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन का कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है। दरअसल, सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद सरकार ने सबक लेते हुए इन तीनों बिल्डिंगों का कायाकल्प करने की योजना बनाई है। बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग ने तीनों बिल्डिंगों का सर्वे करके सामान्य प्रशासन विभाग को रिनोवेशन का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार सतपुड़ा भवन का रिनोवेशन 72.78 करोड़, विंध्यालय भवन का 62 करोड़ और वल्लभ भवन-1 पर 100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर जीएडी को भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि जीएडी इसके लिए फंड मुहैया कराता है या नहीं। एक बात यह भी तय है कि सतपुड़ा की आग से जहां सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है, वहीं अन्य बिल्डिंगों के रिनोवेशन पर भी करोड़ों रुपए स्वाहा होंगे।

गौरतलब है कि 12 जून को प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी प्रशासनिक बिल्डिंग सतपुड़ा भवन में आग लग गई थी। करीब 14 घंटें बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को काफी क्षति पहुंची। जानकारों का कहना है कि आग के दौरान तापमान करीब 1500 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में बिल्डिंग के कांच तक पिघल गए। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बिल्डिंग का ढांचा पूरी तरह खराब हो गया होगा। यानी यह बिल्डिंग अब कार्यालय चलाने लायक नहीं बची है। यही वजह है कि सरकार ने इसका सेफ्टी ऑडिट कराया है। इसके बाद रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है।

रीडेवलपमेंट प्लान को धरालत पर उतारने से पहले सतपुड़ा भवन के ईंट, प्लास्टर, लोहा आदि का सैंपल लिया गया है। इन सैंपलों का परीक्षण नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में नॉन डिस्ट्रेक्टिव टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। इस टेस्ट से बिल्डिंग की क्षमता का आंकलन किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि बिल्डिंग का आगे उपयोग हो पाएगा या नहीं। सरकार इस टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट को 10 लाख रुपए फीस देगी।

दरअसल, सतपुड़ा भवन की आग के बाद सरकार को वीबी-1 और विंध्याचल भवन की चिंता सताने लगी है। पुनर्निर्माण के इस दौर में इनकी दीवारें खोखली होती जा रही हैं जिससे इमारत के कमजोर होने का तथा उसमें कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जान-माल का खतरा पैदा हो गया है। परंतु सतपुड़ा भवन की आग से पहले इस दिशा में जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया तथा बिल्डिंग के हर फ्लोर पर रिनोवेशन धड़ल्ले से किया गया। जबकि इन बिल्डिंगों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ी है। वहीं फाइलों, फर्नीचर और अन्य संसाधनों का भी बोझ इन पर बढ़ा है। इसलिए सरकार ने इन बिल्डिंगों का सेफ्टी ऑडिट कराकर इनके रिनोवेशन का खाका तैयार करवाया है।

राजधानी की शान मंत्रालय वल्लभ भवन वर्ष 1964 में बना था, इसमें अभी हाल के वर्षों में दो नए विंग बनाकर इसका विस्तार किया गया है परंतु 59 साल पुरानी बिल्डिंग में तोड़फोड़ नहीं की गई है जो उचित है। वहीं सतपुड़ा भवन भी लगभग 40 वर्ष पुराना है इसमें कई विभागों के संचालनालय हैं तथा अपनी-अपनी सुविधा और मर्जी के मुताबिक रिनोवेशन का कार्य करवाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार की तोड़फोड़ से भवन कमजोर हो रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रमुख भवन विंध्याचल है। यह भी लगभग 40 वर्ष पुराना है, इसमें मुख्यत: कृषि, ग्रामीण विकास, सहकारिता, उद्यानिकी, राज्य योजना आयोग, विधि विभाग है। जिसमें 6 हजार कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं। सभी विभागों में एक-दो बार रिनोवेशन का कार्य हो गया है। लेकिन इस दौरान सुरक्षा मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया है। हाल ही में सरकार ने जो सेफ्टी ऑडिट कराया है, उसमें 444 कमियां बताई गई हैं, वहीं 428 कमियां दूर की गई हैं। साथ ही बिजली का लोड भी कम किया गया है। अब देखना यह है कि इन तीनों बिल्डिंगों के रिनोवेशन के लिए सरकार हरी झंडी देती है या नहीं।

● **सुनील सिंह**

वचन पत्र बनेगा वोट बैंक

मप्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि जीत हासिल करने के लिए दोनों ही ओर से दांव चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव को जीतने के लिए हर वर्ग के लिए वचन पत्र बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी अपने वचन पत्र को ही वोट बैंक मान रही है। दरअसल, 2018 में कांग्रेस की जीत में उसके वचन पत्र का बड़ा योगदान था। इसलिए कांग्रेस का इस चुनाव में भी वचन पत्र पर फोकस है। इस बार पार्टी वोट के हिसाब से वचन पत्र तैयार करवा रही है। वचन पत्र में सभी वर्गों, खासतौर पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के लिए लुभावने वादे शामिल होंगे।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टी के रणनीतिकारों ने जाति, वर्ग, उम्र के मतदाताओं की संख्या का आंकलन किया है। मतदाताओं की संख्या के इसी गणित के चलते पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है और उनका दिल जीतने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी ने इनको लुभाने के लिए कदमताल तेज कर दी है। उधर, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि आज प्रत्येक वर्ग यह जानना चाहता है कि पार्टी सरकार बनने पर उनके लिए क्या करेगी। इसे अच्छे तरीके से जनता के बीच रखने के लिए अलग-अलग वचन पत्र तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को यह वचन देगी कि सरकार में आने पर उनके लिए स्वरोजगार योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाकर प्रदेश में स्थापित उद्योगों में नियोजित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुटी है। सरकार में आने पर पार्टी किस वर्ग के लिए क्या करेगी, इसका उल्लेख वचन पत्र में किया जाएगा। अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से वचन पत्र जारी होगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा। इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी के संबंधित विभागों की रहेगी। 230 सदस्यीय मप्र विधानसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। वचन पत्र तैयार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इसने सभी वर्गों से संबंधित विषयों पर उप समितियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करके राज्य स्तरीय वचन पत्र का प्रारूप तैयार किया है। पार्टी सरकार में आने पर अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या करेगी, इसे अलग-अलग वचन पत्र जारी कर बताया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के संबंधित विभागों की रहेगी। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 47 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 35 सीटें सुरक्षित हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही इन वर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत हैं। शिवराज सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए अलग-अलग स्वरोजगार योजनाएं प्रारंभ की हैं। पेसा के नियम लागू करके आदिवासी वर्ग को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। वहीं, कांग्रेस कमलनाथ सरकार में इन वर्गों के लिए किए गए कामों को आधार बना रही है।

कांग्रेस के निशाने पर आधी आबादी भी है। कमलनाथ इसके जरिए चुनावी वैतरणी को पार करने की कवायद में जुट भी गए हैं। राज्य में कुल मतदाता 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 79 लाख 62 हजार 711 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 है। यह वचन पत्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर होगा और इसे प्रियदर्शनी नाम दिया जाएगा। इस वचन पत्र में महिलाओं के लिए खास प्रावधान होंगे। महिला सुरक्षा, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक दलों की महिलाओं को लुभाने के लिए चल रही कवायद के बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही दल महिलाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मगर सवाल यह उठ रहा है क्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि मप्र में 230 विधानसभा सीटें हैं और उनमें सिर्फ 21 महिलाएं विधायक हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो आबादी भले आधी हो। मगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व उनका 10 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि महिलाओं के हित की लड़ाई सदन में कभी नहीं लड़ी जा सकी है, क्योंकि उनसे जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले प्रतिनिधि ही कम होते हैं। सवाल है क्या दोनों ही राजनीतिक दल आबादी के आधार पर महिलाओं को चुनाव मैदान में भी उतारेंगे।

● **अरविंद नारद**

युवाओं व किसानों के लिए भी वचन पत्र

कांग्रेस महिलाओं के साथ-साथ युवाओं और किसानों के लिए अलग से वचन पत्र बनाएगी। इसके माध्यम से यह बताया जाएगा कि सरकार बनने पर वह क्या और कैसे करेगी। हर वर्ग के युवाओं के लिए अलग-अलग स्वरोजगार की योजना लागू करने का वचन दिया जाएगा। वहीं, किसानों से संबंधित वचन पत्र में उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ सभी किसानों की ऋण माफी पूरी करने का वादा रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र समिति को युवा और किसानों के लिए अलग से वचन पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के रोजगार की है। प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इनके लिए भाजपा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी वर्गों के युवाओं के लिए स्वरोजगार की अलग-अलग योजनाएं लागू की जाएंगी। उद्योगों के साथ युवाओं को संबद्ध कर रोजगार दिलाया जाएगा। प्रत्येक योजना में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

पीडब्ल्यूडी ने व्यवस्थित की 25 हजार नस्तियां

सतपुड़ा भवन में लगी आग से करीब-करीब विभिन्न विभागों की 12 हजार से अधिक फाइलें स्वाहा हो गई हैं। इनमें से कई फाइलों का जहां डिजिटलाइजेशन हो गया था, वहीं अधिकांश फाइलें जलने के साथ ही उनका किस्सा भी खत्म हो गया है। आग में जो चीजें जली हैं, उन्हें दोबारा तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन इस आग से विभागों को बड़ा सबक मिला है। इससे सबक लेते हुए लोक निर्माण विभाग ने वल्लभ भवन-1 में अपनी सारी फाइलों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार विभाग ने पुराने भवन में रखी लगभग 25 हजार नस्तियों को व्यवस्थित कर दिया है।

जिस तरह किताब में इंडेक्स देखकर संबंधित विषय के पेज पर आसानी से पहुंचा जाता है, उसी तरह लोक निर्माण विभाग में भी 25 हजार फाइलों को व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही इन फाइलों का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। दरअसल, अभी तक विभागों में फाइलें जहां की तहां पटक दी जाती थीं। स्थिति यह थी कि एक फाइल को खोजने के लिए कई-कई दिन लग जाते थे। लेकिन सतपुड़ा भवन की आग ने विभागों को सचेत कर दिया है, वहीं यह सबक भी सिखा दिया है कि विभाग अपनी फाइलों को यहां-वहां फेंकने की बजाय व्यवस्थित करके रखे। फाइलों को व्यवस्थित करने की सबसे पहले पहल लोक निर्माण विभाग ने की है। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग प्रदेशभर में हो रहे निर्माण कार्यों का पैरेंट डिपार्टमेंट है। इसलिए इस विभाग में प्रदेश के विकास योजनाओं से संबंधित फाइलें रहती हैं। ये फाइलें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर ये फाइलें व्यवस्थित और सुरक्षित नहीं रहीं तो प्रदेश का विकास प्रभावित हो सकता है।

12 जून को सतपुड़ा भवन में लगी आग से पहले लोक निर्माण विभाग में भी फाइलें अव्यवस्थित रहती थीं। अधिकारी-कर्मचारी फाइलों को जहां के तहां रख देते थे। स्थिति यह थी कि जब जरूरत पड़ती थी तो फाइलों की खोजबीन में सब जुट जाते थे। इससे कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक आग ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को जागृत कर दिया है। अब लोक निर्माण विभाग में पुरानी फाइलों को इस तरह व्यवस्थित ढंग से रखा जा रहा है, जैसे किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें रहती हैं। बकायदा कैटेगिरी वाइज फाइलें रखी गई हैं। इनकी एंट्री रजिस्टर में की गई है। यानी कोई अनजान व्यक्ति भी उस रजिस्टर को देखकर फाइल तक पहुंच सकता है। बकायदा फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए विभाग ने कर्मचारियों को काम पर लगाया है।

लोक निर्माण विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 हजार से अधिक नस्तियों को ढूंढने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। वहीं इन नस्तियों का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। इस काम में अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं। बताया जाता है कि कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। वहीं जिस तरह लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है, जिसे हर किताब की जानकारी होती है, उसी तरह लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी फाइलों की लाइब्रेरी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कौनसी फाइल कहां है, इसकी पूरी जानकारी इनको होगी। जानकारी के अनुसार इन फाइलों को इस तरह रखा गया है कि अगर कोई घटना-दुर्घटना होती है तो इनको तत्काल दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि लोक निर्माण विभाग की तरह ही प्रदेश के अन्य सरकारी विभाग अपने विभागों की फाइलों और नस्तियों को इसी तरह व्यवस्थित करेंगे।

● **कुमार विनोद**

फायर सेफ्टी पर भी किया जा रहा फोकस

दरअसल, सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी, तो वह आग तेजी से इस कारण फैली थी कि हर फ्लोर पर फाइलें जहां की तहां पड़ी हुई थीं। इन फाइलों ने आग में फ्यूल का काम किया। जिस कारण आग विकराल रूप धारण कर पाई। इसलिए लोक निर्माण विभाग ने फायर सेफ्टी के मद्देनजर फाइलों को व्यवस्थित किया है। गौरतलब है कि सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद प्रशासन ने बड़ा सबक लिया है। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो इसके लिए अब हर सरकारी बिल्डिंग के उपकरणों की जांच कराई गई है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। सरकारी बिल्डिंगों में कितने उपकरणों की आवश्यकता है और कितने उपकरण लगाए गए हैं, इसकी गिनती की गई है। लोक निर्माण विभाग की जांच में पाया गया कि आवश्यकता से अधिक उपकरणों और अनियंत्रित विद्युत लोड के कारण आग ज्यादा तेजी से फैली। उल्लेखनीय है कि 12 जून को सतपुड़ा भवन में लगी आग के मामले में जांच दल ने 287 पन्नों का जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार शासन दारा गठित जांच समिति ने 3 स्थल निरीक्षण, 32 बयानों, राज्य स्तरीय फोरेंसिक साइंस लैब, सागर की जांच रिपोर्ट, चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर और उनके जांच दल की तकनीकी रिपोर्ट, नुकसान के आंकलन के लिए बनी पीडब्ल्यूडी की 2 उप समितियों के प्रतिवेदन को शामिल करते हुए कुल 287 पन्नों का जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत कर दिया है। आखिर 14 घंटे बाद भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग बुझ गई है, लेकिन कई सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन विभागों में रखे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, शिकायत शाखा समेत विधानसभा प्रश्न से संबंधित दस्तावेज जल गए हैं। हजारों की संख्या में यहां फाइल्स मौजूद थीं, जिनके पूरी तरह जलकर राख हो जाने की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि यहां कोरोनाकाल के समय स्वास्थ्य विभाग में की गई खरीदी और अस्पतालों को किए गए भुगतान से जुड़ी फाइल्स भी थीं। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अग्निकांड की जांच के लिए बनी समिति के सदस्य राजेश राजौरा ने बताया कि इमारत के अंदर जाना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए यह बताना कि अंदर कितनी फाइल्स जली हैं या बच गई हैं, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। एक बार जांच पूरी हो जाए तभी पता चल सकेगा कि कितनी फाइल्स आग से नष्ट हुई हैं।

आदिवासियों के नाम पर महाघोटाला

मप्र में आदिवासियों के नाम पर जमीनों को हड़पने का बड़ा खेल खेला जा रहा है। आदिवासियों की जमीन बेचने में जबलपुर जिले में हुए खेल में चार अफसरों पर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इससे कहीं बड़ा खेल कटनी जिले में हुआ है। दो दशक में कलेक्टरों की अनुमति से आदिवासियों की 2100 एकड़ से अधिक जमीन अन्य वर्ग को बेच दी गई। हालांकि अभी तक सिर्फ एक आईएएस अफसर अंजू सिंह बघेल पर ही कार्रवाई की गई है। कटनी जिले में जमीन का यह पूरा खेल रसूखदारों के दम पर खेला गया, जिसकी आड़ तत्कालीन कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी बने। इन्होंने आदिवासियों की जरूरत के हिसाब से कम बल्कि रसूखदारों की पहुंच पर अधिक अनुमतियां जारी कीं। हद तो इस बात की है कि अधिकारियों ने उन जमीनों को भी बचने की अनुमति दे दी, जो शासन ने आदिवासियों को जीवन यापन के लिए पट्टे पर दी थी।

दो दशक के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 2006 से 2008 के बीच आदिवासियों की जमीन हड़पने में कोई गिरोह लगा हुआ था, जिसका हथियार प्रशासनिक अमला बना। इस अवधि में सबसे अधिक 123 आदिवासियों की जमीन बिक्री अनुमति जारी की गई। समाज के अंतिम पंक्ति में आने वाले आदिवासियों के हित संरक्षण और उन्हें छल से बचाने के लिए गैर आदिवासी को जमीन बेचने के लिए राजस्व संहिता में प्रावधान किया गया है। इसमें बेटी-बेटे के विवाह होने, बीमारी या अन्य आपात स्थिति पर कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई के बाद ही आदिवासी को जमीन बेचने की अनुमति दी जाती है। आदिवासियों की जमीनों की खरीद-फरोख्त का खेल जिले में पदस्थ रहे पांच कलेक्टरों के कार्यकाल में जमकर हुआ। जिन 281 आदिवासियों को जमीन बेचने की अनुमति दी गई, उनमें 204 आदिवासियों को तो सिर्फ 5 कलेक्टरों के कार्यकाल में ही स्वीकृति मिली। बाकी 10 कलेक्टरों ने सिर्फ 77 आदिवासियों को अनुमति दी। जानकारी के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने के सबसे अधिक मामले 2006 से 2008 तक सामने आए हैं। इस दौरान 123 आदिवासियों ने 619 हेक्टेयर जमीन बेची। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर अनुपम राजन व अंजू सिंह बघेल रहीं। इसके अलावा वर्ष 2011, 2012 व 2013 में भी 81 आदिवासियों को जमीन बेचने की अनुमति दी गई। इस दौरान एम सेल्वेंद्रम व अशोक कुमार सिंह कलेक्टर रहे।

इस खेल में एक दर्जन अफसर शामिल रहे, जो दो दशक से कटनी में कलेक्टर के तौर पर पदस्थ रहे हैं। कार्रवाई महज एक कलेक्टर अंजू सिंह बघेल पर ही हुई। अंजू सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 7.6 हेक्टेयर जमीन अपने बेटे अभिवेंद्र के नाम स्थानांतरित कर दी थी। जिले में अब तक 15 कलेक्टर पदस्थ रहे हैं। इनमें शहजाद खान 1998-2001, आरआर गंगारेकर 2001-2004, आरके माथुर 2004-2004, अनुपम राजन 2004-2007, अंजू सिंह बघेल 2007-2009, एम सेल्वेंद्रम 2009-2011, केवीएस चौधरी 2018-2019, डॉ. पंकज जैन 2019-2019, अशोक सिंह 2012-2014 विकास सिंह नरवाल 2014-2016, प्रकाश जांगरे 2016-2016, एसबी सिंह 2019-2020, प्रियंक मिश्रा 2020-2022, विशेष गढ़पाले 2016-2018 और अविप्रसाद 2022 से अब तक कलेक्टर हैं।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, दो दशक में कटनी जिले में 281 आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को बेचने की अनुमति तत्कालीन कलेक्टरों ने दी। इससे 860 हेक्टेयर यानी 2127 एकड़ जमीन दांव पर लग गई। इन जमीनों को बेचने वाले आदिवासी परिवार कहां और किस हाल में हैं, किसी को कुछ नहीं पता। प्रशासन भी इनके बारे में नहीं बता पा रहा है। आदिवासियों को जमीन बेचने की सबसे अधिक अनुमति 2006 से 2008 के बीच जारी की गई। यह वह समय था, जब जमीन के दाम आसमान पर थे और कारोबार अपने चरम पर पहुंच गया था। इन तीन सालों में आदिवासियों की जमीन बिक्री का औसत 80 फीसदी रहा। आदिवासी की जमीन सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचने की प्रक्रिया जटिल है। कलेक्टर को जमीन के विक्रय करने वाले का उद्देश्य और खरीदार से संबंधित कारण में संतुष्ट होना आवश्यक है। ये आवश्यक है कि जिस जगह की जमीन है खरीदार भी वहीं का निवासी हो। जबकि इस अनुमति में जबलपुर और कटनी जिले के निवासी है। कलेक्टर की अनुमति में जमीन बेचने और खरीदने का प्रयोजन के साथ उद्देश्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी इस प्रक्रिया में नहीं हुआ। बता दें कि कुल 13 प्रकरणों में से सर्वाधिक 7 मंजूरियां बसंत कुर्रे की तरफ से जारी हुईं। इसके बाद 3 मामलों में ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने, 2 मामलों में एमपी पटेल और 1 मामले में दीपक सिंह ने जमीन हस्तांतरण की अनुमति दी थी।

● **राजेश बोरकर**

जिंदा आदिवासी को मृत बताकर बेची जमीन

हाल ही में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा में जिंदा आदिवासी रतिया कोल को मृत घोषित करते हुए उसकी बेशकीमती जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। विधायक संजय पाठक ने मामला संज्ञान में आने के बाद पीड़ित आदिवासी को न्याय दिलाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार कलहरा ग्राम निवासी रतिया कोल की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर अजब-गजब कारनामे को अंजाम दिया। पहले तो बुजुर्ग रतिया कोल को 1998 में मृत रतिया बाई के कागजात लगाकर जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दिया, फिर उनकी 0.55 हेक्टेयर जमीन को फौती साबित कर दिया। वहीं, अब जिंदा इंसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटक रहा है। मामला सुनने में भले ही फिल्मी लग रहा हो लेकिन ये पूरी आपबीती विजयराघवगढ़ के रतिया कोल की है। जो अधिकारियों के चक्कर लगाकर जब थक गया तो वो स्थानीय विधायक संजय पाठक के पास जा पहुंचा। पीड़ित रतिया कोल की बात सुनकर तो एक पल के लिए विधायक पाठक भी दंग रह गए कि कैसे कोई गरीब की जमीन हड़पने के लिए इस तरह की जालसाजी कर सकता है।

मप्र में सत्ता और संगठन में बदलाव के तमाम कयासों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि शाह ने यह संकेत भी दे दिया है कि मप्र में विधानसभा चुनाव का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा।

मप्र पर शाह का कंट्रोल

विजय संकल्प यात्रा शुरू करेगी भाजपा

प्रदेश में सियासी माहौल भाजपामय बनाने के लिए अमित शाह ने बैठक में विजय संकल्प यात्रा निकालने को हरी झंडी दे दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि अमित शाह ने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। मप्र में विजय संकल्प यात्रा का खाका भी तैयार कर लिया है। सूत्रों की मानें तो भाजपा राज्य के छह पॉलिटिकल क्षेत्रों से विजय यात्रा शुरू कर सकती है। प्रदेश के मालवा-निमाड़, चंबल-ग्वालियर, बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र से भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकालने का रोडमैप तैयार किया है। इन सभी अलग-अलग क्षेत्रों में भाजपा के बड़े नेता यात्रा में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा की कमान संभाल सकते हैं।

मप्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 11 जुलाई को भोपाल में भाजपा के कोर ग्रुप नेताओं के साथ बैठक की। करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने चुनावी जंग फतह करने की रूपरेखा बनाई। बैठक के पहले, बैठक के दौरान और बैठक के बाद जो संदेश निकला उससे साफ हो गया है कि मप्र में चुनाव का पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा। वहीं चुनावी मैदान में पांच चेहरे अहम भूमिका निभाएंगे। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत अन्य नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बैठक के दौरान अमित शाह ने मप्र चुनाव से जुड़ी कमेटियां बनाने पर भी विचार-विमर्श किया। चुनाव प्रबंधन कमेटी, मेनिफेस्टो कमेटी बनाने पर भी सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं को मप्र चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिनमें उन्हें अलग-अलग कमेटियों में जगह देने की रणनीति है।

मप्र की चुनावी कमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। इसके साथ ही संदेश दे दिया गया है कि प्रभारी भूपेंद्र चौधरी और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ही विधानसभा चुनाव के पावर सेंटर होंगे। अमित शाह ने राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों की तैयारियों का जायजा लिया। राज्य की 150 सीटों पर खास फोकस करने की रणनीति बनाई है। इन सीटों पर पार्टी ने अभी तक क्या काम किया है और विपक्ष ने क्या तैयारी की है, इस पर मंथन किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से फीडबैक लेकर अमित शाह भोपाल दौरे पर आए थे। इसलिए उन्होंने हर एक पहलू पर बात की। राज्य की सभी सीटों पर मंथन किया। इस दौरान राज्य की कमजोर और मजबूत सीटों को लेकर अमित शाह ने अलग-अलग रणनीति बनाने की बात कही है। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बैठाने की भी बात अमित शाह ने कही है। जमीनी स्तर पर मजबूती और आक्रामकता के साथ कांग्रेस की रणनीति को काउंटर करने के दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया, जिसमें समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दे पर बात हुई। अमित शाह के साथ बैठक में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे।

आखिरकार साल की शुरुआत से बार-बार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के कयास और संभावनाओं पर गृहमंत्री अमित शाह ने फुल स्टॉप लगा ही दिया। उन्होंने बंद कमरे में प्रदेश के सभी नेताओं को इशारों ही इशारों में कह दिया कि प्रदेश में बार-बार इस तरह की बातें सामने नहीं आना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। इसका असर पार्टी की

गतिविधियों पर पड़ता है और कार्यकर्ता भी भ्रम में रहता है कि वह क्या करें और क्या न करें। अमित शाह करीब 3 घंटे तक भोपाल में रहे। उनके जाने के बाद प्रदेश में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मंत्रियों तथा प्रदेश के पदाधिकारियों के फोन घनघनाने लगे कि आखिर हुआ क्या? अभी तक जो जानकारी सामने निकलकर आ रही है, उससे यही संदेश जा रहा है कि प्रदेश में अब नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। व्यावहारिक तौर पर भी केंद्रीय संगठन अब इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की गतिविधि तेज हो गई है और जुलाई मिलाकर मात्र 4 महीने का समय ही चुनाव में बचा है। नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे और प्रदेश में नई सरकार 6 जनवरी के पहले शपथ ले लेगी, क्योंकि इसी दिन पुरानी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। शाह न केवल अटकलों पर विराम लगाकर गए, बल्कि नेताओं को भी चेतावनी दे गए हैं कि अब किसी प्रकार की भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित नहीं करें और पार्टी की मजबूती पर ध्यान दें। जिन नेताओं में आपस में मतभेद हैं वे इसे भुलाकर चुनाव की तैयारियों में लग जाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लोगों को दिलाया है, उनको भी साथ लेकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं। प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जरूर बड़ी जवाबदारी सौंपी जाना है, जिसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा की भी नई भूमिका तय होने वाली है। कुल मिलाकर शाह का दौरा इसलिए ही था कि मप्र में चुनाव सिर पर होने के बावजूद सिर फुटौव्वल होने लगी थी और इसके दुष्परिणाम चुनाव में सामने आ सकते थे। प्रदेश का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है, इसलिए भी केंद्रीय नेतृत्व अब संगठन को लेकर संवेदनशील है। यह तो तय हो गया कि प्रदेश संगठन में आने वाले समय में कई नवाचार और राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा।

अमित शाह ने बैठक में साफ संदेश दिया कि मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव तक प्रदेश

चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ही पॉवर सेंटर होंगे। मप्र की चुनावी तैयारी, अभियान, प्रबंधन के साथ अन्य मामलों में यादव और वैष्णव ही समन्वय करेंगे और दिल्ली से संपर्क में रहेंगे। यादव और वैष्णव एक सप्ताह के अंदर फिर मप्र आ सकते हैं। शाह का भी 30 जुलाई को आना तय हो गया है। बैठक के दौरान यादव और वैष्णव शाह के अगल-बगल ही बैठे। बाद में भी दोनों शाह के साथ ही वापस गए। साफ है कि दोनों अब मप्र में डेरा जमाएंगे। इससे पहले शाह ने मप्र के नेताओं से अलग-अलग मुद्दों पर बात की। बैठक में चुनाव अभियान समिति, प्रबंध कमेटी और मेनिफेस्टो के साथ अन्य कमेटियों पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इनकी घोषणा जल्द होगी। मप्र भाजपा के नेताओं के साथ बैठक में शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव का प्रमुख कार्य भूपेंद्र यादव ही देखेंगे। मप्र के नेताओं के बीच समन्वय का काम भी करेंगे। शाह ने भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को एक प्रारूप भी दिया है। इस प्रारूप के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बताया गया कि शाह ने बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अब तक की चुनावी तैयारी को लेकर समीक्षा की। बैठक में बाहरी राज्यों से आए विस्तारकों की रिपोर्ट पर भी मंथन हुआ। शाह के नेतृत्व में बैठक में तय हुआ है कि आने वाले चुनाव में भाजपा किन मुद्दों और किस अंदाज में जनता के बीच जाएगी। शाह कई तरह के फीडबैक पहले ही हासिल कर चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के नेताओं से भी स्थानीय मसलों पर बातचीत की है। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी जल्द ही मप्र के प्रवास पर निकलेंगे। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान वे नाराज नेताओं को भी समय देंगे।

● **जितेंद्र तिवारी**

आदिवासी वोटों पर भाजपा का फोकस

अमित शाह की बैठक में साफ तौर पर भाजपा नेताओं को संदेश दे दिया गया है कि आदिवासी समुदाय के वोटों पर खासतौर पर फोकस किया जाए। राज्य में करीब 21 फीसदी आदिवासी समुदाय की आबादी है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में भाजपा आदिवासी वोटों को साधकर चुनावी जंग फतह करने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों की मानें तो अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य में आदिवासी समुदाय के बीच पूरी ताकत के साथ काम किया जाना चाहिए। साथ ही आदिवासी समुदाय के मामले सामने आने पर भी सवाल उठाया। बैठक के दौरान शाह ने कहा कि मप्र में आदिवासी वोट पर पूरी ताकत से काम किया जाना चाहिए। फीडबैक के मुताबिक आरक्षित 47 सीटों के साथ यह 80 से ज्यादा सीटों पर प्रभावी हैं। शाह ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 10 मिनट अलग से बात की। यादव और वैष्णव भी इस दौरान थे। शाह ने पूछा कि आदिवासियों को लेकर मप्र में लगातार मामले क्यों सामने आ रहे हैं? यह ठीक नहीं है। शाह की बैठक में तालमेल और आक्रामकता की कमी, वर्कर की नाराजगी, नेताओं के अनबन और जमीन तक संगठन की जमावट जैसे मामलों पर चर्चा की बात सामने आई। शाह ने कहा कि ताकत के साथ मैदान में उतर जाओ। चुनावी चौसर जम चुकी है। सूत्रों की मानें तो शाह पूरे फीडबैक के साथ भोपाल आए थे। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों तीन तलाक, समान नागरिक संहिता से जुड़ी चर्चा भी की।

सरकार का चुनावी निर्माण पर फोकस

मप्र में चुनावी साल होने के कारण सरकार का फोकस सबसे अधिक उन योजनाओं और कार्यों पर है, जिसका जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने सड़कों जैसे चुनावी निर्माण के कार्यों पर सबसे अधिक फोकस किया है। इन योजनाओं के लिए फंड की कमी न हो इसके लिए कई विभागों के फंड पर पहरा बैठा दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने 9 विभागों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। निर्धारित किए गए बजट के आहरण पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि चुनावी वर्ष में सरकार का सबसे अधिक फोकस सड़क और अन्य अधोसंरचना के निर्माण पर होता है। इसलिए वित्त विभाग ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्कूल शिक्षा सहित 9 विभागों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। निर्धारित किए गए बजट के आहरण पर रोक लगाई गई है। एक लिस्ट 31 मार्च को जारी हुई थी जिसे अपडेट किया गया है। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना पैसा खर्चा नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव की दस्तक का असर ऐसा है कि चुनावी गणित वाली योजनाओं में तो भरपूर पैसा है, लेकिन बाकी अधोसंरचना संबंधित कामों को लेकर धीरे-धीरे ब्रेक लगने लगे हैं। लाड़ली बहना जैसी योजनाओं को फोकस पर लेने से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य काम पीछे हो रहे हैं। बजट की दिक्कतों के कारण ही सरकार को पहला अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है। सरकार कर्ज, निराश्रित निधि सहित अन्य मदों के जरिए चुनावी बोझ उठाते हुए बाकी कामों की रफ्तार बनाए रखने के जतन कर रही है, लेकिन कई जगह आने लगी हैं। बड़े दीर्घकालीन प्रोजेक्ट फिलहाल प्राथमिकता से पीछे हो गए हैं। सड़कों की मरम्मत को पिछले दिनों कायाकल्प अभियान से पैसा देना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के निर्माण पर असर पड़ा है। छह महीने से नए बजट आवंटन में कमी आई है। मार्च 2024 में नर्मदा के पानी का उपयोग करने की समयसीमा खत्म हो रही है। दूसरी ओर जिलों के मुख्य मार्गों के निर्माण में बजट की दिक्कत है। विधानसभावार सड़क निर्माण के लक्ष्य के चलते इंटर कनेक्ट सड़कों का काम प्रभावित हुआ है। स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। आंगनबाड़ियों, शाला भवनों का निर्माण, पुल-पुलिया, सीवेज प्रोजेक्ट सहित अन्य कामों पर असर पड़ा है।

जानकारी के अनुसार चुनावी वर्ष में सरकार ने जिन योजनाओं और कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की योजना बनाई है उसके तहत लाड़ली बहना योजना में अभी 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल-इंदौर मेट्रो के एक रूट को अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है। नल-जल मिशन के तहत पैसा दिया जा रहा है। मार्च 2024 तक समयसीमा है। सीखो कमाओ योजना के तहत बजट प्रावधान किया गया है। संविदा कर्मियों को सुविधाएं, कर्मचारी डीए वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका सहित चुनिंदा वर्ग की वेतन वृद्धि, मानदेय के लिए बजट प्राथमिकता में हैं। हर महीने औसत 10-12 बड़े कार्यक्रम हो रहे है, विभागों के लिए यह प्राथमिकता पर हैं। साथ ही जिन कामों को पेंडिंग में रखा गया है उनमें 10 हजार किमी से ज्यादा सड़कों का निर्माण, 25573 आंगनबाड़ी किराए के भवनों में, 8 हजार निर्माण, 20 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े सीवेज के काम, 12 से ज्यादा छोटे-मध्यम बांध प्रोजेक्ट जिन पर आर्थिक असर पड़ेगा।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

इन विभागों पर वित्तीय प्रतिबंध

सरकार ने जिन विभागों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाया है उनमें स्कूल शिक्षा विभाग में हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में फर्नीचर, प्रयोगशाला, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुदान, मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास, नवभारत साक्षरता अभियान एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण पर होने वाले खर्च पर रोक लगाई गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नई स्टेशनरी की खरीदी, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, प्रयोगशाला का उन्नयन, सरकारी कॉलेजों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प प्रोजेक्ट, स्ट्राइव योजना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार कमियों की पूर्ति, विभागीय परिसंपत्तियों के मेंटेनेंस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, हाउसिंग फॉर ऑल वैट क्षतिपूर्ति, स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान, वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, 2.0 स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन विभाग में पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए अनुदान, पर्यटन नीति का क्रियान्वयन पर्यावरण-एप्को को अनुदान, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में निवेश प्रोत्साहन योजना। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और संस्कृति विभाग में मप्र संस्कृति परिषद, समारोह के आयोजन के लिए अनुदान पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर सचिव एवं बजट संचालक आइरिन सिंथिया जेपी की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि विभागों एवं योजनाओं के लिए प्रावधान इस राशि का आहरण वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। संबंधित विभागों के अधिकारी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का आहरण नहीं करेंगे। वित्त विभाग से जारी सर्कुलर में इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है।

कब रुकेगा मौत का तांडव?

भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगभग डेढ़ महीने से सुलगने के उपरांत पुलिस तथा सेना की माहौल में सुधार की कोशिश व्यर्थ गई। लाख कोशिशों के उपरांत भी कुकी, नगा और मेइती समुदाय के उग्र लोग हिंसात्मक हैं। सरकार के लिए अब यह हिंसा सिरदर्द बन चुकी है। सरकार का शांति बहाली दावा सही साबित नहीं हुआ। शिविरों में रहने को मजबूर 50,000 से अधिक लोग बेघर हैं। शांति की खबरों और कोशिशों के बीच मणिपुर की राजधानी इंफाल में पश्चिमी जिले के एक गांव में 9 मई को एक महिला समेत तीन लोगों की हत्या और अब 11 लोगों की हत्या ने माहौल फिर खराब कर दिया है। हिंसा में उग्रवादियों की एंट्री हो चुकी है। दुविधा यह है कि उग्रवादी सुरक्षाकर्मियों के भेष आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं। खामेनलोक क्षेत्र में उग्रवादियों के हमले से लोग खौफ में हैं।

विदित हो कि मणिपुर में मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगें जाने के विरोध में कुकी तथा नगा समुदायों ने 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के बैनर तले निकाला था, जिसके विरोध में मणिपुर में मेइती हिंदू तथा आदिवासी कुकी, जो कि ईसाई हैं, एवं नगा समुदाय, जो कि कुकी समुदाय के साथ हैं, के बीच के बाद यह हिंसा भड़की थी। यह मार्च उच्च न्यायालय के 27 मार्च के उस फैसले के विरूद्ध निकाला जा रहा था, जिसमें न्यायालय ने राज्य को ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। 3 मई से भड़की इस हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तथा 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। विदित हो कि मणिपुर में उग्रवाद एक पुरानी समस्या है, जिसकी जड़ें कथित रूप से राजनीति में भी बहुत गहरी हैं। ऐसे में अगर तीन जातियों की हिंसक झड़पों में अगर उग्रवादी शामिल हो चुके हैं, तो मणिपुर सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी इसे रोकना अब आसान नहीं होगा। हालांकि मणिपुर में पहले के मुकाबले कर्फ्यू के चलते काफी शांति है, परंतु सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है तथा न जल्दी हालात सामान्य होने के संकेत हैं। इसकी वजह यह है कि हिंसा अब केवल जातिवाद और आरक्षण तक सीमित नहीं रही, वरन् क्षेत्रीयता तथा वर्चस्व की लड़ाई तक पहुंच चुकी है, जिसे लगातार छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू की सरकार की लापरवाही इतनी बड़ी हिंसा के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार मानी जानी चाहिए।

अब हाल यह है कि हिंसा में अधिकारियों तथा नेताओं को भी अपना खतरा बना हुआ है। असम राइफल्स, पुलिस, सीआरपीएफ तथा सुरक्षा एजेंसियां हिंसा रोकने का भरसक प्रयास कर रही हैं। हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। एसआईटी बन चुकी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में एक शांति समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कई मंत्री, कुछ सांसद, कुछ विधायक, वहां सक्रिय राजनीतिक दलों के नेता, कुछ विश्वसनीय अधिकारी, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर हिंसा पर नजर रखे हुए हैं। वह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह तथा अधिकारियों, मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लेकिन उनके दौरे के बाद हिंसा भड़कना आश्चर्यजनक है। प्रश्न यह है कि क्या केंद्र सरकार का सीधा दखल इस हिंसा को शांत करा पाएगा? यह प्रश्न इसलिए भी है, क्योंकि उग्रवादियों का हिंसा में कूदना इस हिंसा के शांत होने को लेकर शंका पैदा करता है। मुश्किल यह है कि गृहमंत्री अमित शाह के दखल से भी यहां की हिंसा में शामिल समुदाय, विशेषकर कुकी समुदाय नाराज है तथा अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पिछले दिनों इस समुदाय ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। कुकी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान हाथों में तख्तियां ली हुई थीं, जिन पर लिखा था- कुकी समुदाय के लोगों के जीवन की रक्षा करें। बाद में ये प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर भी बैठे थे। हिंसा रोकने के लिए मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार इंटरनेट सेवाएं 3 मई से बंद की हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ याचिका की तत्काल लिस्टिंग से इनकार करते हुए कहा कि मामला उच्च न्यायालय के पास है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

मेइती समुदाय दिख रहा उग्र

देखने में आ रहा है कि सेना के डर से लोग भले ही घरों में कैद हैं, परंतु अभी भी मेइती समुदाय उग्र दिख रहा है। हिंसा में बड़ी बात यही है कि सबसे पहले मेइती समुदाय के लोग ही उग्रता पर उतरे तथा इस समुदाय के लोगों ने आदिवासी एकता मार्च पर हमला किया। सवाल यह है कि मेइती समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों पाना चाहता है? मणिपुर के आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि उनको मिले आरक्षण तथा उनके अधिकार क्षेत्र की प्राकृतिक चीजों पर कब्जें की यह साजिश है और सरकार इस साजिश में शामिल है। हालात यह हैं कि उग्रवादी संगठन इस हिंसा को शांत नहीं होने देना चाहते। जानकार मान रहे हैं कि उग्रवादी संगठनों का हिंसा में कूदना सरकार के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। उग्रवादी संगठन हिंसा को बढ़ावा देंगे तथा विरोधी पक्ष के सामान्य लोगों को मौत के घाट उतारने से नहीं चूकेंगे। शांति बहाली की कोशिश तथा कड़ी निगरानी के बीच तीन लोगों की हत्या यह साबित कर चुकी है। संवेदनशील क्षेत्रों के जिन लोगों को सरकार ने विस्थापित कर दिया है, उनके वापस अपने घर लौटने की संभावनाएं फिलहाल नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय हिंसा प्रभावित मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मंजूरी दे चुका है। हालांकि राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का यह दावा है कि मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण है तथा नियंत्रण में है, गलत साबित हुआ। कांग्रेस का कहना है कि सरकार हिंसा रोकने में नाकाम साबित हुई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश दरकिनार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी घोषणाएं करते हैं या निर्देश देते हैं, उसका सभी विभाग तत्परता से पालन करते हैं, लेकिन इन विभागों में एक विभाग ऐसा भी है, जो सीएम के निर्देश दरकिनार कर देता है। वह विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। यह वह विभाग है जिसके मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विडंबना यह देखिए कि यह विभाग उनके निर्देशों का पालन करने में हमेशा कोताही बरतता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं और निर्देशों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर भी नहीं मानते हैं। जबकि मुख्यमंत्री खुद इस विभाग के मंत्री हैं। इसका असर यह हो रहा है कि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की मनमानी महिला एवं बाल विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। इससे आईसीपीएस यानी मिशन या अमला भी अछूता नहीं है। मामले में विभागीय जिम्मेदारों का रवैया इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 16 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, लेकिन उसका लाभ महिला एवं बाल विकास के संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। आश्चर्य यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद बाल संरक्षण योजना क्रियान्वयन से जुड़े इस अमले का अब तक कैडर निर्धारित करने की जरूरत नहीं समझी है। जबकि यह कर्मचारी बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार और मप्र सरकार द्वारा संचालित बाल संरक्षण योजना की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बावजूद इसके विभागीय जिम्मेदारों ने संविदा नीति 2018 के माध्यम से मिलने वाले 90 प्रतिशत वेतन से जहां इनको लाभांवित करने की जरूरत नहीं समझी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से की गई बढ़ोत्तरी से भी जानबूझकर वंचित किया गया है।

एक तरफ मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों को दूसरे विभाग लागू कर चुके हैं, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के उपसचिव अजय कंटेसरिया ने 19 मई 2023 आदेश में शामिल इस 5वें बिंदु पर यह टीप लगाते हुए अडंगा लगा दिया है कि मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा पृथक से विचार किया जाएगा। बावजूद इसके विभाग इस विषय पर अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। बताया जाता है कि निर्णय की प्रत्याशा में 25-26 जिलों ने बढ़ा हुआ वेतन दे दिया, लेकिन जिन जिलों के परियोजना अधिकारियों ने मिशन वात्सल्य के अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया, उनको यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बढ़े वेतन का इंतजार कर रहे करीब 250 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग भले ही एक है पर कर्मचारियों को राज्य सरकार की संविदा नीति का लाभ देने के मामले में इसके मापदंड अलग-अलग हैं। समेकित बाल संरक्षण कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव दिनेश लोहिया की मानें तो महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को 90 प्रतिशत वेतन एवं ईपीएफ देने का आदेश महीनों पहले जारी किया जा चुका हैं। समाजसेवा व राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के मानदेय में भी व्यापक बढ़ोतरी की जा चुकी है। बावजूद इसके कई बार ज्ञापन सौंपने और अधिकारियों से व्यक्तिगत मिलकर मांग रखने के बाद भी इसे संज्ञान में नहीं लिया गया। इस दोहरे व्यवहार से भी आईसीपीएस के अधिकारी-कर्मचारियों में निराशा है।

● **राकेश ग्रोवर**

कैसे मिलेगा 100 प्रतिशत तक वेतन का लाभ

हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव पूर्व संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को 100 प्रतिशत तक वेतन देने सहित कई घोषणाएं की है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस घोषणा का लाभ भी आईसीपीएस अधिकारी-कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि विभाग ने इसके पहले इनको संविदा नीति 2018 के तहत 90 प्रतिशत का लाभ नहीं मिला है। बता दें कि अभी स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पाठ्यपुस्तक निगम, जल संसाधन और लोक निर्माण जैसे विभाग कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की मंशानुसार संविदा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 9 वर्ष की सेवा के बाद भी सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ से वंचित संविदा कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अंधेरे में रखा है। यदि विभागीय अधिकारियों को संविदा कर्मचारियों की चिंता होती तो इस विषय पर मुख्यमंत्री से जरूर चर्चा करते, लेकिन नहीं की। नहीं तो मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री अब तक समस्या का समाधान कर चुके होते। केंद्र प्रवर्तित इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 676 पद सृजित कर व्यापमं के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की थी। अमले के प्रति असंवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारी-कर्मचारियों ने विभाग से ही किनारा करना शुरू कर दिया। इसके चलते इनकी संख्या करीब 350 ही रह गई है। जबकि इसके पहले विभाग व्यापमं के माध्यम से दोबारा इन पदों को भरने की कोशिश कर चुका है और पटवारी परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद से ही यहां फिर भगदड़ मच गई है।

वेंटिलेटर पर आयुष्मान

मप्र में 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई केंद्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना वेंटिलेटर पर आ गई है। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने वाली इस योजना में अब तक महज 7 फीसदी हितग्राहियों को ही मुफ्त उपचार मिल पाया है। इतना ही नहीं प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा 3.55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। इधर, योजना को समझने और उसे लागू करवाने में वरिष्ठ अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति यह है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के अधीक्षकों को तो योजना की ठीक-ठीक जानकारी ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को बिना कार्ड के इलाज देने से ही इनकार कर दिया जाता है, जबकि नियमानुसार हितग्राही मरीज का इलाज कार्ड बनने के पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे मरीजों का कार्ड भी आधे घंटे में बन जाना चाहिए, क्योंकि हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र नियुक्त किया गया है। इसके बाद भी मरीजों को कार्ड के लिए दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान योजना निर्धन और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बीमार होने पर निजी और सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है।

केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के आंकड़ों को देखें तो मप्र, उप्र सहित कई राज्य इलाज प्रदान करने में पीछे रहे हैं। इन राज्यों में 5 साल में इस योजना के तहत अस्पताल में इलाज का औसत 7 प्रतिशत रहा है। जबकि मप्र में 5 सालों में सबसे ज्यादा 3.55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। इलाज का खर्च लगभग 4000 करोड़ रहा। दूसरी ओर साउथ के राज्यों सहित कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 20 से 25 प्रतिशत ही रहा है। सालाना आधार पर यह दर और भी कम है। जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल को-ऑर्डिनेटर अमूल्य निधि का कहना है कि मप्र, उप्र जैसे राज्यों में योजना का क्रियान्वयन निश्चित ही अच्छा नहीं रहा। योजना आने पर पहली बार इलाज के रेट्स पर नियंत्रण हुआ। इतने कार्ड पर इलाज नहीं हुआ तो क्या फर्जी कार्ड बने थे, ये जांच का विषय है।

अगर आयुष्मान भारत योजना के आंकड़ों को देखें तो मप्र की आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। आयुष्मान भारत (मप्र) के जनरल मैनेजर ओपी तिवारी ने कहा कि योजना के तहत पात्र परिवार 1.08 करोड़ हैं। मेडिकल आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. विवेक पांडेय ने कहा कि इतने कार्ड देखकर फर्जी कार्ड की संभावना जांचने के लिए बड़ी जांच की जरूरत है। मप्र में आयुष्मान घोटाला भी हो चुका है। रिटायर्ड हेल्थ डायरेक्टर केके ठस्सू के मुताबिक मप्र में बड़े शहरों के अलावा इमपेनल्ड हॉस्पिटल्स का नेटवर्क छोटी जगहों में नगण्य है। यह वजह हो सकती है कि गंभीर न होने पर लोग स्थानीय स्तर पर इलाज करा लें। साउथ में हेल्थ नेटवर्क अच्छा है। कई अधिकारियों ने माना कि योजना में इलाज के रेट फिक्स होने से निजी अस्पतालों को दिक्कत रही है। पेमेंट अटकने का भी इश्यू रहा है।

गौरतलब है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध 120 निजी अस्पतालों का बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के ख्यातिप्राप्त निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इन निजी अस्पतालों पर अर्थदंड लगाकर वसूली कर रहा है। बता दें कि आष्युमान योजना के अंतर्गत कुल 620 निजी अस्पतालों को तीन साल (वर्ष 2019 से जुलाई 2022 तक) में 1048 करोड़ 98 लाख 19 हजार 481 रुपयों का भुगतान किया गया है। जांच में कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई अस्पतालों में खुद के कर्मचारियों के नाम आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए थे और उन्हें मरीज बनाकर रकम निकाल ली गई। इसी तरह किसी मरीज का बिल 50 हजार का बना तो उसे बढ़ाकर दो लाख रुपए की राशि सरकार से वसूल ली जाती थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान कार्डधारियों को अस्पताल लाने के लिए जगह-जगह एजेंट नियुक्त किए गए थे। कुछ अस्पतालों ने इन्हें जनसंपर्क अधिकारी का पदनाम दे दिया था। बिलिंग की राशि में बढ़ोतरी का खेल जांच के नाम पर किया जाता था। महंगी-महंगी जांच के नाम पर बिल बना लिए जाते थे।

● **लोकेंद्र शर्मा**

निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार के लिए अनुबंधित अस्पतालों की पहली बार ग्रेडिंग तैयार की जा रही है। उनकी स्टार रेटिंग की जाएगी। विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन के बाद अस्पतालों को एक से लेकर पांच तक स्टार दिए जाएंगे। जिसे पांच स्टार मिलेंगे वह सबसे अच्छा माना जाएगा। आयुष्मान योजना में देश में पहली बार इस तरह की ग्रेडिंग की जा रही है। इसका बड़ा लाभ रोगियों को होगा। जिस अस्पताल की रेटिंग अच्छी होगी वह रोगियों के उपचार के लिए बेहतर हो सकता है। उन्हें हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। अच्छी रेटिंग वाले अस्पताल को दावा राशि का आधा हिस्सा बिल पेश करने के दिन ही देने की तैयारी है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले। उधर, जिन अस्पतालों की रैकिंग अच्छी नहीं रहेगी उन्हें सुधार के लिए कहा जाएगा। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं, अस्पतालों के विरूद्ध शिकायत, रोगियों से मिले फीडबैक (प्रतिक्रिया) आदि बिंदुओं पर अस्पताल का मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पिछले दो वर्ष में कई कुछ अस्पतालों के विरूद्ध उपचार में लापरवाही, रोगी से निर्धारित पैकेज से ज्यादा राशि लेने, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद निर्धारित समय तक निशुल्क फॉलोअप नहीं करने की शिकायतें ज्यादा आई हैं। ऐसे में रोगी या उसके स्वजन भी यह निर्णय लेने में दुविधा में रहते हैं कि कौन से अस्पताल में उपचार कराना चाहिए। सरकार की इस व्यवस्था से उन्हें आसानी हो जाएगी। उपचार के लिए अस्पतालों को मिलने वाले पैकेज में रेटिंग के आधार पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रेटिंग निर्धारित करने का उद्देश्य बेहतर काम करने वाले अस्पतालों को प्रोत्साहित करना और जिनका काम अपेक्षाकृत कम अच्छा है उनमें सुधार कराना है।

कूनो में क्षमता से अधिक चीते

कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की अलग-अलग कारणों से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कूनों में क्षमता से अधिक चीते होने के कारण इनमें आपसी संघर्ष बढ़ रहा है। गौरतलब हैं कि साल 2022 के शरद ऋतु और 2023 के सर्दियों में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाकर भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ताकि 70 साल पहले भारत से विलुप्त होने के बाद इन्हें फिर से स्थापित किया जा सके। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना कि यह सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसे ठीक से हासिल करना इतना आसान नहीं है। नामीबिया में लीबनिज-आईजेडडब्ल्यू के चीता अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिक इनके फिर से स्थापित करने की योजना में कमियां होने की बात कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका में, चीते काफी बड़े इलाकों में फैले हुए हैं और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में एक से भी कम चीता रहता है।

कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बनाई गई योजना में माना गया है कि अधिक शिकार, चीतों को बनाए रखेगा, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चीतों की अधिक संख्या शिकार की अधिक संख्या पर निर्भर करती है। शोध टीम ने कहा, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान छोटा है, इसलिए इस बात की आशंका अधिक है कि छोड़े गए जानवर पार्क की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाएंगे और पड़ोसी गांवों के लोगों के साथ इनका संघर्ष हो सकता है। एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस), विश्व स्तर पर लुप्तप्राय चीता की एक उप-प्रजाति है। यह 70 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहती थी, उसके बाद यह विलुप्त हो गई।

सितंबर 2022 और फरवरी 2023 में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से एसिनोनिक्स जुबेटस-जुबेटस उप-प्रजाति के कुल 20 चीतों को भारत के मप्र राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। जिसे भारत में इन बिल्लियों की एक नई आबादी के पहले केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान लगभग 17 गुणा 44 किलोमीटर (लगभग 750 वर्ग किमी) का एक बिना बाड़ वाला जंगली इलाका है। स्थानीय शिकार की संख्या के आधार पर, गणना की गई कि कूनो नेशनल पार्क में 21 वयस्क चीतों को रखा जा सकता है। जो कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग तीन चीतों के घनत्व के बराबर का इलाका है।

नामीबिया में चीतों के स्थानीय व्यवहार पर लंबे समय तक अध्ययन तथा शोध किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी जगह पर क्षमता से अधिक चीतों को नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही पूर्वी अफ्रीका में तुलनात्मक शोध के आधार पर, लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्डलाइफ रिसर्च (लीबनिज-आईजेडडब्ल्यू) के वैज्ञानिक भी पार्क में जरूरत से ज्यादा चीतों को रखने के खिलाफ हैं। जीव वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राकृतिक परिस्थितियों में आमतौर पर प्रति 100 वर्ग किमी में एक वयस्क चीता रहता है। यह न केवल नामीबिया के लिए सच है, बल्कि पूर्वी अफ्रीका में सेरेन्गेटी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक रूप से बहुत अलग-अलग स्थितियों के लिए भी सही है, जहां शिकार का घनत्व बहुत अधिक है।

इस परिप्रेक्ष्य को लेकर, टीम ने नए निवास स्थान में चीतों के स्थानीय व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाया, विवादास्पद मुद्दों की पहचान की और दोबारा उन जगहों पर उन्हें स्थापित करने की योजना की छिपी हुई मूल धारणाओं की पहचान की गई। शोध के मुताबिक ये मान्यताएं चीता की सामाजिक-स्थानिक प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करती हैं। नर चीते दो अलग-अलग स्थानीय तरीकों को अपनाते हैं। नर आमतौर पर अपने इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। जबकि यहां मौजूदा नर बिना कब्जा किए इलाकों में घूमते रहते हैं, जैसा कि अक्सर मादाएं करती हैं। ये नर पहचानी गई जगहों को लेकर कभी-कभार दूसरों पर आक्रमण भी करते हैं। चीता रिसर्च प्रोजेक्ट के डॉ. जॉर्ग मेल्जाइमर कहते हैं, चीतों के इलाके एक-दूसरे की सीमा से सटे नहीं होते हैं, वे हमेशा एक-दूसरे से लगभग 20 से 23 किलोमीटर दूर होते हैं। इलाकों के बीच की जगह का किसी भी नर द्वारा बचाव नहीं किया जाता है, यह बिना इलाके वाले नर जिसे फ्लोटर्स कहते हैं और मादाओं के लिए रहने और गुजरने की जगह होती है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

नामीबिया में इलाके बड़े और शिकार का घनत्व कम

मप्र में इसी महीने 2 चीतों की मौत हो चुकी है। चीता रिसर्च प्रोजेक्ट से डॉ. बेटिना वाचर कहते हैं, यह दूरी शिकार के आधार के वास्तविक आकार से स्वतंत्र है। नामीबिया में, इलाके बड़े हैं और शिकार का घनत्व कम है, पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्र छोटे हैं और शिकार का घनत्व अधिक है। लेकिन प्रदेशों के बीच की दूरी स्थिर है और बीच में कोई नया क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है। जबकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से स्थापित करने की योजना के तहत, इन दूरियों को नजरअंदाज किया गया है। वाचर, मेल्जाइमर और उनकी टीम ने कहा कि साल 2022 की शरद ऋतु में नामीबिया से लाए गए चीते, जिनमें तीन नर भी शामिल थे, इनके चलते पहले ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान की वहन करने की क्षमता पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में स्थापित उनके क्षेत्रों के आकार के बावजूद, तीन नामीबिया के नरों ने पूरे राष्ट्रीय उद्यान पर कब्जा कर लिया होगा, जिससे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भेजे गए अतिरिक्त चीतों के लिए वहां कोई जगह नहीं बची है। वैज्ञानिकों ने कहा है, इसलिए हमारा अनुमान हैं कि चीते राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी पाए जा सकते हैं और पार्क के आसपास के किसानों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। उनकी स्थानीय प्रणाली को स्थापित करने की प्रक्रिया में शायद कई महीने लगेंगे और इससे पार्क के बाहर इनके द्वारा कब्जा किया जाएगा, यही वजह है कि फ्लोटर्स और मादा अक्सर पार्क के बाहर भी पाए जाते हैं। वर्तमान शोध के निष्कर्षों के आधार पर, टीम ने सिफारिश की है कि भविष्य में भारत में चीतों के दोबारा स्थापित की जाने वाली प्रजातियों के स्थानीय संगठन को ध्यान में रखा जाए। यह सक्रिय रूप से संघर्षों को हल करने में मदद करेगा और दोबारा स्थापित किए जाने के बाद चीता प्रादेशिक प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में अहम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

बुंदेलखंड को साधने का जतन

मप्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अपने सबसे कमजोर इलाकों में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र पर खास नजर है। यही कारण है कि पार्टी के तमाम नेताओं की सक्रियता इस इलाके में बढ़ रही है। बुंदेलखंड राज्य का वह इलाका है, जिसमें विधानसभा की 230 सीटों में से 29 सीटें आती हैं। इस समय इनमें से 19 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। आठ स्थानों पर कांग्रेस के विधायक हैं और सपा-बसपा के पास एक-एक सीट है। कुल मिलाकर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा मजबूत स्थिति में है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में कभी कांग्रेस के पास कद्दावर नेता के तौर पर सत्यव्रत चतुर्वेदी हुआ करते थे, मगर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने राजनीति से पूरी तरह किनारा कर लिया है। इस क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। दूसरी ओर, इस इलाके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सांसद हैं तो प्रहलाद पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। उमा भारती भी इसी क्षेत्र से आती हैं। इसके अलावा, शिवराज सरकार में पांच प्रमुख मंत्री इस इलाके से आते हैं। कांग्रेस इस इलाके में आगामी चुनाव में बढ़त हासिल करना चाहती है, लिहाजा उसके नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उन इलाकों का दौरा कर गए हैं, जिन सीटों पर कांग्रेस कई बार से हार रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। यादव पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी इस इलाके में काफी है। वे इस इलाके का बीते एक माह में दो बार दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम नेताओं के साथ बैठने की, सभाएं की और संवाद भी किया।

मप्र के हिस्से में बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिले आते हैं। सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, छतरपुर और दतिया। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंच गई थी, तब भी उसे इस इलाके में ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। यही वजह है कि अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए इस क्षेत्र पर कांग्रेस की खास नजर है। बुंदेलखंड मप्र का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं बुंदेलखंड में प्रदेश के बाकी इलाकों से ज्यादा हैं। बुंदेलखंड में दिखावे के लिए हर बार चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन मतदान के ठीक पहले जाति वाला मामला हावी होने लगता है। कहते हैं कि बुंदेलखंड में दल से ज्यादा जातियों का जोर रहता है। जातियों में बंटे वोटर अपने-अपने जाति-समाज के कैंडिडेट के साथ खड़े नजर आते हैं। कमोबेश नवंबर 2023 के चुनाव में भी यही सीन रह सकता है। जातीय समीकरणों के चलते इस इलाके में भाजपा और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपनी ताकत दिखाती है। इन दोनों दलों को वोट कटवा भी माना जाता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था।

कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ और संगठन का काम देख रहे दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को ही मुद्दा बनाकर अपने चुनाव अभियान की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं, भाजपा अपनी विकास योजनाओं के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में हैं। बुंदेलखंड पैकेज, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और 45 हजार करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने भी बुंदेलखंड में पार्टी की मजबूती के लिए बड़ा दांव खेला है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी बुंदेलखंड में चुनाव से काफी वक्त पहले ही अपना एग्रेसिव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री कमलनाथ और दिव्या सिंह लगातार बुंदेलखंड के दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वे भाजपा के स्थानीय मंत्रियों और सरकार पर भ्रष्टाचार के सीधे-सीधे आरोप भी लगा रहे हैं। बुंदेलखंड में जीत के लिए कांग्रेस ने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। किस सीट पर कितनी ताकत लगानी है? किन मुद्दों को उछालना है? कहां भाजपा कमजोर है? इसकी व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस क्षेत्र के आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए भी कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन की बातचीत भी अंदरूनी तौर पर चल रही है। कांग्रेस बुंदेलखंड में जातीय समीकरण साधने के साथ ही पिछड़ेपन को भी मुद्दा बना रही है। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के वायदों के साथ धर्म पताका भी लेकर चल रहे हैं। उनके सामने 2018 का परिणाम दोहराने की चुनौती भी है। पिछले महीने उन्होंने संत रविदास जयंती पर दलित वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा गांव चला था। शिवराज ने घोषणा की कि सागर में संत रविदास की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। उनके पास 45 हजार करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना, बुंदेलखंड पैकेज और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जैसे मेगा प्रोजेक्ट बताने के लिए भी हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

विकास की दौड़ में कितना पिछड़ा है बुंदेलखंड

यहां बताते चलें कि विकास की दौड़ में पिछड़े बुंदेलखंड इलाके में विधानसभा की 29 सीटें आती हैं। बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो बुंदेलखंड की 29 सीटों में से 19 में भाजपा और 8 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी एक-एक सीट आई थीं। बाद में कमलनाथ सरकार का तख्तापलट होने के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला ने भाजपा का दामन थाम लिया था, जबकि बसपा की राम बाई अहिरवार ने अंतिम समय में भाजपा खेमे में जाने से इनकार कर दिया था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बुंदेलखंड को मप्र का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहां कुपोषण का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। पानी की कमी के कारण खेती-बाड़ी का भी बुंदेलखंड में बुरा हाल है। उद्योग-धंधे न के बराबर हैं। बेरोजगारी के कारण पलायन भी यहां का बड़ा मुद्दा है।

लोकतंत्र के मंदिर में न कायदा, न कानून

जिस राज्य में मुख्यमंत्री हर मंच से यह कहने से चूकते नहीं हैं कि मप्र मेरा मंदिर है और जनता इसकी भगवान और मैं जनता का सेवक। उस प्रदेश में लोकतंत्र के मंदिर में भगवान की किस कदर उपेक्षा की जाती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में हुए कुल 15 सत्र में 128 बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन उनमें से सदन केवल 128 घंटे ही चल पाया। उस दौरान भी जनहित के मुद्दों की बजाय हंगामे ही होते रहे।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में जब भी विधानसभा का कोई सत्र शुरू होता है, सत्तापक्ष और विपक्ष बड़ी तैयारी के साथ सदन को चलाने के दावे करते हैं, लेकिन हर बार सदन की कार्यवाही कुछ ही दिनों में सिमट जाती है। सत्तापक्ष, विपक्ष पर और विपक्ष, सत्तापक्ष पर सदन न चलने का आरोप मढ़ देता है। लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। माननीयों का इससे कुछ नहीं बिगड़ता है। जहां सरकार की कोशिश रही कि वह इस दौरान सारे विधेयक, अनुपूरक बजट या अन्य काम जल्दी-जल्दी निपटा ले, वहीं विपक्ष हर बात पर हंगामा करने में लगा रहा। हद तो यह कि सारे विधेयक, सारे बिल बिना चर्चा के ही पारित होते गए। यानी इस लोकतंत्र के मंदिर में न कोई कायदा दिखा और न कोई कानून। एक जमाना था जब विधानसभा का एक-एक सत्र 50 से 70 दिन तक चला करता था, लेकिन 15वीं विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मुश्किल से 5 से 7 दिन सत्र चले।

मप्र में जब गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने नियमों के तहत सदन को चलाने का दावा किया था। इस दौरान कई बार उन्होंने कहा था कि 15वीं विधानसभा के बाकी सत्र पूरे दिन चलेंगे। यही नहीं, इन्होंने विधानसभा में कई नवाचार भी किए हैं, जिसे देशभर में सराहना भी मिली है। लेकिन विडंबना यह भी रही है कि इनके नेतृत्व में विधानसभा का एक भी सत्र पूरे समय तक नहीं चल पाया है। इसके लिए भाजपा जहां विपक्षी कांग्रेस को दोष देती है, वहीं विपक्षी भाजपा को। वजह जो भी हो, लेकिन यह तो साफ है कि मप्र विधानसभा में अब जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। सत्तापक्ष और विपक्ष बेवजह के मुद्दों पर हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही कुछ दिनों तक ही जैसे-तैसे चल पाती है। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था। 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया। इन दो दिनों में भी सत्र 4 घंटे ठीक से नहीं चला। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चला। 12 जुलाई को सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। भारी हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 26 हजार 816 करोड़ 63 लाख 87 हजार रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास हुआ। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र था। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग के मामले में जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई।

सदन में जनता की बात नहीं

विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। विधायक चुने जाने वाले नेता ही विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाकर उस पर चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर सरकारें नियम व कानून बनाती है। यहां पर होने वाले सवाल-जवाबों के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था होती है, लेकिन अब प्रदेश में स्थितियां अलहदा होती जा रही हैं। इसकी वजह है विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन हो जाना। प्रदेश की विधानसभा में इसी तरह का कुछ चिंताजनक ट्रेंड बना हुआ है। यही वजह है कि अगर बीते तीन दशकों पर नजर डालें तो प्रदेश विधानसभा में चर्चा के लिए जितना समय माननीय लेते थे, उसमें अब 75 फीसदी तक की कमी आ चुकी है। हद तो यह है कि 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया तो 5 दिन के लिए गया था, लेकिन वह भी 2 दिन में ही समाप्त हो गया। इस दौरान सदन की कार्यवाही महज 2 घंटे 34 मिनट ही चली। इस दौरान विपक्ष ने सीधी पेशाब कांड, आदिवासी अत्याचार, महाकाल लोक घोटाला और सतपुड़ा भवन अग्निकांड के मुद्दों को उठाते हुए चर्चा की मांग की, जिसके चलते सत्तापक्ष व विपक्ष के सदस्य आमने-सामने आ गए थे।

अगर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो कई बार ऐसे भी मौके आए जब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तय समय की सीमा में भी वृद्धि की गई है या फिर देर रात तक कार्यवाही चलती रही है, लेकिन अब ऐसे मौके आने की नौबत ही नहीं आती है। इसकी वजह है अब माननीय सदन में अपनी बात रखने के लिए तर्कों के बजाय हंगामा करने को अधिक महत्व देते नजर आते हैं। इस तरह के हालात 12वीं विधानसभा से बनने शुरू हुए तो वह अब तक जारी है। यही नहीं इसके बाद से तो चर्चा के समय में लगातार गिरावट के हालात बने हुए हैं। इसके पूर्व की कार्रवाई पर नजर डालें तो पहले औसतन हर विधानसभा के कार्यकाल में करीब साढ़े पांच सौ घंटे चर्चा होती थी, जो अब कम होकर औसतन सवा सौ घंटे के आसपास ही रह गई है। 15वीं विधानसभा में तीन सत्रों को छोड़कर चार साल में अन्य कोई भी सत्र (बजट, मानसून और शीतकालीन) अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर सका। यहां तक की बजट सत्र की बैठकें भी समय से पहले ही समाप्त हो गईं। जबकि इस सत्र के सबसे लंबा होने की परंपरा रही है।

सत्र चलाने में किसी की रुचि नहीं

दरअसल, पक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। इससे अध्यक्ष व्यथित भी नजर आए। सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं। दिग्विजय सरकार के बाद अगर 15 माह की

15वीं विधानसभा में 128 घंटे ही हुई चर्चा

15वीं विधानसभा प्रदेश के इतिहास में कुछ अलग ही प्रकार की है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सत्तापक्ष के विधायकों की बगावत के बाद विपक्षी भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई। यानी कांग्रेस ने 15 महीने तो भाजपा ने बाकी समय सरकार चलाई। इस दौरान भी विधानसभा के जितने सत्र आयोजित किए गए, वे सभी पूरे नहीं चले। इस कारण जनता के मुद्दे दबकर रह गए। बीते रोज यानी 12 जुलाई को 15वीं विधानसभा का 15वां और आखिरी सत्र समाप्त हो गया है। इस विधानसभा के दौरान कोविड महामारी की वजह से कुछ सत्र औपचारिक रूप से हो सके। विधानसभा में 79 दिन की बैठकें बुलाई गईं, जिनमें छह विधानसभा की तुलना में सबसे कम 128 घंटे ही चर्चा हुई है। इस विधानसभा में शुरुआत के 5 सत्र कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के रहे तो, 10 सत्र शिवराज सरकार के कार्यकाल के हैं। कमलनाथ सरकार ने पांच सत्रों में 28 बैठकें बुलाकर 49 घंटे सदन में विभिन्न विषयों व जनता के मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इसके बाद विधानसभा के आखिरी सत्र तक शिवराज सरकार ने 51 दिन की बैठकों में 79 घंटे ही चर्चा कराई। विधानसभा की कार्यवाही की समयसीमा धीरे-धीरे सिमट रही है, इससे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा भी कम हो रही है। आलम यह है कि कभी सदन में मंत्री गायब रहते हैं तो कभी सवाल पूछने वाले विधायक। इसका असर यह हो रहा है कि जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में स्वच्छ बहस नहीं हो पा रही है। इससे जनता का भी रूझान सदन की कार्यवाही के प्रति कम हो रहा है।

दिग्विजय कार्यकाल में 9 माह चली थी विधानसभा

अगर प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार के पहले की बात की जाए तो उसके पहले 10 सालों तक प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार रही है। इस दौरान विधानसभा में चर्चा के लिए लंबा समय मिलता था, जिसकी वजह से कार्यवाही के दिन भी 5 साल में 9 महीने के लगभग हो जाते थे। दिग्विजय सरकार के पहले कार्यकाल 1993-98 के पांच सालों में 13 सत्र हुए थे, जिसमें सदन की कार्यवाही के लिए 283 दिन का समय मिला था। इस दौरान सदन में चर्चा को लेकर माननीयों की भी विशेष रूचि होती थी जिसकी वजह से तब पूरे कार्यकाल में 534 घंटे चर्चा हुई। इसी तरह से उनके दूसरे कार्यकाल 1998-2003 में भी 13 सत्र हुए, जिसकी अवधि 288 दिन की रही। इस दौरान सदस्यों द्वारा जनहित से जुड़े मामलों पर 517 घंटे चर्चा की गई।

कांग्रेस सरकार को छोड़ दिया जाए तो पूरे समय भाजपा की ही सरकारें बनती रही हैं। इस दौरान सत्र की संख्या में तो वृद्धि की गई, लेकिन चर्चा के लिए निर्धारित दिनों के पहले सत्र समाप्त होने व चर्चा के लिए समय में भी तेजी से गिरावट आती रही। 12वीं विधानसभा में भाजपा के तीन मुख्यमंत्री बने जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। 12वीं विधानसभा में 15 सत्र हुए, लेकिन इनमें केवल 159 दिन बैठकें हुईं। इन बैठकों में 275 घंटे विधायकों ने विभिन्न मुद्दों व विषयों पर चर्चा की। इसके बाद 13वीं और 14वीं विधानसभा में 17-17 सत्र बुलाए गए, लेकिन 13वीं विधानसभा में 167 दिन बैठकें हुईं, जिनमें चर्चा के लिए 265 घंटे का समय विधायकों को मिल सका। 14वीं विधानसभा में 135 दिन के लिए बैठकें बुलाई गईं और चर्चा के लिए समय घटकर मात्र 182 घंटे रह गया।

विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर संसदीय कार्यमंत्री व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस ने सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। हम चर्चा चाहते थे, ये भागना चाहते थे। शायरी में कहा- बदहवास हुए इस तरह से कांग्रेस के लोग, जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। उधर, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, ये जनता की बात हमसे सुन लेते, लेकिन इन्हें परेशानी है। दबा दो, छिपा दो, इनके पास यही बचा है। वहीं महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा, सत्तापक्ष अहंकार में है। विधानसभा सत्र चलाना चाहिए। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम तो अपनी आवाज उठाएंगे। ये सौदे की सरकार है, इसीलिए इसे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। उधर, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तरह से चाहा कि सत्र चले। जो मुद्दे उठाए गए, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उन पर कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष का हमेशा रहता है कि उधम करो।

अगर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो वे इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वे आकर्षण का केंद्र बने रहें। इसके लिए वे अजब-

15वीं विधानसभा में बैठकों की स्थिति

सत्र	तय बैठकें	इतने दिन चली बैठकें
जनवरी 2019	4	4
फरवरी 2019	4	3
जुलाई 2019	17	13
दिसंबर 2019	7	6
मार्च 2020	17	2
मार्च 2020	3	1
सितंबर 2020	3	1
मार्च 2021	23	13
अगस्त 2021	4	2
दिसंबर 2021	5	5
मार्च 2022	13	8
सितंबर 2022	5	3
दिसंबर 2022	5	4
फरवरी-मार्च 2023	13	12
जुलाई 2023	5	2

जनता के करोड़ों रुपए पर सिर्फ हंगामा

मप्र विधानसभा में बीते कुछ सालों से सत्र तय समय से पहले स्थगित हो रहे हैं। जबकि इन सत्रों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह राशि जनता के टैक्स की होती है और उम्मीद की जाती है कि यहां जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने इसे राजनीति और सिर्फ हंगामा करने का स्थान बना लिया है। हंगामे के कारण सत्र तय अवधि से पहले ही स्थगित कर दिया जाता है। सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र भी 13 दिन में स्थगित होने का उदाहरण मौजूद है। कमलनाथ सरकार के समय भी अधिकांश सत्र पूरे नहीं चले। इसी तरह इसी 9 अगस्त से बुलाया चार दिवसीय मानसून सत्र तो सिर्फ 2 घंटे 11 मिनट में पूरा हो गया। इस दौरान मिलावटी शराब के मामलों में फांसी जैसी सजा के प्रविधान वाला आबकारी संशोधन विधेयक भी बिना चर्चा पारित हो गया। जानकारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि सत्तापक्ष या विपक्ष, दोनों सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। जनहित के मुद्दे पर बहस न होना या कानून बनाने की कवायद पर चर्चा न होना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। वर्ष 2017 से अब तक कोई भी सत्र अपनी तय अवधि तक नहीं चला। 21 फरवरी से तीन मई 2017 के सत्र में चार दिन बैठक नहीं हुई। जुलाई 2017 में दो, नवंबर-दिसंबर 2017 में चार, फरवरी-मार्च 2018 में पांच, जून 2018 में तीन, जुलाई 2019 दो, दिसंबर 2019 में एक, मार्च 2020 में 15, सितंबर 2020 में दो और फरवरी-मार्च 2021 में 10 दिन बैठकें नहीं हुईं। 15वीं विधानसभा में तीन सत्रों को छोड़कर चार साल में अन्य कोई भी सत्र (बजट, मानसून और शीतकालीन) अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर सका। यहां तक की बजट सत्र की बैठकें भी समय से पहले ही समाप्त हो गईं। जबकि यह सबसे लंबा होने की परंपरा रही है। दरअसल, पक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रुचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। पिछले मानसून सत्र में यही स्थिति बनी। इससे अध्यक्ष व्यथित भी नजर आए पर सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं।

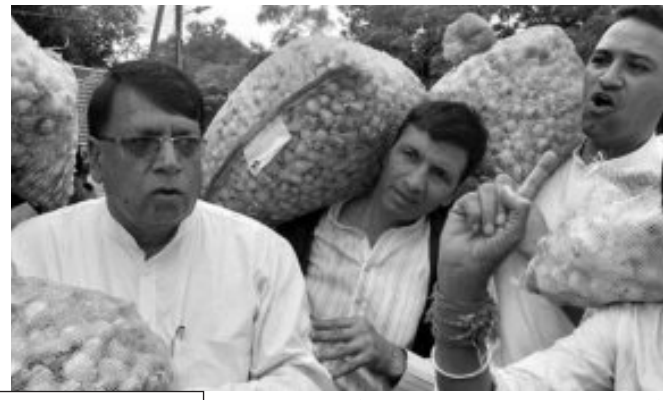

गजब कार्य करते हैं। इस बार आदिवासी विधायक फुनदे लाल मार्को गेटअप में पहुंचे और कहा कि हम सर पर टोपी रूपी कोमब्री और जूट का कपड़ा पहन कर आए हैं। हमें डर है कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता या नेता हमारे सर पर पेशाब न कर दे। वहीं पहले दिन रैगांव की विधायक कल्पना वर्मा टमाटर और मिर्ची की माला पहनकर पहुंचीं।

विधायकों के अधिकारों का हनन

पिछले कई सालों से जिस तरह विधानसभा के सत्र सिमटते जा रहे हैं और सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, उससे विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। बड़ी तैयारी के साथ विधायक विधानसभा सत्र के लिए प्रश्न लगाते हैं। एक घंटे के प्रश्नकाल में 25 प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है। जिन सदस्यों के प्रश्न इसमें शामिल होते हैं वे सदन में सरकार का उत्तर चाहते हैं और पूरक प्रश्न भी करते हैं पर हंगामे के कारण प्रश्नकाल ही पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन भी हो रहा है। अपनी बात रखने का उन्हें मौका भी कम मिल रहा है। इसे लेकर विधायक आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं। विधेयकों को लेकर भी स्थिति अलग नहीं है। इस दौरान अधिकतर विधेयक हंगामे के बीच ध्वनिमत से चंद मिनटों में पारित हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है। विपक्ष लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करना चाहता है पर सत्तापक्ष हंगामा करने लगता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। हंगामा करना ही इनका मकसद रहता है। जबकि, सदन का मंच हमें जनहित पर चर्चा करने के लिए दिया है और सबकी प्रक्रिया निर्धारित है।

गौरतलब है कि विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसमें से 15 करोड़ रुपए विभिन्न अनुदानों के अलग निकाल दिए जाएं तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन-भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतनभत्ते, बिजली बिल, पानी, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होते हैं। सदस्यों को सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए प्रतिदिन डेढ़ हजार रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। यह सत्र प्रारंभ होने से तीन दिन पहले और तीन दिन बाद तक दिया जाता है। निजी वाहन से सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आने पर प्रति किमी के हिसाब से 15 रुपए का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा शासन स्तर पर प्रश्न-उत्तर तैयार करने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में अलग राशि खर्च होती है। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी का कहना है कि सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जनता भी यही अपेक्षा करती है कि उनसे जुड़े विषयों पर सदस्य चर्चा करेंगे और समाधान निकलेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो मतदाताओं में निराशा का भाव आएगा, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। सत्र पूरा चले और विधेयकों पर चर्चा हो, इसकी जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों की है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने पहले ही दिन कहा था कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पर समस्या यह है कि किससे बात करें। सामने (प्रतिपक्ष) में अब कोई बहस करने वाला ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे विधायकों ने कई मुद्दों पर प्रश्न, ध्यानाकर्षण और स्थगन सूचनाएं भी दीं पर सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती थी। यही वजह है कि सत्र की अवधि पहले ही कम रखी और फिर उसे चंद घंटों में समाप्त भी कर दिया।

हर घंटे का खर्च 40 लाख

विधानसभा की कार्रवाई का एक मिनट के संचालन का खर्च करीब 66 हजार रुपए आता है। इसके बाद भी जनता से जुड़ी समस्याओं के प्रति विधायकों की गंभीरता नहीं दिख रही है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आम बजट पर सामान्य चर्चा हुई तो 230 सदस्यों की विधानसभा में महज 19 सदस्य ही उपस्थित थे, जिनमें से 4 मंत्री और 2 विधायक सत्तापक्ष के। इस बीच भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि यह देख लिया जाए कि सदन में कोरम पूरा है या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने दिखवाया तो 10 फीसदी विधायक ही सदन में मौजूद थे, इसे देखते हुए उन्होंने सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सदन में उपस्थित रहने को कहा। विधानसभा का सालाना बजट 100 करोड़ रुपए है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए अनुदान, वेतन और खर्चों के रहते हैं। बाकी 85 करोड़ रुपए सदन की कार्यवाही के संचालन पर खर्च होते हैं। यानी सालभर में तकरीबन 45 बैठकें होती हैं। इस हिसाब से एक दिन की बैठक के दौरान पांच घंटे सदन की कार्रवाई चलती है, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक घंटे की कार्रवाई पर 40 लाख रुपए और 1 मिनट की कार्रवाई पर खर्च 66 हजार रुपए के करीब खर्च होते हैं।

15वीं विस का कोई सत्र पूरा नहीं

15वीं विधानसभा की स्थिति यह रही कि पिछले 5 साल में कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चला। 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र यानी मानसून सत्र 5 दिन की बजाय दूसरे दिन ही खत्म हो गया। 2 दिन चली बैठक में 4 घंटे भी सदन के अंदर काम नहीं हुआ। इसको लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं पर जनहित से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हम बड़ी तैयारी के साथ प्रश्न लगाते हैं

ताकि समस्या का समाधान हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अध्यक्षों के सम्मेलन में भी सत्र की अवधि लगातार घटने का मुद्दा उठा था। लोकसभा वर्ष में सौ दिन, बड़ी विधानसभा 90 से 75 दिन और छोटी विधानसभा में सदन की कार्यवाही 60 दिन चलनी चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। अभी वर्ष में छह माह के भीतर सत्र बुलाना अनिवार्य है। इस अवधि को तीन माह करने की अनुशंसा की है। लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में भी यही कहा गया। हर बार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की कार्यवाही संचालित करने पर सहमति बनती है। लेकिन सदन में पहुंचते ही नेता हंगामे पर उतर आते हैं। आलम यह है कि 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र यानी मानसून सत्र में 41 ध्यानाकर्षण और 6 स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, वहीं 139 के संबंध में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही दो दिन में ही सिमट गई। ऐसा ही 15वीं विधानसभा के लगभग हर सत्र में हुआ है।

हां की जीत, लोकतंत्र हार गया

मप्र देश के उन प्रदेशों में शामिल था, जहां विधानसभा की कार्यवाही अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनती रही है। लेकिन पिछले कुछ विधानसभा से स्थिति यह हो गई है कि विधानसभा का सत्र महज औपचारिकता बनकर रह गया है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं। इस दौरान सारे सरकारी काम हंगामे के बीच निपटा लिए जाते हैं। सरकारी काम निपटाने के लिए हां की जीत

से पारित करा लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से लोकतंत्र हर बार हार रहा है। पिछले कुछ विधानसभा सत्रों को देखें तो विपक्ष के ज्यादातर सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने नारे लगाते रहते हैं। इधर विपक्ष के सदस्य नारे लगाते रहते हैं और उधर कुछ मंत्री भी अपने कुर्तों की बाहें चढ़ाकर जोर-जोर से बोलते रहते हैं। उनके हाव-भाव यह दर्शा रहे होते हैं कि वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इधर मंत्री कुर्ते के बाजू चढ़ाकर चेहरे पर अपने तेवर लाते, उधर विपक्ष के नारों का दायरा बढ़ जाता है। साथ ही आवाज भी ऊंची हो जाती है। आसंदी पर अध्यक्ष बहुत व्यस्त नजर आते हैं। फिर वे खड़े होकर कुछ पढ़ते हैं। उनका पूरा ध्यान अपने सामने रखे कागजों पर रहता है। अध्यक्ष कुछ पढ़ते हैं फिर अचानक एक मंत्री खड़े होते हैं। अध्यक्ष कुछ कहते हैं, फिर मंत्री वही क्रम दोहराते हैं। और हंगामे के बीच अध्यक्ष के माइक से आवाज आती...जो पक्ष में हैं वे हां कहें! विधायक बिना रुके बोलते जाते हैं! हां की जीत हुई... हां की जीत हुई! हां की जीत हुई! इसके बाद अध्यक्ष कुछ मिनट तक यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं! हंगामे के बीच हां जीतता रहता है। हर जीत के बाद विपक्ष और जोर से चिल्लाता है। यह दृश्य मप्र विधानसभा के हर सत्र में आम हो गया है। जानकारों का कहना है कि विधानसभा सत्र न चलाने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार बन गया है। मानसून सत्र में भी यही देखने को मिला। विधानसभा आंकड़ों पर चलती है। उसके आंकड़ों से पता चला कि 15वीं विधानसभा का यह सबसे छोटा सत्र रहा। हालांकि पिछले करीब 20 साल में विधानसभा के सत्र लगातार सिकुड़ते चले आ रहे हैं। वर्तमान विधानसभा राज्य की 15वीं विधानसभा है। यह कई मायनों में ऐतिहासिक हो गई है। यह विधानसभा बिना चुनाव के सरकार बदले जाने की गवाह भी है। सबसे कम घंटे काम का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। पिछले पांच साल में कुल 79 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। हालांकि इस अवधि में भी निर्धारित समय तक सदन नहीं चला।

एक सवाल का जवाब तैयार करने में खर्च होते हैं औसतन 50 हजार

इन दिनों मप्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसके दो दिन सिर्फ विधायकों के हंगामे के कारण खराब हो चुके हैं। इस हंगामे के चलते 220 से 310 तक सवालों के जवाब बनने के बावजूद सार्वजनिक नहीं हो पाते। सदन में पूछे गए एक सवाल का जवाब तैयार करने में औसत 50 हजार रुपए तक खर्च आता है। कुछ सवालों के जवाब जुटाने में गांवों से भी जानकारी मंगाई जाती है। इनका खर्च 75 हजार से एक लाख रुपए तक चला जाता है। एक दिन के प्रश्नकाल पर औसतन 50 लाख रुपए तक आता है। ये राशि विधानसभा की एक दिन की बाकी कार्यवाही के कुल खर्च से भी ज्यादा है, क्योंकि सदन की हर घंटे की कार्यवाही 2.50 लाख रुपए की पड़ती है। यदि 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.50 लाख तक आता है। बजट सत्र के दौरान 2500 से ज्यादा सवाल पूछे जाना है। 2019 से अब तक ऐसे 500 सवाल पूछे जा चुके हैं, जिनमें एक ही जवाब मिला- जानकारी एकत्रित की जा रही है। यदि इसी बजट सत्र की बात करें तो 5 दिनी कार्रवाई में 28 फरवरी को 224, 1 मार्च को 227, 2 मार्च को 230, 3 मार्च को 307 सवाल पूछे गए। किसानों की कर्जमाफी को लेकर तीन साल में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। लेकिन, सभी में सिर्फ एक ही जवाब दिया गया- जानकारी जुटा रहे हैं। व्यापमं घोटाले की जांच 2013 से चल रही थी जो 2015 में बंद कर दी गई। इस बारे में अब तक 80 सवाल पूछे गए, जिसमें हमेशा कोर्ट का हवाला देकर जवाब खत्म कर दिया गया। 2017 में हुए मंदसौर गोलीकांड के बाद 2018 में न्यायिक आयोग गठित हुआ था, तब से अब तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। दो सरकारें बदल चुकीं, लेकिन अब तक इसमें एक ही जवाब मिला- कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधायकों द्वारा पूछे गए किसी एक सवाल का जवाब तैयार करने में विधायक, उसके स्टाफ का वेतन, विधानसभा का स्टाफ, संभाग और जिलास्तर पर होने वाला खर्च शामिल रहता है। इसमें कर्मचारी का वेतन, विशेष भत्ता, फोटोकॉपी, डाक या व्यक्ति द्वारा दस्तावेज भोपाल ले जाने का खर्च भी शामिल रहता है। एक प्रश्न में विधायक का आधा दिन खर्च होता है और उनके स्टाफ निजी सचिव के दो दिन का वेतन। कुल खर्च 5 हजार रुपए। प्रश्न की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, दस्तावेज इकट्ठा कर प्रश्नशाखा में प्रश्न लगाने का खर्च 1000 रुपए। इस शाखा में प्रश्न का इनवर्ड होगा और इसे कम्प्यूटर पर टाइप किया जाएगा। यहां से अंडर सेक्रेटरी से लेकर 15 से 20 लोगों के स्टाफ का वेतन। कुल खर्च 4 से 5 हजार रुपए। हफ्तेभर बाद प्रश्न संबंधित विभाग में जाता है। यहां जांच होती है। मंत्री की सहमति से सचिवालय को भेजते हैं। कुल खर्च 10 हजार रुपए। 5. 80 प्रतिशत प्रश्नों की जानकारी संभाग, जिलों से आती है। इस पर कुल 15 हजार रुपए खर्च होते हैं।

मोदी-शाह भरोसे भाजपा

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपना फोकस अब इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे पांच राज्यों मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और मिजोरम पर फोकस कर दिया है। लगातार इन राज्यों में केंद्रीय नेताओं के दौरों के साथ संगठन की बैठकें आयोजित होने लगी हैं। भाजपा हाईकमान को इन पांच राज्यों में एक समय भाजपा की सबसे मजबूत कड़ी रही छत्तीसगढ़ इस समय सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रहा है। इस कारण मोदी और शाह ने छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। भाजपा हाईकमान के पास छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकप्रियता में बढ़त बनाए हुए हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की पूरी संभावना है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस को मिल रही बढ़त और छत्तीसगढ़ भाजपा में नेताओं के बीच जारी मतभेद को लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा कर 7000 करोड़ रूपए की सौगात दी है।

जून महीने में भी अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, तब शाह ने 22 जून को दुर्ग में जनसभा को संबोधित किया था। एक जुलाई को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का भी बिलासपुर में दौरा हो चुका है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि शाह के निर्देश पर 175 कार्यकर्ताओं की विशेष टीम पिछले महीने से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए है और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति की जमीनी रिपोर्ट तैयार कर अमित शाह को सौंपी है। अपने ताजा दौरे के दौरान अमित शाह इसी रिपोर्ट को वरिष्ठ नेताओं से साझा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसी के आधार पर प्रदेश के नेताओं को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौपेंगे।

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उसे 90 विधानसभा सीटें मिलीं। इसमें से 39 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 51 सीटें सामान्य वर्ग से हैं लेकिन इन सामान्य सीटों में भी करीब एक दर्जन सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग का खास प्रभाव है। प्रदेश के मैदानी इलाकों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी भारी संख्या है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 47 प्रतिशत है। मैदानी इलाकों से करीब एक चौथाई विधायक इसी वर्ग से विधानसभा में चुनकर आते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव से पिछड़े वर्ग की सीटों पर भाजपा का दबदबा था लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में एससी के लिए आरक्षित 10 सीटों में से 6 सीटें जीत ली और एसटी के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 25 सीटें जीत ली थी। एससी, एसटी और आदिवासी वोटरों के सहारे लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा एक बार फिर पिछड़ों के वोट के सहारे छत्तीसगढ़ में सत्ता पाना चाहती है। इसके लिए अपने संगठन को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए भाजपा ने प्रदेश में कई बदलाव किए थे। तीन बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर को छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर लगातार छत्तीसगढ़ में कैम्प कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।

हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमजोर पक्ष यह भी रहा है कि भाजपा भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर सकी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के सामने चेहरे के अभाव की है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को प्रदेश की राजनीति से लगभग बाहर कर दिया गया है। फिलहाल भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। इसलिए चेहरे की बजाय संगठन के बल पर भाजपा भूपेश बघेल को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में तय है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं भूपेश बघेल प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। जहां तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। इसलिए कांग्रेस पहले ही भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास का कार्ड खेल रही है। वहीं भाजपा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाने से भाजपा को तगड़ा झटका भी लगा है।

● रायपुर से टीपी सिंह

कांग्रेस भी जुटी मिशन मोड में

अगर भाजपा प्रदेश में चुनावी रूप से सक्रिय हो रही है तो कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उपमुख्यमंत्री बना दिया है। छत्तीसगढ़ को पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद मिला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता में हुई वापसी में घोषणा समिति के अध्यक्ष रहे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की भूमिका महत्वपूर्ण थी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दौड़ में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास मंहत भी थे। लेकिन बाजी भूपेश बघेल के हाथ लगी। कहा गया था कि ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ में लागू होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूपेश बघेल पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसे में चुनाव के पांच महीने पहले टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाकर असंतोष को साधने की कोशिश की गई है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 और भाजपा के पास 14 सीटें हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस का दबदबा रहा है। प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43.2 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं भाजपा को 32.9 प्रतिशत वोट मिले थे। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 40.3 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं भाजपा को 2013 में 41 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। बसपा को यहां पर साल 2013 में 4.3 प्रतिशत वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने अजीत जोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इन चुनावों में पार्टी को 10.7 प्रतिशत वोट हासिल हुए। अब अजीत जोगी नहीं है और बसपा का भी आधार सिकुड़ गया है।

आसान नहीं विपक्षी एकता की राह

विपक्षी दल अपने साथी दल के पर कतर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक जीतने के बाद वह अपने को 2024 का विजेता मानकर चल रही है। वह चाहती है कि बाकी दल उसकी पालकी के कहार बनें। इस चक्कर में कम से कम चार ऐसे दल हैं जो कांग्रेस को अपने राज्य से बाहर रखना चाहते हैं।

फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गीत है- कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया। विपक्षी एकता के प्यार का भी वही हाल है। सबकी इच्छा है कि भाजपा हार जाए और मोदी हट जाएं, पर कोई अपनी अंगुली कटवाने को तैयार नहीं है। सबके घर के दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों का दरवाजा हमारे लिए खुला रहे।

समझना कठिन हो रहा है कि मिलने के लिए मिल रहे हैं कि अलग होने के लिए। इसी कड़ी में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बैठक परस्पर अविश्वास के माहौल में हो रही है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की ओर संदेह की नजर से देख रहे हैं तो कांग्रेस के मन से आवाज उठ रही है कि सिंहासन खाली करो कि कांग्रेस आती है। समस्या यह है कि यह एक ऐसी बारात है जिसमें कोई अपने को बाराती मानने को तैयार ही नहीं है। सबको लग रहा है कि दूल्हा तो हमें ही होना चाहिए। तो अघोषित रूप से तय हो चुका है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सबसे ज्यादा आक्रामक दिखेगा, वही दूल्हा बनने का हकदार होगा। इस चक्कर में मोदी को गाली देने की होड़ लगी है।

विपक्षी दल अपने साथी दल के पर कतर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक जीतने के बाद वह अपने को 2024 का विजेता मानकर चल रही है। वह चाहती है कि बाकी दल उसकी पालकी के कहार बनें। इस चक्कर में कम से कम चार ऐसे दल हैं, जो कांग्रेस को अपने राज्य से बाहर रखना चाहते हैं। ये हैं- तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति। विपक्षी एकता के लिए इनकी शर्त है कि कांग्रेस उनके राज्य में चुनाव न लड़े। अब जो बच जाते हैं, उनमें प्रमुख दल हैं- राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भाकपा(माले), माकपा, द्रमुक, राकांपा, शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे), झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य छोटे-मोटे दल। इनमें से लगभग सभी का कांग्रेस से पहले से ही गठबंधन है।

किसी को कोई संदेह न रह जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को चुनौती दे दी है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की सेवाओं के संबंध में केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध को भाजपा विरोध का लिटमस टेस्ट बना दिया है। जो इस अध्यादेश का विरोध करेगा, वही भाजपा और मोदी विरोधी माना जाएगा। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि विपक्षी एकता की बैठक का पहला एजेंडा ही यही होगा। बाकी दल कांग्रेस से सवाल पूछें कि वह इसके विरोध में हैं या समर्थन में? याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को मिलने के लिए समय भी नहीं दिया। इस मुद्दे के जरिए केजरीवाल राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं।

कांग्रेस को घेरने में केजरीवाल अकेले नहीं हैं। ममता बनर्जी अगर आएंगी तो कांग्रेस से ही सवाल करेंगी। यह कि बंगाल में उनके खिलाफ लड़कर कांग्रेस भाजपा की मदद क्यों करना चाहती है? अखिलेश यादव आजकल दीदी की अंगुली पकड़कर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समस्या कांग्रेस से ही है। वह भी चाहते हैं कि कांग्रेस उप्र से दूर रहे। यही मांग चंद्रशेखर राव की भी थी। हालांकि वह पटना की बैठक में नहीं आए।

कांग्रेस इनकी बात मान ले तो 139 सीटों पर तो उम्मीदवार ही न खड़े करे। आंध्र, ओडिशा, दिल्ली और पूर्वोत्तर (असम को छोड़कर) से वह साफ ही है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वह गठबंधन की जूनियर पार्टनर है। तो कांग्रेस के लिए वही राज्य बचते हैं, जहां उसकी भाजपा से सीधी टक्कर है। मतलब-गुजरात, मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। प्रश्न है कि क्या कांग्रेस इस कीमत पर विपक्षी एकता के लिए तैयार है। कर्नाटक की जीत के बाद उसका उत्साह सातवें आसमान पर है। वह कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के लिए जगह खाली करनी चाहिए। यानी दोनों एक-दूसरे से जगह खाली करने को कह रहे हैं। कोई जगह देने की बात ही नहीं कर रहा।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब लगभग सभी दल भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। ताजा शिकार उद्धव ठाकरे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि मुंबई नगर महापालिका में उद्धव के मुख्यमंत्री रहते वित्तीय अनियमितता हुई।

अभी सहमति नहीं बनी

भाजपा विरोधी दलों और नेताओं को इस जमीनी यथार्थ का आभास है, तभी वे अपने मतभेदों को परे रखकर एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद 1977 की तरह पार्टियों का विलय कर एक पार्टी बनाने की बात तो दूर अभी तक उनमें आरंभिक सहमति बनती भी नहीं दिख रही, जिससे लगे कि मोदी और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त विपक्ष की कड़ी चुनौती मिलने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म-इतिहास और राष्ट्र आदि को लेकर जिस तरह का जागरण हुआ है, विपक्ष की कोई पार्टी भाजपा की तुलना में उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है। देश के बड़े समूह की मानसिकता यही है कि व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कष्ट भी उठाने पड़ें तो हिंदुत्व, राष्ट्रीयता और धर्म-संस्कृति आदि के मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते।

लोकसभा चुनाव के मुद्दे और प्राथमिकता अलग

राज्यों के स्तर पर कुछ पार्टियां, नेता और गठबंधन भले ही मजबूत दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकता सर्वथा भिन्न होती है। मोदी सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर काम करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय पर ऐसे ठोस काम किए हैं, जिनसे एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार हुआ है। आदिवासियों से लेकर दलितों में भाजपा की गहरी होती पैठ इसका सशक्त उदाहरण है। इसकी तुलना में विपक्ष कहां खड़ा है? राज्यों में किसी क्षेत्रीय दल का राजनीतिक रास्ता कांग्रेस काट रही है तो कहीं कांग्रेस का क्षेत्रीय दल। किसी सहमति बनने से पूर्व ही तृणमूल ने ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस चुनाव में वामपंथी दलों के साथ गठजोड़ करती है तो वह उसका समर्थन भूल जाए। आम मतदाताओं को भी इसका आभास है कि विपक्षी नेताओं के भीतर एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का अभाव है। इसी कारण वे किसी को प्रधानमंत्री पद के रूप में अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। जनता ने गठबंधन वाली अस्थिर सरकारों का दौर भी देखा है और उसके दुष्परिणाम भी भुगते हैं। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे में क्या विपक्षी दलों का कोई नेता जनता को यह विश्वास दिलाने में सक्षम होगा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर एवं टिकाऊ सरकार देने में सक्षम होंगे?

महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल के शीशमहल की जांच तेज हो गई है। तमिलनाडु में द्रमुक के एक मंत्री सेंथिल बालाजी प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में हैं तो दूसरे मंत्री और उनके बेटे को जांच में मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

विपक्षी दलों की जैसी बैठक पटना में हुई, उस तरह की पहले शायद ही कभी हुई हो। इससे पहले जब भी विपक्षी दल एकता के उद्देश्य से मिलते रहे हैं तो एक बात तय रहती थी कि सब कुछ न कुछ लेन-देन के लिए तैयार हैं। यहां जो लोग जुट रहे हैं, उनके मन में सिर्फ लेने की बात है, देने की नहीं। पहले की विपक्षी एकता गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से संचालित होती थी। उस समय व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती थी। अब जो पार्टियां और नेता मिल रहे हैं, उन्हें भाजपा से ज्यादा समस्या नहीं है। उन्हें लगता है कि भाजपा से लड़ने में वे सक्षम हैं, पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा।

विपक्षी दलों का यह सम्मेलन एक व्यक्ति से लड़ने की ताकत जुटाने के लिए हुआ, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई से बड़ी समस्या हो गई है मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम। यह ऐसी समस्या है जिसका सामना भारत के विपक्ष ने कभी नहीं किया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा सरकार के खिलाफ बनता है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि नौ साल बाद भी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जैसे संप्रग के समय दूसरे कार्यकाल में घोटाले पर घोटाला सामने आने लगा था, वैसा ही मोदी सरकार के साथ भी होगा, पर इस मोर्चे पर भी निराशा हाथ लगी।

आगामी आम चुनाव से पहले भाजपा के विरूद्ध राजनीतिक गोलबंदी की कवायदें तेज हो रही हैं। इसमें शरद पवार को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह इस दिशा में कोई खाका बनाने का प्रयास करें। भाजपा के विरूद्ध मोर्चाबंदी की तैयारी को लेकर हाल में पवार ने तीन महत्वपूर्ण बातें की हैं। एक, विपक्षी मोर्चे के पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होना आवश्यक नहीं। दूसरे, हम भाजपा के विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे, 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में रणनीति बनाई गई, जिसमें विपक्षी खेमे की ओर से संयुक्त उम्मीदवारी को लेकर विचार किया गया। वैसे, ये तीनों बातें ऐसी नहीं हैं जिन पर भाजपा विरोधी किसी नेता ने पहले बयान न दिया हो। हां, एक साथ तीनों बातें पहली बार किसी बड़े नेता ने कही हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ने के बाद से ही लगातार भाजपा के विरूद्ध विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा करने पर जोर दिया है। पटना बैठक भी उन्हीं की पहल पर हुई।

दरअसल, पहले हिमाचल प्रदेश और हाल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय से विपक्षी दलों को आगामी आम चुनाव को लेकर उम्मीद बंधी है। उन्हें लगता है कि वे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो मोदी के नेतृत्व में भी भाजपा को परास्त किया जा सकता है। इन नेताओं को समझना चाहिए कि राजनीति और चुनाव कल्पना का नहीं, अपितु यथार्थ का विषय है। कोई नेता या नेताओं का समूह किसी समीकरण या राजनीतिक तस्वीर की कल्पना कर ले तो आवश्यक नहीं कि वे उसे यथार्थ में भी बदल पाएं।

विपक्षी एकता के इन प्रयासों के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि इस खेमे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसे लेकर पवार ने आपातकाल के बाद हुए चुनाव का उदाहरण दिया कि तब भी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जनता पार्टी चुनाव जीती और अंतत: मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हालांकि, 1977 का उदाहरण देने वाले भूल रहे हैं कि आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष में साथ आने, जेल में बंद रहने और यातनाएं भुगतने के कारण विपक्षी नेताओं का परस्पर संवाद और संबंध बहुत गहरा हो चुका था। दूसरे, आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जैसे दलीय स्वार्थों से परे एक ऐसा विराट व्यक्तित्व था जिसके प्रति सबके मन में सम्मान का भाव था। वहीं विपक्षी एकता और जनता पार्टी के गठन के मुख्य कारक थे। दक्षिण भारत के परे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेसी नेताओं के विरूद्ध कई कारणों से व्यापक आक्रोश भी था। जबकि वर्तमान राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल अलग है।

आज का राजनीतिक सच यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के समानांतर विपक्ष के पास कोई एक सर्वस्वीकार्य चेहरा नहीं है। यहां तक कि जिन राज्यों में भाजपा का जनाधार मजबूत नहीं और उसे वोट नहीं मिलता वहां भी लोगों का बड़ा समूह प्रधानमंत्री मोदी को ही अपनी पसंद बता देता है। दूसरे, संगठन और जनाधार के स्तर पर भी भाजपा देश की इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति है, जिसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दलों के गठजोड़ का टिकना आसान नहीं।

● **विपिन कंधारी**

भाजपा को पता है कि 2024 में उसे सत्ता तश्तरी में रखी नहीं मिलेगी। देश में राजनीतिक स्थितियां हाल के महीनों में भाजपा के लिए उतनी सुखद नहीं रही हैं। यदि इस साल के विधानसभा चुनावों में उसे जीत नहीं मिलती है, तो आम चुनाव की उसकी डगर कठिन हो सकती है। लिहाजा भाजपा इन चुनावों से पहले ऐसा कार्ड तैयार रखना चाहती है, जो उसके लिए संजीवनी का काम कर सके। इसके लिए उसने संभवतः समान नागरिक संहिता को चुना है और इस पर तैयारी शुरू कर दी है।

यूसीसी : तुरुप का पत्ता

त्रिपल तलाक, जम्मू-कश्मीर में धारा-370 और राम मंदिर निर्माण जैसे अपने एजेंडे पर काम करने के बाद भाजपा ने अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर नजर टिका दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उसने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया था, जबकि उत्तराखंड में उसकी सरकार संहिता तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। भाजपा समान नागरिक संहिता को अगले लोकसभा चुनाव से पहले ला सकती है; क्योंकि उसका लक्ष्य 2024 में एनडीए-3 सरकार सुनिश्चित करना है। हालांकि मोदी सरकार इसे किस रूप में लाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाजपा, जिसमें पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, का यूसीसी राग लोकसभा ही नहीं, बल्कि इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए भी है। क्योंकि भाजपा महसूस करती है कि उसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है।

यदि समान नागरिक संहिता भाजपा के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के हिसाब से हुई, तो निश्चित ही विपक्षी दल, अन्य धार्मिक और सामाजिक संगठन इसका विरोध करेंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वें विधि आयोग ने मार्च, 2018 में जनता के साथ विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जरूरत देश को नहीं है। अब पांच साल बाद 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आम जनता से विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और 15 जुलाई तक लोगों से विचार मांगे हैं। कानून और न्याय की संसदीय समिति ने भी यूसीसी मामले में 3 जुलाई को बैठक बुलाई है, जिसमें सुशील मोदी की अध्यक्षता में विधि आयोग और कमेटी के सदस्य भी रहेंगे। विधि आयोग को अब तक साढ़े आठ लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। समान नागरिक संहिता इसलिए देश में चर्चा के केंद्र में आ गई है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी में पर्सनल लॉ या विरसे के कानून, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों को एक समान संहिता से संचालित किए जाने की संभावना है। चूंकि समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र का अहम हिस्सा रही है। ज्यादातर जानकारों को लगता है कि इसका प्रारूप उसे चुनावी लाभ देने की दृष्टि वाला बनाया जा सकता है। ऐसे में अन्य धार्मिक संगठन, जिनकी अपनी धार्मिक संहिता (पर्सनल लॉ) हैं; इस पर विरोध कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मप्र भाजपा के मेरा बूथ, सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता का जोरदार पक्ष लिया और जोर देकर कहा कि एक ही देश में दो कानून नहीं हो सकते। चुनाव भाषणों को छोड़ दें, तो हाल के

क्या हैं पेचीदगियां?

देश की स्वतंत्रता के बाद एक से ज्यादा बार समान नागरिक संहिता की निजी (धार्मिक/सामाजिक) कानूनों में सुधार का मुद्दा उठा है। यदि सिर्फ समान नागरिक संहिता की ही बात की जाए, तो इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह मसला जम्मू-कश्मीर में धारा-370 खत्म करने से भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। धार्मिक समूह तो विरोध करेंगे ही, इस पर राजनीतिक सहमति बनाना भी बहुत मुश्किल काम होगा। साथ ही देश के कानूनों के भीतर ही कई विरोधाभास हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे देश में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें भरपूर धार्मिक हस्तक्षेप है। 31 अगस्त, 2018 को 21वें विधि आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि यह ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं हो कि एकरूपता की कोशिश ही खतरे का कारण बन जाए। यूसीसी का मतलब प्रभावी रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने, संरक्षण, उत्तराधिकार, विरासत इत्यादि से जुड़े कानूनों को व्यवस्थित करना होगा। इसमें देशभर में संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखना होगा। कई जनहित याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ तलाक, गार्जियनशिप (अभिभावक्ता) और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों के नियमित करने की मांग की जा रही है।

वर्षों में यह पहला मौका है, जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह समान नागरिक संहिता पर बोले हैं। चूंकि विधि आयोग ने इससे जुड़ी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, मोदी का इस तरह इस पर बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष का सवाल है कि जब पांच साल पहले इसी सरकार के समय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, तो अब ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि इसे लागू किया जाए? विपक्ष के मुताबिक, संहिता लागू होने से देश में कई तरह के विवाद के पिटारे खुल जाएंगे।

भाजपा का कहना है कि समान नागरिक संहिता देश में बराबरी का रास्ता खोलेगी और इसमें गलत क्या है? पार्टी के मुताबिक, इससे बेहतरी का रास्ता खुलेगा। बता दें कि विधि आयोग ने सन् 2016 में जब इस मुद्दे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी, तो करीब दो साल का समय लगा था। जनता, जिसमें तमाम धार्मिक और सामाजिक समूह शामिल हैं; के सुझावों के बाद उसने मार्च, 2018 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें साफतौर पर कहा गया था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जरूरत देश को नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट में पारिवारिक कानून (फैमिली लॉ) में सुधार की बात जरूर कही गई थी।

अब जब यूसीसी की चर्चा भारत में बहुत तेजी से हो रही है, तो दिलचस्प बात यह है कि आज से 73 साल पहले 23 नवंबर, 1948 को देश की संसद में इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। उस समय सवाल यह था कि क्या समान नागरिक संहिता को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? लंबी बहस के बाद भी इस पर कोई राय नहीं बन पाई। कारण था देश का बहुलवादी होना। जब इस पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो यह मुद्दा टाल दिया गया। एक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यूसीसी लागू कराने की मांग की गई थी। हालांकि 7 दिसंबर, 2015 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को देश में यूसीसी लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कानून बनाने का काम संसद का है। इसके बाद इसी साल जनवरी में गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिकाकर्ता अनूप बरनवाल ने अपनी याचिका में राज्यों की इस पहल को चुनौती दी थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी के गठन का अधिकार है। अगर राज्य ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। सिर्फ कमेटी के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मई, 2022 में सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में समान नागरिक संहिता के अध्ययन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यही नहीं, गुजरात सरकार ने भी अक्टूबर, 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया था। यही नहीं शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार के लिए सभी धर्मों में एक समान कानून लागू करने की मांग वाली याचिका भी वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है। मप्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे लागू करने की बात कर चुका है, तो वास्तव में यह उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही कहा गया है। भाजपा के अन्य नेता भी इसी को आधार बनाकर इसका समर्थन करते हैं।

समान नागरिक संहिता की चर्चा तेज होने के साथ ही धार्मिक समूह भी सक्रिय हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 27 जून को इस विषय पर चर्चा के लिए बैठक की। यह उसकी इस तरह की पहली बैठक थी। कोई तीन घंटे की इस बैठक में संहिता के तमाम कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील मौजूद थे। इसमें फैसला किया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। साथ ही बोर्ड से जुड़े लोग विधि आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसे विधि आयोग को सौंपा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने ड्राफ्ट पर मुख्य फोकस शरीयत के जरूरी हिस्सों पर रखेगा। दिलचस्प यह है कि बोर्ड की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के मप्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया था। मोदी के बयान के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? ओवैसी ने पूछा कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा? सरकार का कहना है कि विधि आयोग सिविल कोड को लेकर संजीदगी से विचार कर रहा है। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सरकार सभी संबंधित पक्षों से बात करेगी। लेकिन इसे लागू करने के बारे में फैसला संसद को लेना है। कोई बाहरी अथॉरिटी उसे कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती।

● इन्द्र कुमार

यूसीसी से क्या बदलेगा?

यूसीसी के लागू होने से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, ताकि वह ग्रेजुएट हो जाएं। ग्राम स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा होगी। बिना पंजीकरण सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी। पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार होंगे। बहु-विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लडके-लडकी की बराबर की हिस्सेदारी (पर्सनल लॉ में लडके का शेयर ज्यादा होता है) होगी। नौकरीपेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता-पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव-इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पति-पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पैरेंट्स (दादा-दादी या नाना-नानी) को दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी।

गुरु दक्षिणा में दिया धोखा!

अजित पवार ने अपने चाचा से सियासत की एबीसीडी सीखी है, अपने गुरु और चाचा शरद पवार को धोखा देकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि अब वो सियासत का महत्वपूर्ण सेमेस्टर पास कर चुके हैं। अजित पवार ने साबित कर दिया कि राजनीति में गुरु दक्षिणा में धोखा भी दिया जाता है। अजित पवार के चाचा भी हैं शरद पवार और गुरु भी। चेले ने जो सीखा उसका शक्ति प्रदर्शन अपने गुरु पर ही कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और उनकी एनसीपी की जो गत हुई है उसके पीछे की कहानी समझ पाना आसान नहीं है। ये साजिश है, स्वार्थ है या सुनियोजित योजना के तहत सब कुछ हुआ है! अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के हौसले कमजोर करने के लिए भाजपा ने सत्ता का प्रलोभन देकर, खरीद फरोख्त करके या ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर एनसीपी को तोड़ा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने खुद ही अपने भतीजे को महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री और बेटी को केंद्रीय मंत्री बनवाने के लिए ये किया। या राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अपनी चाणक्य बुद्धि लगाकर अपने भतीजे को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिराने की साजिश के तहत भेजा है। कुछ भी हो सकता है।

इतिहास खुद को दोहराता है, यह कहावत हम सबने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ऐसा होते देखा होगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वह इतिहास का दोहराव ही है। 1978 में बसंत दादा पाटिल को जिस अंदाज में शरद पवार ने धोखा दिया, कुछ उसी अंदाज में उनके सबसे बड़े भतीजे और एक दौर तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाते रहे अजित पवार ने उन्हें चकमा दिया है। दिलचस्प यह है कि जिस दिन शरद पवार ने अपने गुरु सरीखे बसंत दादा पाटिल की सरकार उलट दी थी, उसके ठीक पहले की रात मुख्यमंत्री निवास में पाटिल के साथ उन्होंने खाना खाया था। भोजन के बाद लौटते वक्त शरद पवार ने उनसे माफी भी मांगी थी, तब बसंत दादा पाटिल ने उस माफी को एक हद तक मजाक ही समझा था। साफ है कि बसंत दादा पाटिल को अंदेशा भी नहीं था कि जिसे युवा मंत्री के तौर पर वे आगे बढ़ा रहे हैं, वह सच बोल रहा है। कुछ इसी तरह अजित पवार की चाल को शरद पवार भांप नहीं पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजित पवार अपने इस कदम के बाद राजनीति में वैसा ही शिखर छू सकेंगे, जैसा शरद पवार ने बसंत दादा पाटिल को धोखा देने के बाद छुआ? सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महत्वपूर्ण दल बनाया, क्या अजित पवार उस पर कब्जा बरकरार रख पाएंगे? सवाल यह भी है कि मराठवाड़ा और खानदेश में शरद पवार के चलते जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सियासी नींव ताकतवर बनी रही, वहां अब भी पार्टी की घड़ी टिक-टिक आगे बढ़ती रहेगी? सवाल यह भी है कि जिस अजित पवार को सिंचाई घोटाले का अहम अपराधी भाजपा मानती रही है, उसके साथ आने के बाद क्या उनका घोटाला भुला दिया जाएगा।

राजनीति के साथ एक दिक्कत यह है कि वह तत्कालिक सवालों से ही ज्यादा जूझती है, उन्हीं के इर्द-गिर्द अपने कदम बढ़ाती है। वह दीर्घकालिक प्रभावों को अपनी जल्दीबाजी वाले स्वभाव के चलते भुलाती रहती है। पत्रकारिता भले ही जल्दबाजी का साहित्य हो, लेकिन उसकी भूमिका दीर्घकालिक सवालों से जूझना और दूरंदेशी प्रभावों पर नजर रखना है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब पत्रकारिता भी राजनीति के जल्दबाजी के स्वभाव से इतना प्रभावित हो गई है कि वह तुरंत नतीजों पर भरोसा करती है, फास्टफूड या यूं कहें कि सत्तू खाने के अंदाज में हर घटना का मुआयना और आंकलन करने लगी है। अजित की तकरीबन सफल बगावत के बाद शरद पवार को शुरूआती झटका जरूर लगा। जब अजित ने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया, तब शरद पवार पुणे के अपने घर में थे। बदले घटनाक्रम के बाद उनसे मिलने उनकी बेटी और एनसीपी की नई नवेली कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पुणे गईं। शरद पवार को अंदाजा हो गया था कि इस बार वे अजित और उनके ग्रुप को बांध नहीं सकेंगे, अजित पर ना तो पारिवारिक और ना ही उनका राजनीतिक दबाव काम आने वाला है, लिहाजा बुजुर्ग पवार ने पुणे में ही रहना उचित समझा। मुंबई जाकर अपनी भद पिटवाना उन्हें ठीक नहीं लगा।

इसका मतलब साफ है कि फिलहाल अजित का एनसीपी पर कब्जा हो गया है। चूंकि राजनीति में कई बार लड़ाइयां सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि अपने वोटरों और समर्थकों की नजर में सक्रिय बने रहने के लिए भी होती हैं। शरद पवार की लोगों से अपील है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली ताकतों को हराएं, एक तरह से ऐसी ही लड़ाई का प्रतीक है। शरद पवार के शब्दों से लग रहा था कि अब वे खुद को थका महसूस कर रहे हैं। चूंकि उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है। जाहिर है कि बढ़ती उम्र का उन पर असर भी है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले का ना तो चमत्कारिक व्यक्तित्व है और ना ही संगठन में गहरी पकड़, लिहाजा एक तरह से एनसीपी में शरद पवार का हाल कुछ-कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है, जैसा शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे का हुआ है।

● **बिन्दु माथुर**

अजित पवार के बहाने पैठ बनाने की कोशिश

भाजपा पिछले दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनावों से खुद के दम पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही है। जिस राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जिस राज्य की राजधानी में जनसंघ के आधुनिक रूप भाजपा का पहला अधिवेशन हुआ, उस राज्य में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने लायक नहीं बन पाई, तो उसे चिंता होनी ही चाहिए। इसलिए उसकी मौजूदा कोशिश और अजित पवार को साथ लाने को इस संदर्भ में भी देखा और समझा जाना चाहिए। सारे घोड़े खोलने के बावजूद भाजपा मराठवाड़ा में अपनी बड़ी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रही है। मराठवाड़ा और खानदेश में अब वह अजित पवार के बहाने पैठ बनाने की कोशिश करेगी। एक तथ्य पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। भाजपा के साथ जो भी दल आए, अपने सांगठनिक कौशल के चलते वह उन पर प्रकारांतर में हावी होती चली गई।

मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर

पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह रैलियां करके राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली। 31 मई को अजमेर में रैली कर मोदी ने बता दिया कि 2023 के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल जैसे हैं, जिन्हें मोदी किसी भी स्थिति में हारना नहीं चाहते हैं। राजस्थान में मोदी की जीत 2024 में वापसी में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, वहीं राजस्थान में भाजपा की विफलता मोदी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरोही जिले के आबू रोड में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया था। हालांकि अपेक्षा से बहुत कम लोग जुटने के कारण मोदी रात दस बजे के बाद ही सभास्थल पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों से लाउडस्पीकर उपयोग की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण भाषण नहीं दे पाने के लिए माफी मांग ली। इस सभा से उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, जालोर और पाली सहित आसपास के जिलों की 26 सीटों को साधने का प्रयास किया था। दक्षिण राजस्थान का यह इलाका भाजपा के लिए मजबूत माना जाता है। यहां की 26 में से पिछली बार भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक नवंबर 2022 को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सभा कर आसपास की 19 सीटों को साधा था। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जयंती समारोह में शामिल होकर भीलवाड़ा के आसींद में सभा की थी। यहां से उन्होंने गुर्जर समाज को भाजपा का साथ देने का संदेश दिया था।

चौथी बार 12 फरवरी, 2023 को मोदी दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर आए। यहां मोदी ने पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर की 58 विधानसभा सीटों को साधने के लिए गुर्जर-मीणा बहुल दौसा में सभा की थी। पांचवी बार 10 मई, 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा और आबूरोड में बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। छठी बार 31 मई, 2023 को मोदी ने अजमेर में रैली की थी। अजमेर रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी किया था। यहां से मोदी ने पूरे राजस्थान में भाजपा के मूल एजेंडे हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की थी। 8 महीने में मोदी के राजस्थान दौरों का आंकलन किया जाए तो वे लगभग 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। मोदी का अब तक का राजस्थान दौरा जाति-समाजों को साधने के मकसद से ही हुआ है। उनका फोकस आदिवासी, ओबीसी, गुर्जर-मीणा और एससी समुदाय रहा है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में हर हाल में सरकार बनाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।

भाजपा संगठन राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं राजस्थान के हर जिले में करवाने पर विचार कर रहा है। संभवत: भाजपा देश में ऐसा पहली बार प्रयोग करने जा रही है जब किसी चुनावी राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री सभा करेंगे। हालांकि गुटबाजी में फंसी प्रदेश भाजपा मोदी की अब तक की 6 रैलियों में अपेक्षा अनुरूप भीड़ जुटाने में बार-बार विफल रही है। इसलिए राजस्थान को लेकर भाजपा की रणनीति साफ है कि राजस्थान के चुनाव में मोदी ही भाजपा का चेहरा होंगे। बाकी गुटों में बंटे नेता मोहरे तो हो सकते हैं मुख्य चेहरा नहीं। भाजपा का आंकलन है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा और सभी गुट एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव के कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा एवं सहयोगी दल ने राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के साथ-साथ उसके तुरंत बाद होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें लगातार तीसरी बार जीतना चाहते हैं। भाजपा आस लगाए बैठी है कि मोदी के करिश्मे के कारण राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी।

भाजपा के पक्ष में एक और तर्क दिया जा रहा है कि 1998 के बाद से राजस्थान में कोई भी सरकार दूसरी बार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में भाजपा की सत्ता में वापसी की उम्मीदें बढ़ी हुई है। वहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस भी जनकल्याणकारी योजनाओं और वादों के दम पर सत्ता में बरकरार रहने की हर संभव कोशिश कर रही है। राजस्थान में सत्ता बदलती है या सत्ता बदलने का रिवाज, इसे देखने के लिए नवबंर या दिसंबर तक इंतजार करना होगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

7 जिलों में नहीं खुला था भाजपा का खाता

दरअसल, राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने गंभीर क्यों हैं, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 33 जिलों में से 7 जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। वैसे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़े गए 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 200 में से 163 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन 2018 में मोदी और वसुंधरा के बीच बढ़े तनाव के बीच हुए चुनावों में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने ही मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे लगाकर भाजपा को ही सत्ता से बाहर कर दिया। 2018 में मोदी और अमित शाह ने राजस्थान के चुनाव जीतने में कोई विशेष रूचि भी नहीं दिखाई थी, और अनमने ढंग से ही प्रचार किया था। इसके अलावा 60 से भी अधिक सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए और भाजपा के वोट काटकर कांग्रेस उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया। संगठन की ओर से ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को बिठाने के कोई प्रयास भी नहीं किए गए। इसके बावजूद 2018 में भाजपा को मिले कुल वोट और कांग्रेस को मिले कुल वोट में मात्र आधा प्रतिशत का फर्क रहा। आत्मघाती मानसिकता के साथ आधे अधूरे मन से लड़े गए 2018 के चुनावों में भाजपा का खाता जिन जिलों में नहीं खुला था उनमें सीकर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर शामिल हैं।

अंधेरे में उप्र

उप्र में इन दिनों जन सामान्य को बिजली के भारी संकट से दो-चार होना पड़ रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक में बिजली की आंखमिचौली का खेल किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बिजली कब आएगी एवं कब चली जाएगी? इसका किसी को कुछ नहीं पता। हर दिन घंटों के कट लगना सामान्य बात हो चुकी है। बिजली का यह संकट किसकी देन है? कुछ नहीं कहा जा सकता। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली माफिया योगी सरकार की नाक के नीचे से सारा खेल कर रहे हैं। बिजली माफिया किसकी मिलीभगत से ये खेल कर रहे हैं? इस पर अधिकारी ने कहा कि बिना सरकार की इच्छा के कहीं कुछ भी संभव होता है क्या? बिजली संकट कब तक रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर अधिकारी का मौन था, जिसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कुछ पता नहीं। जेठ की भरी गर्मी के बाद आषाढ़ की सड़ी गर्मी शुरू हो चुकी है एवं तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। घरों में रुकना दूभर है। गांवों में जिनके पास सोलर प्लेट लगी हैं, वे अपनी कुछ समस्या उसी के सहारे काट रहे हैं। मगर जिनके पास बिजली के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, वे बिजली आने की राह ही देखते रहते हैं। शहरों में बिजली का संकट गांवों की अपेक्षा थोड़ा कम है, मगर सामान्य नहीं है। शहरों में भी कई-कई घंटों तक बिजली गुल रहना सामान्य बात हो चुकी है। गर्मी से बेहाल गांवों के लोग पेड़ों की छांव में हाथों में हाथों से बने पंखे लेकर गर्मी दूर करने का निरर्थक प्रयास करने को विवश हैं।

धौंराटांडा के किसान रवि कहते हैं कि बिजली के संकट ने उप्र के किसानों का दुख दोगुना कर दिया है। इस वर्ष धान की पौध में पानी कम लगने से उसकी बढ़त कम हुई है। अब धान लगाने का समय चल रहा है। पानी ही नहीं होगा, तो धान कैसे लगाएंगे? जिन किसानों ने धान लगा दिए हैं, उनकी धान फसल पानी की कमी से पीली पड़ने की स्थिति में है, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है। बारिश हो नहीं रही है एवं बिजली आ नहीं रही है। डीजल की महंगाई ने खेती को इतना महंगा कर दिया है कि उससे अच्छा किसान चावल खरीदकर खा ले। खेतों की जुताई, मजदूरों की मजदूरी, पानी एवं खाद की लागत आदि सबको जोड़ें तो एक बीघा धान की लागत 3,000 से 3,500 रुपए तक आती है, जबकि एक बीघा खेत में कड़े परिश्रम के बाद 4,500 से 5,000 रुपए का धान निकल पाता है। अगर मौसम बिगड़ा अथवा आवारा पशुओं ने खेती उजाड़ दी, तो लागत भी नहीं लौटती। अगर मान भी लें कि खेती अच्छी हो गई, तो भी एक बीघा में 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 1,000 से 1,500 रुपए ही मिलते हैं। अगर किसान अपनी मेहनत जोड़ें, तो घाटा अगर खेत की भी 6 महीने की कीमत जोड़ें, तो उससे भी बड़ा घाटा दिखेगा। मगर किसानों के भाग्य ही फूटे हुए हैं। कभी किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तो कभी सरकार की बेरुखी की मार झेलनी पड़ती है। सामान्य सी बात है कि धान के खेतों में लगातार पानी रहना चाहिए। अगर धान के खेतों में पानी नहीं रहता है, तो वो चटकने लगते हैं। इससे धान के पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। धान के पौधे तभी ठीक से विकसित होते हैं, जब उनमें लगाने के समय से लेकर बाली में भरपूर दाना पड़ने तक पानी रहता है।

उप्र के सभी 75 जनपदों में बिजली संकट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोग बिजली संकट से त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली संकट पर अपने मातहतों को फटकार लगा रहे हैं, मगर कोई सार्थक प्रयास न कर सकना उनकी विवशता है अथवा विफलता? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर इतना अवश्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली आपूर्ति के तमाम दावे विफल हो चुके हैं। 24 घंटे बिजली देने के दावे गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के दावे एवं पिछली सरकारों से अधिक बिजली आपूर्ति के दावे की हवा निकल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं उनकी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार असमर्थ दिख रही है।

शाहजहांपुर निवासी महेश शर्मा का कहना है कि उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे तहसीलों में एवं 20 घंटे गांवों में बिजली देने के अपने ही वादे पर नहीं टिक सकी है। अब तो बिजली संकट है, सामान्य बिजली आपूर्ति के दिनों में भी सरकार के वादे के अनुरूप बिजली कभी नहीं आई। घंटों के कट पहले लगते थे, अब शहरों में 4-4 घंटे से अधिक समय के कट लग रहे हैं, तो गांवों में 12 से 14 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। कहीं-कहीं तो 24 घंटे दूर, कई-कई दिन तक बिजली नहीं रहती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

ऊर्जा मंत्री ने झाड़ा पल्ला

उप्र के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक ट्वीट इन दिनों चर्चा में है। ऊर्जा मंत्री ने इसमें कहा है कि 2012-17 के बीच बिजली की अधिकतम मांग 13,598 मेगावॉट थी एवं अब 2023 में बिजली की मांग बढ़कर 27,611 मेगावॉट हो गई है। जून 2022 में बिजली की अधिकतम मांग 26,369 मेगावॉट की थी। वर्तमान में न्यूनतम बिजली की मांग 22,000 से अधिक मेगावॉट है। ये मांग अप्रत्याशित एवं ऐतिहासिक है। आज तक बिजली की इतनी मांग नहीं हुई थी। इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने अपनी नाकामी का भांडा मौसम पर भी फोड़ते हुए कहा है कि 2012 में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक ही रहता था, मगर तापमान बढ़ते-बढ़ते 2023 में 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस वजह से भी बिजली की खपत बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री की अजब-गजब बातें कितनी सही हैं, कितनी हास्यास्पद हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में पूरे उप्र में सरकारी एवं संविदा पर लगभग 10,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 37,000 कर्मचारी नियमित हैं जबकि 68,000 कर्मचारी संविदा पर हैं। मगर बिजली विभाग में कम से कम 2,65,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। सन् 2012 में बिजली विभाग में 42,000 नियमित कर्मचारी थे। इसका अर्थ यही हुआ कि पूर्ववर्ती सरकारों से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग में नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जगह उलटा 6 वर्षों में 5,000 कर्मचारी कम कर दिए। स्थिति यह है कि संविदा पर कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को भी नियमित नहीं किया जा रहा है, जो अर्हता रखते हैं।

अगड़ी जातियों की अहमियत

बिहार की राजनीति यही कोई तीन दशक से गैर सवर्ण जातियों के इर्द-गिर्द घूमती आई है। खास तौर पर पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व इतना बढ़ा कि इस तबके से आने वाले लालू यादव-राबड़ी देवी-नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते आए हैं। हालांकि एक दौर वह भी रहा है, जब मुख्यमंत्री अगड़ी जातियों के ही होते थे। 90 के दशक में जब मंडल-कमंडल की राजनीति ने अपने पांव फैलाए, तो देश के तमाम दूसरे राज्यों की तरह बिहार की सियासत का नक्शा भी बदल गया। लेकिन हाल के दिनों में, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक वहां अगड़ी जातियों की अहमियत बढ़ गई है।

बिहार में अगड़ी जातियों की आबादी 15 से 20 प्रतिशत के बीच है। एक वक्त यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थीं, लेकिन बाद में भाजपा के साथ आईं। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन में होने की वजह से इनका समर्थन जदयू को मिलता रहा। लेकिन पिछले चुनाव में यह देखा गया कि सवर्ण जातियों ने भाजपा को तो वोट किया, लेकिन जदयू को नहीं। यही वजह रही कि जदयू को पहली बार भाजपा से कम सीट मिलीं और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या के क्रम में तीसरे पायदान पर पहुंच गई।

राजनीति में बिना मकसद कुछ भी नहीं होता। अगर बिहार में अगड़ी जातियों की पूछ बढ़ गई है, तो उसकी वजह भी है। बिहार में जिस तरह से भाजपा तनकर खड़ी हुई है और जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी जैसे अपनी-अपनी जातियों के नेताओं का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ है, उसमें आरजेडी को लगने लगा है कि एमवाई समीकरण के सहारे राज्य की सत्ता में वापसी मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव के मौके पर कहा भी था कि अब हम एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी होंगे। इसी कोशिश में वह अगड़ी जातियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मार्च महीने में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में यह बात साफ दिखी भी। राज्य में पिछड़ा वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले आरजेडी और जेडीयू, दोनों को अब यह अहसास हो चला है कि अगड़ी जातियों का साथ लेकर ही वे अपने वोट बैंक का विस्तार कर सकते हैं।

अब कांग्रेस को ही देखें। कांग्रेस ने बिहार के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी की है उनमें करीब 50 प्रतिशत ब्राह्मण और भूमिहार जाति से हैं। कुल 39 जिलाध्यक्षों में से करीब 66 प्रतिशत अगड़ी जातियों से हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार कांग्रेस के 39 जिलाध्यक्षों को नियुक्त किया है। इनमें से 11 भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 5 मुस्लिम, 4 यादव, 3 दलित, 1 कुशवाहा और 1 कायस्थ जाति से हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी भूमिहार जाति से ही हैं। हालांकि नीतीश सरकार में कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों में से एक दलित, एक मुस्लिम है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में कांग्रेस की रणनीति भूमिहार और ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने की है जिन्हें भाजपा का वोटर माना जाता है। बीते कुछ समय से भाजपा बिहार में पिछड़े वोटर को लुभाने में लगी है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी नीतीश और लालू के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट मिलने का भरोसा है। हालांकि बिहार में अगड़ा समीकरण साधने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने रायपुर अधिवेशन के उस अहम ऐलान को भुला दिया जिसमें ब्लॉक से लेकर सीडब्ल्यूसी तक 50 प्रतिशत पद ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित करने की बात कही गई थी।

कांग्रेस ने पश्चिमी चंपारण में भारत भूषण पांडेय, पूर्वी चंपारण में शशि भूषण राय, मुजफ्फरपुर में अरविंद मुकुल, सीतामढ़ी में कमलेश कुमार सिंह, गोपालगंज में ओम प्रकाश गर्ग, मधुबनी में मनोज मिश्रा, दरभंगा में सीता राम चौधरी, समस्तीपुर में अबू तमीन और सहरसा में मुकेश झा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने सुपौल से विमल यादव, मधेपुरा से सतेंद्र कुमार यादव, अररिया से जाकिर हुसैन, पूर्णिया से नीरज सिंह, किशनगंज से इमाम अली, कटिहार से सुनील यादव, भागलपुर से परवेज जमाल, बांका से कंचन सिंह, लखीसराय से अमरीश कुमार अनीस, शेखपुरा से सत्यजीत सिंह, जमुई से राजेंद्र सिंह, बेगुसराय से अभय कुमार, नालंदा से रवि ज्योति को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पटना महानगर से शशि रंजन, पटना ग्रामीण 1 से सुमित कुमार सनी, पटना ग्रामीण 2 से रघुनंदन पासवान, भोजपुर से अशोक राम, बक्सर से मनोज कुमार पांडेय, रोहतास से कन्हैया सिंह, कैमूर से सुनील कुशवाहा और गया से गगन कुमार मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने जहानाबाद से गोपाल शर्मा, अरवल से धनंजय शर्मा, औरंगाबाद से राकेश कुमार सिंह, नवादा से सतीश कुमार, सारन से अजय कुमार सिंह, वैशाली से मनोज शुक्ला, सिवान से बिधुभूषण पांडेय और सिहोरा से नूरी बेगम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार में जातियों का दबदबा

बिहार में मुख्य रूप से चार बड़ी अगड़ी जातियां हैं- भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। राजनीतिक गलियारों में उन्हें सांकेतिक भाषा में भूराबाल कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम-यादव समीकरण को एमवाई कहते हैं। नब्बे के दशक में जब बिहार की राजनीति में लालू युग शुरू हुआ, तो उनको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। कहा यह गया कि लालू ने बिहार की राजनीति में भूराबाल को साफ करने की बात कही है। हालांकि लालू यादव इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। खैर, सच्चाई जो भी रही हो, लेकिन इस विवाद के बाद वहां लालू यादव की छवि एंटी अपर कास्ट नेता के रूप में उभरी। लालू यादव ने भी इसकी परवाह किए बिना यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग-दलित वर्ग की कुछ अन्य जातियों को गोलबंद कर अपने को मजबूत बनाए रखा।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

फौज जीतेगी या इमरान

पाकिस्तान के हालात हर रोज बदल रहे हैं और इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानियों पर भी दिख रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की सड़कों पर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में मौजूद पाकिस्तानी मूल के लोगों ने गो नवाज गो के नारों के साथ पाकिस्तानी झंडे लहराए और नवाज के बेटे के दफ्तर की दीवारों पर पेंट पोत दिया। नवाज शरीफ लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग (पीएनएमएल) उस गठजोड़ की अहम हिस्सेदार है, जिसकी फिलवक्त पाकिस्तान में सरकार है। साथ ही उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान में वजीरे आजम हैं। हालांकि इस मिलीजुली सरकार में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और कुछ दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा न सिर्फ लगभग पूरे पाकिस्तान में फैल गई, बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए।

दरअसल पिछले साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की अगुवाई में वजीरे आजम इमरान खान की सरकार को नेशनल असेंबली में अहमियत रखने वाली सभी विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिरा दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ की अगुवाई में मिलीजुली सरकार बनी। इमरान इस अपमान को पचा नहीं पाए और उन्होंने फौजी हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि विदेशी साजिश के तहत फौज की मिलीभगत से उनसे गद्दी छीन ली गई। हालांकि वे फौज की मदद से ही चुनाव जीतकर आए थे और तब विपक्ष ने भारी चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। लेकिन शायद तब के जनरल कियानी की जगह अपने खास जनरल को फौज प्रमुख बनाने की बात पर फौजी हुक्मरानों के साथ उनकी ठन गई तो रिश्ते छत्तीस हो गए। इस दौरान पाकिस्तान की माली हालत भी लगातार बिगड़ती गई। इमरान सरकार की उच्च वर्ग समर्थित नीतियों की बनिस्बत मुल्क पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और महंगाई लोगों का जीना हराम कर रही थी, जो अभी भी संभल नहीं पाई है। हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। खैर, फौज के खफा होने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों को इमरान को सत्ता से बेदखल करने का मौका मिल गया।

इमरान ने इसके खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला और देशभर में घूमकर मजहबी भावनाओं के सहारे अपने साथ हुई गैर-इंसाफी और फौज के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने की कोशिश करते रहे। इसमें वे एक हद तक कामयाब भी हुए। कई उपचुनावों और प्रांतीय चुनावों में उनकी पार्टी पीटीआई की जीत हुई। शायद इसका असर यह हुआ कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमों को आगे बढ़ा दिया। इसमें सबसे खास तोशखाना मामला है, जिसमें बतौर वजीरे आजम मिले तोहफों को सरकारी खजाने से औने-पौने दाम पर खरीदकर भारी मुनाफे में बेचना शामिल है। पाकिस्तान में यह भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे मामले नवाज शरीफ जैसे कई नेताओं पर भी चले हैं।

हाल में एक निचली अदालत के समन पर लगातार गैर-हाजिर रहने पर इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भारी आंदोलन भड़क उठा। पिछले एक महीने से जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें कभी इमरान तो कभी फौज का पलड़ा भारी दिखता है। इस दौरान पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से अदालत में पेश होने के लिए जाते वक्त इमरान को गिरफ्तार किया गया, उनको घसीटा गया और उनके समर्थकों को पीटा गया, उसके नजारे परेशान करने वाले थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और आगे किसी भी मामले में गिरफ्तार न करने का आदेश भी दिया। लेकिन मौजूदा शहबाज सरकार की सियासी वजहों से तनाव कम करने में दिलचस्पी नहीं दिखती है। शायद सरकार चुनाव को जितना संभव हो टालना चाहती है और इमरान की पार्टी पीटीआई की लोकप्रियता का ग्राफ कुछ नीचे लाना चाहती है। फौजी हुक्मरानों की नाराजगी का अलम यह है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा को ब्लैक डे घोषित किया और उपद्रवियों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात की।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सत्ता बदलते लंदन का रुख

एक महीने में हालात इतने करवट ले चुके हैं कि 70 साल के इमरान खान के लिए इससे पार पाना आसान नहीं दिखता। जब-जब पाकिस्तान में सत्ता में उलटफेर होता है वहां के सत्ताधीश लंदन का रुख करते हैं। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ का उदाहरण सामने है। शायद इमरान खान के पास भी पाकिस्तान से भागकर ब्रिटेन में पनाह लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न बचे। ऐसा सोचने की ठोस वजहें भी हैं। खबर है कि शहबाज शरीफ ने यह ऑफर इमरान खान को दिया है और सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद उनके घर को घेर लिया गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि सरकार और आर्मी चीफ इस कोशिश में जुटे हैं कि इमरान का मामला किसी तरह से आर्मी कोर्ट के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इमरान के लिए खतरनाक हो सकता है। उन हालातों में इमरान को उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है। पाकिस्तान का इतिहास ऐसी कारगुजारियों का गवाह भी रहा है जब ऐसे ही हालात में जनरल जिया-उल-हक ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था। हालांकि इस बार परिस्थितियां कुछ अलहदा हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हुआ ऐसे में न तो आर्मी चीफ के लिए यह फैसला ले पाना आसान होगा और न ही इमरान के लिए देश छोड़ भाग पाना। आर्मी चीफ वही जनरल मुनीर हैं जो इमरान के कार्यकाल में आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। लेकिन इमरान से उनकी खटपट शुरू हो गई थी। कहते हैं, मुनीर एक रोज एक फाइल लेकर इमरान के पास पहुंचे जिसमें उनकी बीवी बुशरा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उसके कुछ ही समय बाद इमरान ने उनको आईएसआई चीफ के पद से हटवा दिया था।

इस्लामोफोबिया में फंसा यूरोप

27-28 जून को यूरोप के दो अलग-अलग देशों में बिल्कुल विपरीत घटनाएं घटित हुईं। पहली घटना फ्रांस से जुड़ी है जहां 27 जून को पेरिस के उपनगर न्येरेरे में एक 17 साल के अल्जीरियन मुस्लिम किशोर नाहल को फ्रेंच पुलिस ने इतनी बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में दबोच लिया कि वह मर गया। वहीं 28 जून को यूरोप के ही एक दूसरे देश स्वीडन में इराकी मूल के एक 37 साल के नौजवान सलवान मोमिका ने मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को न सिर्फ पैरों से ठोकर मारी बल्कि उसे जला भी दिया। यह सब उसने न केवल स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने किया बल्कि इसके लिए उसने स्वीडिश प्रशासन से अनुमति भी ले रखी थी।

दोनों घटनाओं पर दो तरह की प्रतिक्रिया हुई है। स्वीडन में कुरान जलाने की जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल इस्लामिक देशों ने बल्कि अमेरिका और स्वीडन ने भी निंदा की है। हालांकि अमेरिका और स्वीडन ने यह भी कहा है कि उसने जो किया हम उसका समर्थन नहीं करते लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी ओर पेरिस में नाहल की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन पेरिस सहित फ्रांस के दूसरे कई शहरों में 29 जून से दंगा भड़का हुआ है। इन दंगों के पीछे लेफ्ट और इस्लामिस्ट लोगों का गठजोड़ बताया जा रहा है।

नाहल के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला किशोर था जो बार-बार जानबूझकर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता था। 2021 से 2023 के बीच उसके ऊपर अलग-अलग क्रिमिनल ऑफेंस की शिकायतें दर्ज दीं। जिस पेरिस शहर को इतना स्वनियंत्रित शहर कहा जाता है कि वहां स्वभाव से लोग नागरिक नियमों का पालन करते हैं वहां नाहल पूरी तरह से अनियंत्रित होकर विचरता था। 17 साल की उम्र में ही उसके नाम 15 क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज थे और पांच बार उससे पूछताछ की जा चुकी थी। फ्रेंच वेबसाइट यूरोप1 के मुताबिक मार्च और अक्टूबर 2021 में उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन पुलिस लॉकअप से ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जनवरी 2022 में उसे चिल्ड्रन कोर्ट में पेश किया गया जहां जज ने उसको शिक्षित होने का आदेश दिया। इसके बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह गलत लाइसेंस प्लेट लगाकर गाड़ी चला रहा था। जनवरी और मार्च 2023 में उसे ड्रग्स बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

नाहल एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला लड़का था इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस उसे इतना टार्चर करे कि वह मर जाए। इसीलिए उन पुलिसवालों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया जिन पर नाहल की हत्या का आरोप है। मामला इतने में रफा-दफा हो जाना चाहिए था। लेकिन मामला रफा-दफा हुआ नहीं। 28 जून की रात से जो दंगा शुरू हुआ वह अब तक रुका नहीं है। पेरिस में जगह-जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं की गई हैं। फ्रांस के दूसरे बड़े शहर मर्साइ में वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। सरकारी संपत्तियों को जहां-तहां आग के हवाले किया जा रहा है और 40 हजार पुलिस बल मैदान में उतार दिए जाने के बाद भी फ्रांस में उपद्रव, आगजनी और दंगे थमे नहीं हैं। फ्रांस वह देश है जहां के फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दुनिया को दो विचारधाराएं दी। जो जार या राजा के खिलाफ विद्रोही थे उनको लेफ्ट कहा गया और जो जार के समर्थक थे उनको राइट। इस लेफ्ट और राइट के बंटवारे की बुनियाद जिस फ्रांस में पड़ी आज वह उसी बंटवारे का शिकार है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही उभरकर सामने आया है कि फ्रांस में लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट समूहों ने हाथ मिला लिया है और नाहल की मौत के बहाने पूरे फ्रांस को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ नाहल की मौत तक नहीं सीमित है।

बीते कुछ सालों में यूरोप के अधिकांश देशों में इस्लामिक चरमपंथ और उसके खिलाफ क्रिश्चियन प्रतिरोध बढ़ा है। नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, इटली और फ्रांस में बार-बार इसके खिलाफ आवाजें उठती रहीं हैं। फ्रांस ही वह देश है जहां की एक पत्रिका चार्ली हाब्दो ने बार-बार मुस्लिमों के पैगंबर का कार्टून बनाया जिससे दुनियाभर के मुस्लिमों में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। खासकर यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का आवेदन करने वाले इस्लामिक देश तुर्की ने एक अलग गुट बनाकर पाकिस्तान और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों को मुखरता से इस विरोध में शामिल करवाया। लेकिन खुद फ्रांस ने इन विरोधों से अधिक नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी को अधिक महत्व दिया।

● **कुमार विनोद**

यूरोप को अरब बनाने की मुहिम चल रही

फ्रांस में 9 से 10 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। फिर भी फ्रांस इस तरह से कभी इस्लामिक उपद्रव का शिकार नहीं हुआ। उस समय भी नहीं जब मुस्लिमों के पैगंबर का कार्टून वाला विवाद हुआ था। जो प्रतिक्रिया हुई वो बाहर से वहां जाकर बसे मुस्लिमों ने ही अधिक दी। इसका कारण संभवतः फ्रेंच मुस्लिमों की वह समझ है जो किसी की अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को समझते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पूरे यूरोप में धीरे-धीरे ये बात प्रचारित हो चली है कि यूरोप को अरब बनाने की नीति पर काम चल रहा है। इसे उन्होंने यूरोबिया का नाम दिया है। यूरोपीय समुदाय में एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि यूरोप को अरब बनाने की मुहिम चल रही है। इसलिए एक ओर जहां मुस्लिम अप्रवासी तेजी से यूरोप की ओर आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम वहां रह रहे हैं उनकी प्रजनन दर ईसाईयों के मुकाबले अधिक है। इसके अलावा ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी करने के लिए ग्रूमिंग गैंग भी चल रहे हैं जिसे लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर खुलकर बोल ही चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा नैरेटिव भी यूरोप में चल रहा है जिसे इस्लामोफोबिया कहा जा रहा है। जो देश, समुदाय या व्यक्ति इस्लामिक अतिक्रमण की बात करते हैं उनको इस्लामोफोबिक बताकर महत्वहीन करने का प्रयास भी किया जाता है। इटली की नेशनलिस्ट लीडर जार्जिया मिलोनी ने हाल में जब इस्लामिक अतिक्रमण को रोकने के लिए नए कानून का मसौदा पेश किया तो उन पर भी यही इस्लामोफोबिया का आरोप लगा दिया गया। मुख्य रूप से इस्लामोफोबिया का नैरेटिव दुनियाभर में लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट ग्रुप चलाते हैं जो यहां भी वही कर रहे हैं।

बेटियों की हत्याएं, करती हैं बेचैन

23 मई 2023 को देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिणामों की घोषणा हुई। इस बार एक बार फिर बेटियों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी। टॉप-10 में से 6 स्थानों पर लड़कियां हैं। इस खबर से पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। हर ओर बेटियों की प्रतिभा, लगन और मेहनत के किस्से सुनाए जाने लगे। यूपीएससी ही नहीं, पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी दसवीं, बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों में भी बेटियों ने प्रथम पंक्ति में अपना नाम दर्ज करवाया है।

बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। यूपीएससी के नतीजों की घोषणा के ठीक पांच दिन बाद यानी 28 मई को उप्र के पीलीभीत जिले में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन वो बच्ची उतनी खुशनसीब नहीं थी कि वो अच्छे से पढ़-लिखकर किसी प्रतिष्ठित परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करती और अपने घर-परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन कर पाती। दरअसल, अब वो प्यारी सी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। उस प्यारी सी बच्ची को उसके पिता ने ही मार डाला। मामला उप्र के पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र का है। जहां एक पिता ने तीसरी बार बेटी पैदा होने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। खानका मोहल्ले की रहने वाली शब्बो की शादी 8 साल पहले सिरसा गांव के रहने वाले फरहान के साथ हुई थी। शादी के बाद शब्बो ने दो बेटियों को जन्म दिया। इसके बाद वह फिर से गर्भवती हुई।

प्रसव पीड़ा होने पर मायके वाले शब्बो को ससुराल से लेकर एक नर्सिंग होम पहुंचे। यहां 28 मई को उसकी डिलीवरी हुई। उसने एक प्यारी-सी बच्ची को जन्म दिया। अगले दिन देर शाम फरहान अपनी पत्नी और बच्चे को देखने वहां पहुंचा। फरहान ने बच्ची को गोद में लेते हुए जैसे ही देखा कि वह बेटी है, उसे जमीन पर पटक दिया। जिससे बच्ची की मौत हो गई। असल में फरहान दो बेटियों के बाद बेटा चाहता था, लेकिन बेटी होने पर उसने ऐसा कदम उठा लिया। 31 मई 2023 को उप्र के गाजियाबाद जिले के हिंडन विहार कॉलोनी में रहने वाली तबस्सुम ने थाना नंद ग्राम में अपनी ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेटी होने पर विवाहिता के घर वालों से 10 लाख रुपए की मांग की गई। जब वह मांग पूरी नहीं हुई तो उसे तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में पोते की चाह में दादी ने अपनी 15 दिन की नवजात पोती को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में आरोपी दादी मिताली विश्वास ने बताया कि वो पोता चाहती थी, जबकि बहू को पोती हुई, जिससे वो काफी नाराज थी। 1 अप्रैल 2023 को जब घर के सभी लोग दोपहर में सो रहे थे, तो उसने मां के पास सो रही बच्ची को चुपचाप उठा लिया। इसके बाद बाड़ी में स्थित कुएं में बच्ची को फेंक दिया। जिससे नवजात की मौत हो गई। बेटियों को गर्भ में ही मार देने का बढ़ता क्रम रोकने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए गए। सरकार से लेकर समाजसेवी लोगों ने अनेक तरह से जागरूकता फैलाई गई। इसका असर भी देखने को मिला लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह लोग बेटी पैदा होने पर खुशी मना रहे हैं, उसे देख लग रहा है कि बेटियों को लेकर समाज की सोच में बदलाव आना शुरू हो चुका है। 6 मार्च 2022 को बिहार के बेतिया जिले के मैनाटां प्रखंड के चपरिया गांव के रहने वाले शेषनाथ कुमार ने अपनी दूसरी बेटी के जन्म का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। शेषनाथ कुमार हेल्थ सेंटर से फूलों और गुब्बारों से सजी कार में अपनी नवजात बेटी को घर लेकर आए। अक्टूबर 2022 को मप्र के जिले बुरहानपुर के नेपानगर के बुधवारा मार्केट में रहने वाले चौकसे परिवार में नन्हीं परी ने जन्म लिया। वो हुई तो महाराष्ट्र में अपने नाना के घर। तीन महीने की होने पर मां उसे लेकर दादा-दादी यानी अपने ससुराल आई। पहली बार कन्या के घर आने की खुशी में बेटी के ताऊ ने घर फूलों से सजा दिया। बैंड बाजा बुलवाए गए। पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की गई। ऐसा करके परिवार ने बेटा-बेटी एक समान होने का संदेश दिया है।

हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात बेहद कम है, उसी हरियाणा में दिसंबर 2015 को जींद जिले के जैजैवंती गांव निवासी संदीप ने बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई और जश्न में पांच गांवों के लोगों को भोज कराया। जनवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी जिला के गांव सुई में जसवंत सिंह गहलोत ने अपनी बेटी के जन्म पर पूरे घर को फूलों से सजाया तथा ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरक कर बेटी के जन्म की खुशियां मनाई। मप्र के छिंदवाड़ा के रहने वाले प्रशांत उईके जय बजरंगबली मंगोड़े के नाम से दुकान चलाते हैं। दिसंबर 2022 को घर बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म की खुशी पर प्रशांत ने अपने ग्राहकों को फ्री में मंगोड़े खिलाए। आसपास के लोग भी प्रशांत की इस खुशी में शामिल हुए।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

आज की नारी, सब पर भारी

आज की बेटियां आत्मविश्वासी, निडर, सुलझी हुई हैं। ऐसे में वे हर काम करने में सक्षम हैं। वहीं आज दुनियाभर में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जिसमें लड़कियां अपना नाम ना कमा रही हों। वे शिक्षा, चिकित्सा, सेना, पुलिस, खेल, विज्ञान हर जगह में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। इसलिए इनके बारे में कहा भी जाता है कि आज की नारी, सब पर भारी ऐसे में वे स्वयं के साथ अपने माता-पिता व परिवार का मान-सम्मान बढ़ा रही हैं। यही भारत का असली विकास है। यह विकास केवल गिने-चुने क्षेत्रों में नहीं बल्कि बहुत से क्षेत्रों में है और सुखद यह है कि उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। आज के बदलते दौर में देखा जाए तो असल में, बेटियां अब बोझ नहीं रहीं, अब वह भी लड़कों की तरह बराबर खड़ी हैं। वे हर कदम व परिस्थिति पर माता-पिता और परिवार के मान-सम्मान का ध्यान रखती हैं। शास्त्रों में भी नारी का सम्मान करने के बारे में लिखा है। उसे पूजनीय व देवी माना गया है। एक औरत से ही घर का वंश आगे बढ़ता है। ऐसे में उसे मारने या सम्मान ना देने की गलती ना करें।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

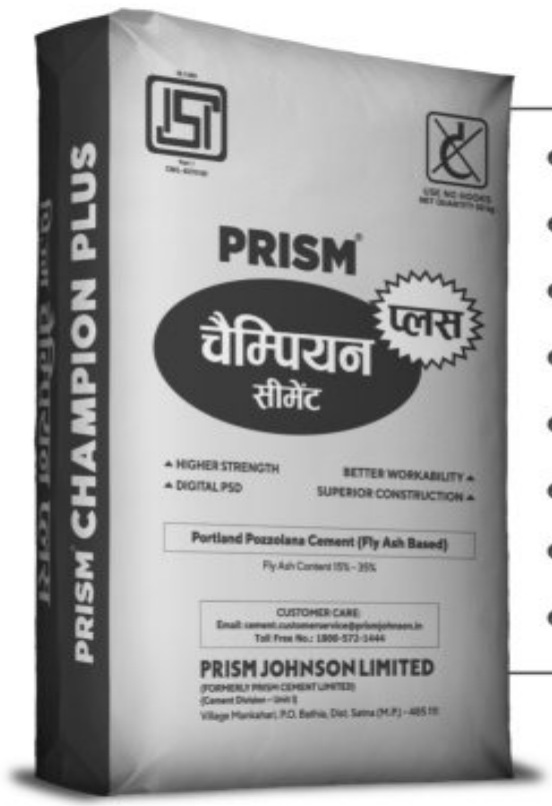

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

नाम

यार रजनीश, मैं सोच रहा हूं कि अबकी बार किसी धार्मिक यात्रा पर कोई बड़ा सा लंगर लगवाऊं, ऐसा लंगर कि लोग देखते ही रह जाएं और मेरी तारीफ करें..., सौरभ ने अपनी इच्छा प्रगट करते हुए कहा।

तो उससे क्या होगा? दोस्त बोला।

क्या होगा? धर्म का काम है, और फिर मेरा नाम भी होगा, और क्या..., सौरभ ने कहा।

कोई फायदा नहीं। लोग आएंगे, खाएंगे-पीएंगे और चले जाएंगे। कोई तारीफ करेगा, कोई नुक्स निकालेगा, फिर भूल जाएंगे। और याद भी रख लेंगे तो कितने दिन? तो उससे फायदा क्या...? रजनीश ने कहा, अगर नाम ही करना है और पैसा ही खर्च करना है, तो और भी कई उपाय हैं नाम कमाने के...।

और कौन से भला? सौरभ रजनीश की तरफ देखने लगा।

गरीब बच्चों को पढ़ाओ, किसी मुसीबत में फंसे, मजबूर या जरूरतमंद की मदद करो। अपने आसपास पेड़-पौधे लगवाओ, गर्मियों के लिए वाटर-कूलर का प्रबंध और सर्दियों में कम्बल इत्यादि बांटने जैसे काम कर सकते हो। वृद्ध-आश्रम या अनाथ-आश्रम हैं, जहां पैसा खर्च किया जा सकता है। बच्चों-बड़ों-महिलाओं को शिक्षित करने या लोगों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए कैंप लगवा सकते हो..., और ऐसे न जाने कितने और भी छोटे-बड़े कार्य तुम कर या करवा सकते हो, जिनसे न केवल जन-कल्याण और पर्यावरण के संरक्षण जैसे काम होंगे, बल्कि तुम्हें आदर और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यानी तुम्हारा नाम होगा। केवल धर्म के नाम पर चंदा देने या लंगर लगवा देने से कोई लाभ नहीं..., उसके लिए तो और हजारों-लाखों लोग पहले से मौजूद हैं...।

यार तूने तो मेरी आंखें खोल दीं..., कह कर सौरभ ने रजनीश को गले लगा लिया।

- विजय कुमार

उम्र की सच्चाई

इतनी लंबी उम्र मिली है,
पर जीने का वक्त नहीं,
रिश्तों की भरमार है पर,
रिश्तों का अस्तित्व नहीं ,
चेहरे पे मुस्कान सभी के,
दिल में क्या है स्पष्ट नहीं,
झूठी तारीफों के पुल पर,
सच्चाई का वक्तव्य नहीं,
जेब की दौलत लुटवाओ तो,
यारों की है लाइन लगी,
पर मुश्किल में मदद मांग लो,
फिर तो कोई साथ नहीं।
खून के रिश्ते खून हो गए,
अब सांझा बहता रक्त नहीं
रिश्ते नाते मार दिए सब,
पर दफनाने का वक्त नहीं,
मंदिर-मस्जिद जहां भी देखो
जन मानस की भीड़ लगी,
प्रभु के आदर्शों पर जीवन,
जीने वाले पर भक्त नहीं,
सुख में सब लगते हैं अपने,
लगते है आसक्त सभी,
पर जब खोजा दुख में हमने,
मिले हमें विरक्त सभी
अपना अपने को पहचाने,
गए वक्त की बातें हैं,
जीवन रस की चाह सभी को,
पर पीने का वक्त नहीं,

- जय प्रकाश भाटिया

सपना

विद्यालय का वार्षिकोत्सव चल रहा था। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न थे। सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के खेलकूद तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। उसने भी इन सबमें बढ़-चढ़कर भाग लिया था। पुरस्कार वितरण हेतु क्षेत्र के विधायक महोदय पधार चुके थे। एक-एक कर विजेताओं को विधायक जी पुरस्कृत करते जा रहे थे। प्रधानपाठक विजयी छात्रों का नाम पुकारते जा रहे थे।

और अंत में मैं माननीय विधायक जी निवेदन करूंगा कि वे हमारे विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र को अपने कर-कमलों से शील्ड प्रदान कर सम्मानित करें, जिसने पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ वार्षिकोत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में से तीन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उस छात्र का नाम है- चुन्नीलाल।

उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वह शील्ड लेने जा रहा था। वह उड़ा जा रहा था। मानो उसके पंख लग गए हों।

तभी किसी के जूते की ठोकर से उसकी आंख खुल गई। बड़े मालिक बड़बड़ा रहे थे। अबे, चवन्नी उठ्ठ, स्साले। कब तक सोता रहेगा। चल जल्दी से रात का बर्तन साफ कर दे। नल भी खुल गया है, फिर पानी भी भरना है।

और चुन्नीलाल उर्फ चवन्नी का सपना, सपना ही रह गया। वह सोच रहा था काश! सपने भी सच होते।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

यह कैसी टीम चुनी?

हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब भारतीय क्रिकेट टीम को हार झेलनी पड़ी थी, तो कई तरह से सवाल खड़े हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि वेस्टइंडीज दौरे पर चयनकर्ता टीम के कमजोर पक्षों पर काम करेंगे और एक मजबूत टीम खड़ी करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जब से टीम का चयन हुआ है तब से चयनकर्ता खेल विशेषज्ञों के निशाने पर आ गए हैं। टीम चयन ने यह विवाद भी छेड़ दिया है कि क्या टेस्ट टीम का चयन रणजी ट्रॉफी के आधार पर ना कर आईपीएल के आधार पर किया गया है? क्या भविष्य में टेस्ट टीम आईपीएल के आधार पर चुनी जाएगी?

भारतीय क्रिकेट टीम का इस साल एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए चयन होना है। ऐसे में सेलेक्शन कमेटी का रोल काफी अहम हो जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब टीम को हार झेलनी पड़ी थी तो कई तरह से सवाल खड़े हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय सेलेक्टर्स टीम के कमजोर पक्षों पर काम करेंगे और एक मजबूत टीम खड़ी करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जब से वेस्टइंडीज दौरे के लिए खासकर टेस्ट टीम का चयन हुआ है, तब से चयनकर्ता खेल विशेषज्ञों के निशाने पर आ गए हैं। इस टीम चयन ने यह विवाद भी छेड़ दिया है कि क्या टेस्ट टीम का चयन रणजी ट्रॉफी के आधार पर न कर आईपीएल के आधार पर किया गया है? क्या भविष्य में टेस्ट टीम आईपीएल के आधार पर चुनी जाएगी?

इसकी वजह लगातार 3 सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे सरफराज खान को नजरअंदाज करना तो है ही, साथ ही घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे कई खिलाड़ियों के ऊपर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तरजीह देना है। इस वजह से खेल विशेषज्ञ भड़के हुए हैं और वे रणजी ट्रॉफी की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। जिनमें सुनील गावस्कर, वसीम जाफर जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। दरअसल सुनील गावस्कर ने चेतेश्वर पुजारा को बाहर करने के साथ ही सरफराज को शामिल नहीं करने पर सवाल उठाए थे। अब पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने टीम चयन पर सवाल उठाए हैं। वसीम जाफर ने तीन बड़े सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल है कि चार ओपनर की टीम में क्या जरूरत थी। चयनकर्ता मध्यक्रम में सरफराज खान का चयन कर सकते थे, वे लगातार घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहे हैं।

दूसरा सवाल ईश्वरन और पंचाल रणजी और इंडिया ए के लिए लगातार अच्छा कर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वे आईपीएल नहीं खेलते हैं तो क्या इसी वजह से उनका चयन नहीं हुआ? ऋतुराज लाइन में कहां से आ गए? उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि एक महीने के आराम के बाद भी शमी को आराम क्यों दिया गया? शमी ऐसे गेंदबाज हैं, जो जितनी बॉलिंग करेंगे उतना फिट और फॉर्म में रहेंगे। गौरतलब है कि अगले महीने भारत को वेस्टइंडीज का दौरा करना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। टी-20 टीम की घोषणा अभी नहीं की गई है। 12 जुलाई से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की विदाई हो गई है तो ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को पहली बार मौका मिला है। केएस भरत की जगह बरकरार है, वहीं चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव को टेस्ट टीम में चयनकर्ताओं ने जगह नहीं दी है। जिसके कारण चयनकर्ताओं को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

सरफराज खान को जगह नहीं देने की वजह से चयनकर्ताओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सरफराज का फर्स्ट क्लास औसत सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे बेहतर है। रणजी के पिछले तीन सीजन में उन्होंने 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं। इसके बाद भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ सरफराज ही नहीं इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ी भी हैं, जिनके साथ लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी भेदभाव हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियांक पांचाल, पृथ्वी शॉ और जलज सक्सेना जैसे कई नाम हैं। जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में सिर्फ एक सीजन नहीं बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि इनका दोष सिर्फ इतना है कि इनमें से अधिकांश आईपीएल नहीं खेलते हैं। इसीलिए इनके ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी गई है। टेस्ट क्रिकेट तो छोड़िए लगता है कि घरेलू क्रिकेट में भी टीम का चयन आईपीएल के आधार पर किया जाने लगा है। जिस तरह घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जलज सक्सेना को रणजी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद भी दिलीप ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया है। विशेषज्ञ इन सब चीजों से खुश नहीं हैं। कुछ ने तो यह तक कह दिया है कि अगर सिर्फ फिटनेस के आधार पर ही टीम चुननी है, प्रदर्शन के आधार पर नहीं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है।

● आशीष नेमा

युवा खिलाड़ी को क्यों नहीं मिली उपकप्तानी

वेस्टइंडीज दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे को फिर से रोहित शर्मा का डिप्टी बनाया गया है। रोहित की उम्र 36 साल हो चुकी है और रहाणे का भी क्रिकेटिंग कैरियर बहुत लंबा नहीं बचा है। ऐसे में तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के अनुसार, भारत के भविष्य का टेस्ट कप्तान तैयार करने का यह सही समय था। कैरेबियाई दौरे पर किसी युवा खिलाड़ी को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, ताकि वह खुद को बतौर लीडर तैयार कर सके। वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टेस्ट टीम में चार ओपनर्स को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी का आगाज करते नजर आएंगे। इसके साथ ही टीम में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को भी रखा गया है। हालांकि, टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी रहे मध्यक्रम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना सेलेक्टर्स ने जरूरी नहीं समझा। विराट कोहली और रहाणे के बाद मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज उनकी जगह लेने के काबिल नजर नहीं आता है। टेस्ट टीम में कई पुराने तेज गेंदबाजों की वापसी हुई है। साल 2021 में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले नवदीप सैनी को मौका दिया गया है, तो जयदेव उनादकट को भी टीम में शामिल किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद सिराज को छोड़कर पेस अटैक में ऐसा कोई भी गेंदबाज मौजूद नहीं है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हालिया फॉर्म बेहतर रही हो। मुकेश कुमार अभी बेहद युवा हैं, तो उनादकट और सैनी ने काफी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है।

> “अरशद वारसी उन एक्टर्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर अपने दम पर तय किया और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यूं तो अरशद बॉलीवुड में अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस हैं। हालांकि वे कई फिल्मों में काफी गंभीर भूमिका निभाकर सभी को हैरान भी कर चुके हैं।”

जया बच्चन के 1 ऑफर से बदल गया लिपस्टिक-बिंदी बेचने वाले का नसीब, फिर बना फेमस एक्टर

एक इंटरव्यू में अरशद ने अपने हिट से फ्लॉप होने के दौर को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता जीतेंद्र की उस खास सलाह को भी याद किया जो उन्होंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए दी थी।

एक्टर के अनुसार, जब उनकी डेब्यू फिल्म तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया और उनकी खूब तारीफें कीं। हालांकि बाद में जब वह लगातार फ्लॉप फिल्में देने लगे तो लोग उनसे दूरी बनाने लगे। लोगों को लगा कि कहीं अरशद उनसे काम न मांग लें। जबकि उन्होंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। अरशद के लिए यह बेहद खराब दौर था। हालांकि उन्होंने इस दौर को जीतेंद्र की सलाह को स्वीकार कर गुजार दिया।

जया बच्चन से पहली बार मिलने पर डर गए थे अरशद... इंटरव्यू के दौरान अरशद ने बताया कि उन्हें उनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने कैसे मिली। यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जया बच्चन ने उन्हें ऑफर की थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म को निर्देशक जॉय ऑगस्टीन ने निर्देशित किया था। अरशद वारसी के अनुसार, जब वह अपनी पहली फिल्म के लिए जया बच्चन से पहली बार मिले थे तो वह उनसे बेहद डर गए थे। जबकि निर्देशक इस फिल्म के लिए उनसे पहले ही बात कर चुके थे लेकिन प्रोडक्शन हाउस चाहता था कि वह अपनी तस्वीरें भेजें। उन्होंने बाद में ऐसा किया लेकिन वह अंदर से डर गए थे। इसके बाद अरशद को जया बच्चन का फोन आया, जिन्होंने उनसे ऑफिस में मिलने के लिए कहा और अरशद को अपनी पहली फिल्म मिल गई।

राजेश खन्ना ने छोड़ी फिल्म, चमक गई शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत, सुपरस्टार की हरकत से तनाव में आ गए डायरेक्टर

सुभाष घई ने साल 1979 में आई फिल्म कालीचरण से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी इस फिल्म को राजेश खन्ना के साथ बनना चाहते थे। जबकि फिल्म के डायरेक्टर इसे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ करना चाहते थे। हालांकि बाद में सुभाष घई एनएन सिप्पी की बात पर राजी हो गए। लेकिन जब प्रोड्यूसर राजेश खन्ना के पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे तो वहां उन्हें निराशा हाथ लगी।

राजेश खन्ना ने डेट्स न मिलने की वजह इस फिल्म को करने से मना कर दिया। एक्टर के मना करने के बाद एनएन सिप्पी ने सुभाष घई को इस फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ करने के लिए कह दिया और इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म कालीचरण के लीड एक्टर बनने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म कालीचरण की शूटिंग के दौरान सुभाष घई कई इमोशनल दौर से गुजर रहे थे। उनके मन में बार-बार फिल्म बंद करने की भावना उठी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को पूरा किया। बताया जाता है कि डायरेक्टर में मन ऐसा सवाल शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की वजह से आ रहा था। आपको याद दिला दें कि फिल्म कालीचरण के दौरान ही शत्रुघ्न सिन्हा-रीना रॉय की लव स्टोरी सुर्खियों में आई थी। दोनों के बीच की नजदीकियों से डायरेक्टर सुभाष घई को काफी परेशानी हुई थी।

पहली ही फिल्म से पर्दे पर छा गए थे कुमार गौरव, पिता की तरह नहीं कमा सके नाम, संजय दत्त से है खास रिश्ता

बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव फिल्मों में उनकी तरह नाम नहीं कमा सके। कुमार गौरव ने बॉलीवुड में आगाज तो बेहद शानदार किया था, लेकिन वह इस जबरदस्त आगाज को अंजाम तक न पहुंचा सके। कुमार गौरव ने फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट रही थी और इस फिल्म से ऑडियंस के बीच उनकी लवर बॉय इमेज बन गई थी। लव स्टोरी के बाद कुमार कई फिल्मों में लवर बॉय इमेज में नजर आए थे। उनकी फिल्म नाम भी काफी सफल रही थी, लेकिन फिर उनके सिर पर स्टारडम का खुमार कुछ यूं चढ़ा कि उन्होंने सबकुछ गंवा दिया।

जहां एक तरफ वह कई फिल्मों के ऑफर को ठुकराते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। लगातार कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाने का निर्णय कर लिया। जब पूरी तरह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ अपना बिजनेस शुरू किया। कुमार गौरव ने साल 1984 में संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी की थी। जीजा होने के साथ ही वह संजय दत्त के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। संजू बाबा के कैरियर को वापस ट्रैक पर लाने में कुमार गौरव का बड़ा हाथ रहा है।

> *खरीदारी करने का अपना एक उसूल है। मैं ज्यादा लोड नहीं लेता। रुपए के बजाय किलो में खरीदता हूं। हां, जब श्रीमती जी के साथ होता हूं तब अपने उसूल ताक पर रख देता हूं। दुकानदार से भाव-ताव वही कर लेती हैं। फिर घर आकर जोड़ती हैं कि उन्होंने आज कितने रुपए की बचत की। मोल-तोल करने की मेरी आदत कभी रही नहीं।*

बाजार से टमाटर खरीदने के खतरे

पिछले कई दिनों से मैं गांव में था। गर्मी की छुट्टियों में आम और जामुन के मजे ले रहा था। इस दौरान देश-दुनिया से बेखबर-सा रहा। दो दिन पहले ही राजधानी लौटा। आते ही श्रीमती जी ने घर-गृहस्थी हमारे हाथ में दे दी। थैला थमाकर बोलीं, जाओ पहले बाजार से सब्जी ले आओ। किचन में कुछ बचा नहीं है। मैंने बचने की असफल कोशिश की, लेकिन सब्जी तो घर बैठे ऑनलाइन भी मंगाई जा सकती है। हां, पर सब्जी देखकर लानी है। इस मौसम में सड़ी-गली सब्जी ज्यादा आती है। तुम्हारे गांव से लौटने का मैं इंतजार ही कर रही थी। श्रीमती जी के कठिन संकल्प के आगे मैंने समर्पण कर दिया। घर के बाहर मेरा कितना भी खास रुतबा हो, पर घर में विशुद्ध रूप से आम आदमी हूं। इसलिए चुपचाप झोला उठाकर चल दिया।

खरीदारी करने का अपना एक उसूल है। मैं ज्यादा लोड नहीं लेता। रुपए के बजाय किलो में खरीदता हूं। हां, जब श्रीमती जी के साथ होता हूं तब अपने उसूल ताक पर रख देता हूं। दुकानदार से भाव-ताव वही कर लेती हैं। फिर घर आकर जोड़ती हैं कि उन्होंने आज कितने रुपए की बचत की। मोल-तोल करने की मेरी आदत कभी रही नहीं। जिसे मैं अपनी उदारता समझता हूं, श्रीमती जी उसे बेवकूफी कहती हैं। बहरहाल मैं तपती गर्मी में सब्जी-मंडी तक सुरक्षित पहुंच गया। मैंने खरीदारी में दस मिनट लगाए होंगे। दो किलो आलू, आधा किलो भिंडी, पाव भर अदरक और दो किलो लाल टमाटर झोले में डलवा लिए। मोलभाव किए बिना सब्जीवाले से पैसे पूछकर भुगतान कर दिया। उसने भी हमारी उदारता का उधार नहीं रखा। थोड़ी-सी धनिया और हरी मिर्च मेरे झोले में छिड़क दी। मैंने उसे शुक्रिया कहा और झोला लेकर घर की ओर चल पड़ा।

अभी कुछ ही दूर चला था। मुझे लगा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे कुल तीन थे। मुझे गले में पड़ी अपनी चेन की चिंता होने लगी। मैंने अपनी चाल बढ़ाई पर पीछा करने वाले मुझसे तेज निकले। पल भर में तीनों बिल्कुल मेरे सामने थे। मैंने एक हाथ से अपना गला पकड़ा और दूसरे से झोला। वे मुझे छोड़कर झोले की ओर बढ़े। मैंने बचने का प्रयास किया। इस क्रम में झोला एक तरफ गिरा और मैं दूसरी तरफ। इसके बाद मैं अचेत हो गया। जब मुझे होश आया, सबसे पहले मेरा हाथ चेन पर गया। सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। तभी पास खड़े पड़ोसी पांडेय जी दिखे। बड़े चिंतित लग रहे थे। मैंने उन्हें इशारे से बताया कि सब ठीक है। वह बोल पड़े, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप बुरी तरह लुट चुके हैं। आपके झोले से टमाटर गायब हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। मैंने अचरज से उन्हें देखा। ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं? टमाटरों के लुटने से मैं बर्बाद कैसे हो गया! यह सोच ही रहा था कि पुलिस पहुंच गई। उसकी गिरफ्त में दो आदमी थे। तीसरा टमाटरों के साथ फरार था।

पुलिस ने एक लुटेरे से पूछा, तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? उसने बेखौफ उत्तर दिया, साहब, दुस्साहस हमने नहीं इन्होंने किया है। बाजार से दो किलो टमाटर खरीदते हम लोगों ने इन्हें देख लिया था। जिस वक्त टमाटर की ओर निहारना तक हराम है, यह आदमी उन्हें रसोई में ले जाने की हिमाकत कर रहा था। आप हमें नहीं इन्हें गिरफ्तार करें। अभी भी मैं पूरा माजरा समझ नहीं पाया था। मैंने पांडेय जी की ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह फट पड़े, अव्वल तो आपको गांव से आने की क्या जल्दी थी? आ ही गए थे तो बाजार क्यों गए थे? और अगर गए भी थे तो टमाटर क्यों लाए? तुम्हें पता भी है इसका भाव? मैंने गर्दन हिलाकर मना किया। फिर विनम्र होते हुए बोले, भई टमाटर इस समय सेंचुरी मार चुका है और अभी भी नाट-आउट है। आप जैसों की फिल्डिंग ऐसी ही रही तो कई रिकार्ड टूटेंगे। सरकार तक खतरे में पड़ सकती है। वह कैसे भला? मैंने मासूमियत का चोला ओढ़ लिया। टमाटर खाते हो, पर इसके साइड इफेक्ट नहीं पता। कुछ साल पहले प्याज ने सरकार बदल दी थी। ये तो टमाटर हैं। इनका दुष्प्रभाव और अधिक हो सकता है। ये चाहें तो पल भर में जमे-जमाए कवि को मंच में ही बिखेर दें। नेताओं की सफेदी लाल कर दें। पांडेय जी एक सांस में बोल गए।

अब मुझे अपनी भूल का अहसास हुआ। मेरे एक गलत फैसले से मेरी जान पर बन आई थी। सरकार तक गिर सकती थी। तभी श्रीमती जी का फोन आ गया, अजी कहां रह गए? बच्चे बड़ी देर से चटनी खाने का इंतजार कर रहे हैं! मैं फिर से बेहोश हो गया।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

शिवराज सरकार की अनुपम सौगात
सीखना-कमाना अब होगा साथ-साथ

- 46 क्षेत्रों के 800 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, इनमें विनिर्माण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेल्वे, आईटी, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी, विधि सेवाएं व अन्य सेवा क्षेत्र शामिल।
- 18 से 29 वर्ष के 10वीं-12वीं पास, आईटीआई, स्नातक व स्नातकोत्तर युवा पात्र।
- प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हजार रुपये तक स्टायपेंड।
- 15 जून से पंजीयन एवं 15 जुलाई से प्लेसमेंट।
- पंजीयन के लिए https://mmsky.mp.gov.in/ पोर्टल विजिट करें।

D16075/23

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2023

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

₹ 3000 तक बढ़ेगी राशि

21 वर्ष से ही मिलेगा लाभ

1 करोड़ 25 लाख बहनों को हर महीने ₹ 1000

संपर्क : ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800

D16075/23